राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

घाटी में सेना जनता से बनाएगी करीबी रिश्ते : रावत

>>5

वर्ष 3 अंक 65

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 14 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

एक नई **आजादी...**

एनएमसी अधिनियम, 2019 के तहत चिकित्सा शिक्षा तथा सुविधाओं के क्षेत्र में आएगा सबसे बड़ा सुधार पेज 3

जय हिंद

सीता बचा लाईं थीं 18 मासूमों की जिंदगी

भदोही : गैस रिसाव से धधकती स्कूल वैन में फंसे हुए थे बच्चे, जान की परवाह किए बिना लपटों के बीच वैन में घुसकर बच्चों को निकाल लाईं थीं सीता। खुद झुलस गईं पर साहस दिखा बचाई बच्चों की जान।

• पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

स्वतंत्रता के सारथी

अब तक 50 निर्धन बच्चों को बना चुके अफसर

जमशेदपुर : खनिज प्रदेश झारखंड के जमशेदपुर जिले में कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव हैं संजय कच्छप। कोल्हान प्रमंडल में दर्जन भर पुस्तकालय खोल निर्धन परिवारों के बच्चों का गढ़ रहे भविष्य। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

सिक्किम विस में एक ही दिन में शून्य से 10 पर पहुंची भाजपा

नई दिल्ली : सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 10 विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही दस विधायकों के शामिल होने के बाद सिक्किम में भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन गई है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ज्ञात हो, सिक्किम को छोड़ भाजपा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य दल के रूप में या क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में सेंगर पर आरोप तय

नई दिल्ली : उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के पिता की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में हुई। सत्र न्यायाधीश ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की अदालत से भी आरोप तय हो गए थे, लेकिन दिल्ली की अदालत ने हत्या और ऑर्म्स एक्ट के मामलों को मिलाते हुए आरोप तय किए हैं। पिछले सप्ताह दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

कैरेबियाई चुनौती

वनडे सीरीज वेस्टइंडीज *vs* भारत

शाम 7:00 बजे से

स्थान : पोर्ट ऑफ स्पेन

प्रसारण : सोनी नेटवर्क

कुरैशी ने किया स्वीकार-अकेला पड़ा पाकिस्तान

- विदेश मंत्री ने कहा-सुरक्षा परिषद में समर्थन जुटा मुश्किल, इस्लामिक देश भी नहीं दे रहे साथ
- अपने नागरिकों से कहा-किसी गलतफहमी में न रहें, वहां हमारे लिए कोई हार लेकर नहीं खड़ा है

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दुनियाभर में भारत के विरुद्ध विष वमन बेअसर रहने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने नागरिकों से पाक के अकेले पड़ने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से समर्थन जुटाना पाक के लिए मुश्किल है। इस्लामिक देश भी का साथ नहीं दे रहे।

गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गत सोमवार को कुरैशी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्यों का समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तानियों को नए सिरे से संघर्ष करना होगा। कुरैशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों से दो टूक कहा, 'आप किसी गलतफहमी में न रहें। वहां (यूएनएससी में) आपके लिए कोई हार लेकर नहीं खड़ा है। वहां कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा।' उन्होंने बिना किसी इस्लामिक देश का नाम लिए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर

शाह महमूद कुरैशी फाइल फोटो

उम्माह (इस्लामिक समुदाय) के सरपरस्त भी शायद आर्थिक हितों की खातिर पाक का साथ नहीं देंगे। भारत एक अरब लोगों का बाजार है। बहुत लोगों ने वहां (भारत में) निवेश किया है। हम अक्सर उम्माह व इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन उम्माह के सरपरस्तों ने भी वहां निवेश किया है।

ज्ञात हो, हाल ही में पाक ने भारत से सभी सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध तोड़ते हुए कहा था कि वह भारत के इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाएगा, लेकिन भारत पहले ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू और कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना उसका आंतरिक मामला है। साथ ही पाकिस्तान को भी वास्तविकता को स्वीकार करने की हिदायत दी थी। सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों में रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है।

कुरैशी का ताजा बयान जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर यूएनएससी के पहले सदस्य रूस का समर्थन आने के दो दिन बाद आया है। रूस ने कहा था कि जो भी बदलाव हुआ है वह भारतीय संविधान के दायरे में है। भारतीय गणतंत्र के संविधान के दायरे में ही जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अमेरिका भी कह चुका है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने लद्दाख के मुद्दे पर थोड़ा ऐतराज जरूर जताया लेकिन कुरैशी को साफ कह दिया कि वह भारत और पाक को पड़ोसी मित्रों के रूप में देखता है।

कश्मीर पर अपने पत्र के लिए अमेरिकी सांसद ने भारतीयों से मांगी माफी

वाशिंगटन : अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने भारतवंशियों से बातचीत किए बिना जम्मू-कश्मीर के हालात पर विदेश मंत्री माइक पोंपियो को पत्र लिखने के लिए माफी मांगी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत के फैसले के बाद डेमोक्रेट सांसद टॉम सूजी ने नौ अगस्त को पोंपियो को पत्र लिखा था, जिसमें भारत सरकार के फैसले से कश्मीर में सामाजिक अशांति बढ़ने की आशंका जताई थी। (पेज-5)

पाकिस्तानी युवक ने मलीहा लोधी को सुनाई खरी-खरी, कहा-आप सब चोर हैं

न्यूयॉर्क : पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। हाल में यहां एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाक की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी को एक पाक नागरिक ने ही खरी-खोटी सुनाई। लोधी को चोर बताते हुए कहा, वह पाक का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं। (पेज-11)

पाबंदियां हटीं और किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा : कोर्ट

बड़ा सवाल ▸ शीर्ष अदालत ने तत्काल प्रतिबंध हटाने से किया इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए लगाई गई पाबंदियों पर विपक्ष के चौतरफा हमलों से घिरी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंध हटाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के मामले में तत्काल आदेश देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 'स्थिति गंभीर और संवेदनशील है। रातों रात कुछ नहीं हो सकता। सरकार को स्थिति सामान्य करने के लिए कुछ वक्त मिलना चाहिए।'

जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, एमआर शाह और अजय रस्तोगी की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले तहसीन पूनावाला से कहा कि क्या वह भरोसा दिला सकते हैं कि पाबंदियां हटाने के बाद किसी की जान नहीं जाएगी। यहां स्थिति अलग है कोर्ट रोजाना के प्रशासन में दखल नहीं कर सकता। अच्छे बुरे हर पहलू से विचार करने की जरूरत है। एक फीसद भी चांस नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।

पूनावाला की वकील ने कहा, जम्मू-कश्मीर में स्थिति खराब है। लोग अपनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। सैनिक अपने घरों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। सैनिकों का मामला उठाने पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'आप सैनिकों की तरफ से शिकायत क्यों कर रही हैं। आपकी याचिका इसको लेकर नहीं है। सैनिकों को अनुशासन बनाए रखना है और अगर उन्हें कोई शिकायत होगी तो वो खुद आएंगे।' पूनावाला की वकील ने अनुच्छेद 370 के मामले को उठाने की कोशिश की तो पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि 'इस पर किसी तरह की टिप्पणी न करें।'

केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि 'सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थिति की रोजाना समीक्षा की जा रही है। एक वर्ग है जो स्थिति बिगाड़ने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है। ऐसे सबूत हैं कि अलगाववादी लोगों को भड़का सकते हैं। सीमापार से मिल रहे निर्देशों पर ऐसा हो रहा है।'

इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि हालात सुधरने में कितना समय लगेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2016 में जब आतंकी बुरहान वानी मारा गया था तब जम्मू-कश्मीर में हालात तीन महीने तक खराब रहे थे। उस समय 47 लोगों की जान चली गई थी। इस बार कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण हालात पर नियंत्रण कायम रखा गया है। इसी का नतीजा है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। उम्मीद है कि स्थितियां सामान्य होने में इस बार उतना वक्त नहीं लगेगा। हमें भरोसा है कि हालात जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। इस पर जजों की पीठ ने कहा कि सरकार को स्थिति सामान्य करने के लिए समय मिलना चाहिए। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पाबंदियों के बारे में जिलाधिकारी हालात को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जिलेवार हालात की समीक्षा की जा रही है।

अखंड भारत (विशेष) पेज>>5

'हम जीवन और स्वतंत्रता के बुनियादी मुद्दे पर याचिकाकर्ता के साथ हैं। लेकिन स्थिति गंभीर है। किसी को स्थिति का अंदाजा नहीं है। किसी को नहीं मालूम क्या हो जाए। एक फीसद भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता।

-अदालत की टिप्पणी

कोर्ट का सख्त रुख

- कहा, क्या याचिकाकर्ता भरोसा दिलाएंगे कि पाबंदी हटने के बाद किसी की जान नहीं जाएगी
- यहां स्थिति अलग है, अदालत रोजाना के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती
- अनुच्छेद 370 का मामला उठने पर कहा-इस पर टिप्पणी न करें

कश्मीर टाइम्स की संपादक ने की मांग पर जल्द सुनवाई की मांग

कश्मीर टाइम्स की संपादक ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंधों के कारण पत्रकारों की दिक्कतों का मुद्दा उठाया है और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। संपादक अनुराधा भसीन की वकील ने कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांगी। जस्टिस मिश्र की की पीठ ने वकील से कहा कि वह जल्द सुनवाई की मांग का मेमो कोर्ट रजिस्ट्री को दें कोर्ट उसे देखेगा।

याचिका पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की तरफ से दायर याचिका पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर इतनी बेकार और हल्की याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भी सवाल पूछा जब बताया गया कि ये समाजसेवी हैं तो कोर्ट का दूसरा सवाल था कि क्या हर मुद्दे पर ये याचिका दाखिल करते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की वकील ने कोर्ट से कहा कि वह मानती हैं कि जल्दी में याचिका उतनी अच्छी ड्राफ्ट नहीं हो पाई है उन्हें वक्त दिया जाए वह याचिका में संशोधन करेंगी। कोर्ट ने कहा कि संशोधन से भी कोई फायदा नहीं होगा। दो हफ्ते बाद हालात की समीक्षा पर वह कोई फैसला देगा।

आम्रपाली के घर खरीदारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दें नहीं तो भेज देंगे जेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने दी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को सख्त चेतावनी
- दोनों अथॉरिटी को परियोजना वार सूची तीन दिनों में उपलब्ध कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह आम्रपाली की विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को पूर्णता प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) दें। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोनों अथॉरिटी के अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें जेल भेज देंगे।

ये टिप्पणियां जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम्रपाली के घर खरीदारों के मामले में सुनवाई के दौरान कीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों अथॉरिटी को परियोजना वार सूची तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि जिन परियोजनाओं में लोग रह रहे हैं उनकी सूची दोनों अथॉरिटी को उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए अथॉरिटी से कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो वे परेशानी में फंस जाएंगे।

इससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अथॉरिटी ने कोर्ट के आदेश का पालन शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए स्पेशल सेल बनाया है। कुछ अधिकारी सिर्फ इसी काम में लगाए गए हैं। लेकिन उनके पास अभी परियोजना वार सूची नहीं है। अथॉरिटी की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन होगा।

घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोती ने जब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए पैसा अन्य स्रोतों से जुटाया जा सकता है। कोर्ट ने उनसे कहा कि वह घर खरीदारों के लिए कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ कागजों पर शेर नहीं है। ठोस कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने आम्रपाली के सीएमडी और अन्य निदेशकों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें निर्माण के लिए अभी 1.5 करोड़ रुपये दिया गया है। उन्हें निर्माण पूरा करने के लिए 7.59 करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वह इस बारे में अर्जी दाखिल करें और उसमें रोड मैप भी दें कि वे आगे कैसे काम पूरा करेंगे। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई पर विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत इस मामले को लेकर समूह के खिलाफ पहले ही काफी तीखे तेवर अपनाए हुए है।

उत्तर प्रदेश में अब खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- डीजीपी ने जारी किया आदेश, विशेष स्थिति पहले से लेनी होगी अनुमति

अलीगढ़ और मेरठ के बाद अब उप्र के सभी जिलों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब खास मौकों पर ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीजीपी ओपी सिंह ने सभी एडीजी जोन, आइजी/डीआइजी रेंज, एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे धार्मिक आयोजन न हों, जिससे लोगों को व्यवधान हो और यातायात प्रभावित हो। डीजीपी ने कहा कि सभी जिलों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश दिया गया है।

अलीगढ़ से हुई शुरुआत : अलीगढ़ में शुक्रवार के दिन सड़कों पर नमाज और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और आरती का नया चलन शुरू हो गया था। इससे जहां यातायात प्रभावित होता था वहीं, शांति व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा बना रहता था। नौ जून को अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में सड़क पर आरती होने से जाम लग गया था। इसके बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सड़क पर नमाज व आरती पर रोक लगा दी थी।

मेरठ में एक सप्ताह से सड़क पर नमाज बंद : मेरठ में भी गत दिनों सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कहीं-कहीं तो दूसरे समुदाय ने भी भजन-कीर्तन का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। टकराव और न बढ़े तथा धार्मिक आयोजनों की वजह से यातायात प्रभावित न हो, इसके मद्देनजर गत बुधवार को सभी थानों को निर्देश दिए गए थे कि जुमे की नमाज मस्जिद के भीतर ही पढ़ी जाए।

मुसलमान भी मानते हैं यह राम जन्मस्थान

नई दिल्ली : अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मुकदमा लड़ रहे रामलला विराजमान की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों ने भी माना है कि यह राम जन्मस्थान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बाबत दो मुस्लिमों के बयान का हवाला दिया गया। साथ ही कहा गया कि जन्मस्थान स्वयं में देवता है और देवता का बंटवारा नहीं हो सकता इसलिए राम जन्मभूमि में हिंदू-मुस्लिम दोनों का साझा कब्जा नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की ध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने मंगलवार को पांचवें दिन की सुनवाई के दौरान भगवान रामलला विराजमान की ओर से जन्मस्थान पर मालिकाना हक साबित करने के लिए दलीलें रखीं गईं। मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। (पेज-3)

मांग में कमी से ऑटोमोबाइल बिक्री में 19 साल की सबसे तेज गिरावट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बीते तीन माह में करीब 15,000 अस्थायी कर्मचारियों ने खोया रोजगार
- बिक्री में 18.71 फीसद की गिरावट, कंपनियों का उत्पादन 11 फीसद नीचे

मांग में कमी के चलते ऑटो सेक्टर में मंदी की गिरफ्त और भयावह होती जा रही है। इस वर्ष जुलाई में वाहनों की बिक्री में बीते 19 साल में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। ऑटो निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में कुल वाहनों की बिक्री में 18.71 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में छाई मंदी के चलते पिछले तीन महीने में 15,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में गिरावट का सिलसिला बीते नौ माह से चल रहा है। इस बीच ऑटो उद्योग के प्रतिनिधि सरकार से लगातार राहत पैकेज की गुहार लगा रहे हैं। स्थिति में सुधार के लिए उद्योग ने जीएसटी दर को भी 28 से घटाकर 18 फीसद पर लाने की मांग की है। सियाम ने मंगलवार को जुलाई 2019 के बिक्री आंकड़े जारी करते हुए भी इन मांगों को दोहराया। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा, 'बिक्री के ताजा आंकड़ों से स्पष्ट है कि उद्योग को राहत पैकेज की कितनी गहरी जरूरत है।'

सियाम के आंकड़ों के मुताबिक ऑटो सेक्टर के प्रत्येक वर्ग की बिक्री में गिरावट आई है। पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 18,25,148 यूनिट रही, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में इस वर्ग में 22,45,223 यूनिट वाहनों की बिक्री हुई थी। इससे पहले दिसंबर, 2000 में ऑटोमोबाइल उद्योग में 21.81 फीसद की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। बिक्री में गिरावट इतनी तेज है कि इस वर्ष जुलाई में कंपनियों के उत्पादन में 11 फीसद की कमी दर्ज की गई है। आगे भी स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हाल ही में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कुछ दिनों के लिए उत्पादन रोकने का फैसला किया है।

कारों और एसयूवी श्रेणी के वाहनों की बिक्री के मामले में भी गिरावट का स्तर बीते 19 साल में सबसे तेज रहा है। जुलाई में इस श्रेणी में 2,00,790 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई जो पिछले वर्ष जुलाई के आंकड़े (2,90,931) से करीब 31 फीसद कम है। पिछली बार इतनी तेज गिरावट दिसंबर 2000 में देखी गई थी जब वाहनों की बिक्री 35.22 फीसद गिरी थी।

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 16.82 फीसद की गिरावट पेज>>10

जगीं उम्मीदें

12-14 अक्टूबर को होगा निवेशकों का सम्मेलन, खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अंबानी सहित कई उद्योगपति जता चुके निवेश की इच्छा, कई उद्योगपति कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पैकेज की प्रतीक्षा

उद्योगों के लिए जन्नत बनेगा जम्मू-कश्मीर

रोहित जंडियाल, जम्मू

बेरोजगारी की मार झेल रहे जम्मू-कश्मीर के लिए आने वाले दिन रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़े औद्योगिक घराने यहां पर निवेश करने को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई उद्योगपतियों ने तो निवेश की घोषणा भी कर दी है और कई केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पैकेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य प्रशासन उद्योगपतियों को लुभाने के लिए जम्मू-कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर तक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।

अनुच्छेद 370 हटने के तुरंत बाद पंजाब के 'ट्राइडेंट' समूह ने राज्य के दस हजार परिवारों को रोजगार देने का वादा किया है। वहीं 'पालिसी बाजार' ने चार हजार रोजगार देने की बात की है। इसी तरह 'उदय कोटक', 'अमूल इंडिया' और हेलमेट बनाने वाली 'स्टीलबर्ड' कंपनी ने भी जम्मू-कश्मीर में निवेश करने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी ने एक दिन पहले ही कंपनी की एजीएम में राज्य में निवेश की इच्छा जताई है। कई अन्य समूह जो पहले भी जम्मू-कश्मीर में निवेश कर चुके हैं, अब व्यापार का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इनमें 'लेमन ट्री' समूह का गुलमर्ग और सोनमर्ग में होटल बनाने का प्रस्ताव है। इस ग्रुप के पहले से ही राज्य में तीन होटल हैं। इसके अलावा रेडिसन, डाबर, बर्जर पेंट, सन फार्मा, कैडिला भी यहां पर पहले से हैं। जम्मू चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान राकेश गुप्ता ने कहा कि राज्य में उद्योग आने से सबसे ज्यादा लाभ यहां के युवाओं को होगा।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होंगे रोड शो : इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि 12 से 14 अक्टूबर तक होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के प्रचार के लिए दुबई, लंदन, नीदरलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में रोड-शो किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्तर के रोड शो होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीनगर में 12 अक्टूबर को शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआसीसी) में होगा और समापन 14 अक्टूबर को जम्मू विश्वविद्यालय में। जम्मू-कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन सम्मेलन आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है और भारतीय उद्योग परिसंघ सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर है। 'अर्नेस्ट एंड यंग' व 'प्राइज वाटरहाउस कूपर्स' कंपनियां भी आयोजन में सहयोग करेंगी। चौधरी ने कहा कि सम्मलेन तीन महीने पहले से तय था। इसका अनुच्छेद 370 हटने से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या कहते हैं उद्योगपति : बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्प क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।'

आतंकवाद के कारण बंद हुए थे उद्योग : 1971 में घाटी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एचएमटी घड़ियां बनाने का प्लांट लगा था। करीब तीस साल पहले आतंकवाद शुरू होने के बाद आतंकियों ने एचएमटी के जनरल मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया था।

बेरोजगारी दर अधिक

राज्य में इस समय बेरोजगारी दर 5.1 फीसद है। रोजगार केंद्रों में करीब एक लाख युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, जबकि छह लाख से अधिक बेरोजगार हैं।

कथित गो-तस्कर पहलू खान मामले में आज आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान के चर्चित कथित गो-तस्कर पहलू खान की उन्मादी भीड़ की हिंसा में मौत के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। अलवर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 डॉ. सरिता स्वामी ने दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन मुकर्रर किया था।

ज्ञात हो, एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह जिले के जयसिंहपुर निवासी पहलू खान अपने दो बेटों इरशाद और आरिफ के साथ जयपुर से दो गाय खरीद कर ले जा रहे थे। शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने उसके वाहन को रुकवाकर मारपीट की थी। मारपीट में पहलू गंभीर रूप से घायल हो गये थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहलू को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इलाज के दौरान पहलू के बयान लिए थे। इस आधार पर केस दर्ज किया गया था।

दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस वे पर 12 किमी लंबा जाम

- हरियाणा के गुरुग्राम शहर में मंगलवार को हुई 55 एमएम बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया।
- जल जमाव से वाहनों की रफ्तार थम गई। दिल्ली-जयपुर हाईवे सहित काफी जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया।
- दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन में राजीव चौक से महिपालपुर तक करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया

15 अगस्त से महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मिल सकती है मुफ्त यात्रा की सुविधा। इसके कैबिनेट मसौदा को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई है। बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर सरकार को सालाना करीब 300 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर सकते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 अगस्त 2019

औद्योगिक क्षेत्रों में भी अब कर सकेंगे गैर औद्योगिक गतिविधियां

तोहफा ▸ दिल्ली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

तकनीक आधारित सभी गतिविधियों को चलाने की मिली अनुमति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में अब गैर औद्योगिक गतिविधियां भी की जा सकेंगी। वहां अस्पताल भी खोले जा सकेंगे, आइटी कार्यालय व गोदाम वगैरह भी। इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार शाम राजनिवास में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई। उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीक आधारित सभी गतिविधियों को चलाने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा भी बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

32 कॉलोनियों के इन सीटू डेवलपमेंट प्लान को मिली मंजूरी : सरकारी जमीन पर बसी 32 झुग्गी बस्तियों के इन सीटू डेवलपमेंट प्लान को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत डीडीए कठपुतली कॉलोनी की तर्ज पर 'जहां झुग्गी-वहां मकान' की तर्ज पर पुराने बाशिंदों को नया मकान देगा। पहले इन कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर बिल्डरों के साथ मिलकर वहां फ्लैट बनाए जाएंगे।

लीज नवीनीकरण का दिया अवसर : रिहायशी और मिश्रित भू उपयोग श्रेणी में 90 साल की लीज खत्म हो चुके संपत्ति धारकों को लीज नवीनीकरण का एक मौका दिया गया है। बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई कि जिन संपत्तियों की लीज का नवीनीकरण होना है, उनके मालिक अपने बकाया शुल्क का भुगतान कर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बकाया राशि का पूर्ण भुगतान 30 दिन के अंदर करना होगा।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के प्लॉटों का होगा ऑनलाइन आवंटन : डीडीए ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए आवासीय भूखंडों के निपटान के लिए ऑनलाइन नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कोई भी निजी डेवलपर अब डीडीए से इन प्लॉटों को ले सकता है। बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों में खाली पड़े प्लॉटों का आवंटन अब वृद्धाश्रम या अनाथालय खोलने के लिए भी किया जा सकेगा। इसके तहत खासकर कुतुब शैक्षणिक संस्थान क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा।

आवासीय योजना के बाद अब डीडीए 225 व्यावसायिक संपत्तियों की भी ऑनलाइन स्कीम लाने जा रहा है। इस आशय के प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई। ऐसी संपत्तियों में ज्यादातर दुकानें ही हैं। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर इन दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। ये संपत्तियां रोहिणी, नरेला, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जोन में स्थित हैं।

बदला जमीन का भू उपयोग : प्रदूषण की मार के चलते बंद हुए कोयला आधारित बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की 64.22 एकड़ जमीन का भू उपयोग बदल दिया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) अब वहां एक ईको पार्क तैयार करेगा। इसी तरह पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में सामुदायिक खेल परिसर तैयार किया जाएगा।

लैंड पूलिंग पॉलिसी को पांच जोनों एन, पी 2, के वन, एल और जे में बांटा गया है। पहले अगर किसी गांव की जमीन कई जोन में आ रही थी तो उसे अधिसूचित केवल एक ही जोन में किया जा रहा था। लेकिन, अब उस गांव की जमीन को हर उस जोन में शामिल कर लिया जाएगा, जहां-जहां वह आ रही है।

अभी तक 64 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही दो प्लॉटों को आपस में जोड़कर निर्माण कार्य किया जा सकता है। लेकिन, अब डीडीए ने इसे दो सौ वर्ग मीटर तक बढ़ाने दिया है।

हाई कोर्ट पहुंचा स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस लिखने का मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जारी की गई एडवाइजरी में हुई चूक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस लिखा गया है। इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की दक्षिण जिले की यूनिट ने स्वतंत्रता दिवस के चलते कुछ दिशानिर्देशों को लेकर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर गणतंत्र दिवस लिखा हुआ था। याचिका में कहा गया है कि यह दिल्ली पुलिस की भारी चूक है। इस बाबत उन्होंने कहा कि मानवीय चूक से यह जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी एडवाइजरी जारी करने से पहले उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं देते।

मेट्रो के सिर्फ चार स्टेशनों पर बदलेगी व्यवस्था : स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवा सामान्य तरीके से संचालित की जाएगी। इस दौरान केवल चार मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास प्रभावित रहेगा। वॉयलेट लाइन पर लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुछ चुनिंदा गेट से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वहीं मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग 14 अगस्त को सुबह छह बजे से 15 अगस्त को दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

एसपीजी ने संभाली लाल किले की सुरक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर लाल किला और आसपास की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। लाल किले के आंतरिक घेरे की सुरक्षा की कमान भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने मंगलवार से संभाल ली है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के कमांडो और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के साथ इसके तीन किलोमीटर के दायरे में करीब 25 हजार अर्ध सैनिक बल के जवान व कमांडो तैनात कर दिए गए हैं।

आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद सावधानी बरत रहीं हैं। यही वजह है कि लुटियन जोन इलाके से लेकर लाल किले तक जिस रूट से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री सहित अन्य वीवीआइपी लाल किला पहुंचेंगे। वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के इस क्षेत्र में 16 पराक्रम वाहनों की तैनाती की गई है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस 16 कमांडो किसी भी तरह के हमले को नाकाम करने में सक्षम हैं। सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार से ही इन वाहनों के साथ सुरक्षाकर्मियों ने अपनी पोजीशन ले ली है। इसमें से कुछ को इलाके में गश्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

यही नहीं दूर से दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए लाल किले व आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर दूरबीन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान के अलावा मचानों पर कमांडो दस्ते को मुस्तैद किया गया है। लाल किले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए वहां दो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके माध्यम से अधिकारी तमाम सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। उधर लाल किले व आसपास के पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। ताकि कंट्रोल रूम में बैठकर समारोह में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहां तैनात बम निरोधक दस्ते नियमित अंतराल पर जांच कर रहे हैं। वहीं लाल किले के अंदर और बाहर स्थित पेड़ों की सांकेतिक कोडिंग की गई है। साथ ही 3200 सुरक्षा प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं पर हैलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम आकाश मार्ग से जमीन पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगी।

न्यूज गैलरी

पानी के लिए सिंगापुर मॉडल अपनाएगी दिल्ली : केजरीवाल

दक्षिणी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मालवीय नगर में बताया कि नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि 2020 में 21 शहरों में पानी का जलस्तर बेहद ही कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने जल प्रबंधन के बेहतर तरीके व नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की तर्ज पर गंदे पानी को साफ किया जाएगा। जिस तरीके से सिंगापुर में गंदे पानी को ले जाकर दूसरे स्थान पर एकत्र किया जाता है और उसे साफ कर नदी में भेजकर पीने योग्य बनाया जाता है। इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला दिया है। इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली में पानी का जलस्तर है। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह योजना भी तैयार की है कि आने वाले दिनों में हर घर की छत पर बारिश के पानी को री-स्टोर किया जाएगा। दिल्ली के हर घर की छत पर री-स्टोर प्लांट लगाए जाएंगे। इस मौके पर पानी बचाने को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाने वाले जाने-माने कार्टूनिस्ट व पेंटर आबिद सुरती भी मौजूद रहे। (जासं)

एंटी रैबीज वैक्सीन की आपूर्ति करें सुनिश्चित : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। यह निर्देश देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत का यह आदेश तब आया जब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पीठ को बताया कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत वार्षिक आवश्यकता के हिसाब से 7 हजार से अधिक वैक्सीन के लिए आदेश जारी किया है। (जासं)

रक्षाबंधन पर बहनों के लिए एसी बसें भी रहेंगी मुफ्त

नई दिल्ली : रक्षाबंधन के त्योहार पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) महिलाओं के लिए फिर तोहफा लाई है। भाई-बहन के त्योहार राखी के पावन अवसर पर दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का फैसला किया है। 15 अगस्त को यानी गुरुवार के दिन महिलाएं सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक (डीटीसी) सामान्य और वातानुकूलित बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। डीटीसी के मुताबिक इस दिन महिलाओं को दिक्कत न हो इसलिए सुबह से ही ज्यादा से ज्यादा बसें सड़को पर उतारी जाएंगी। (राब्यू)

ऑटो वालों पर सरकार मेहरबान, तीन शुल्क माफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ फैसले से 90 हजार ऑटो चालकों को होगा फायदा

▸ जून में ऑटो के किराये में 18 फीसद की हुई थी वृद्धि

ऑटो फीस और जुर्माना

	मौजूदा	प्रस्तावित
फिटनेस फीस	600	0
फिटनेस जुर्माना रोजाना	1000 व 50 रुपये	300 व 20 रुपये
पंजीकरण व दोबारा पंजीकरण	1000	300
डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र	500	150
मालिकाना हक का स्थानांतरण	500	150

चुनाव तैयारी में जुटी दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार अब दिल्ली के ऑटो वालों पर मेहरबान हो गई है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटो वालों के लिए फिटनेस, जीपीएस और डिम्ट्स शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने ऑटो वालों को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को ऑटो की फिटनेस, जीपीएस और डिम्ट्स शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए। इसके अलावा ऑटो से संबंधित अन्य शुल्कों में भारी कटौती कर दी है। सरकार के इस कदम से 90 हजार ऑटो चालकों को फायदा पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी (आप) इससे पहले जून में ऑटो के किराये में 18 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी कर चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो शुल्क माफ हुए हैं उनसे सरकार को कुछ खास राजस्व नहीं मिल रहा था। उल्टे ये विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे।

अभी तक फिटनेस फीस के रूप में ऑटो चालकों को 600 रुपए देने पड़ते थे, जबकि जीपीएस व डिम्ट्स शुल्क के रूप में एक साल में 1420 रुपये तथा जीपीएस में सिम के लिए 584 रुपये देने होते थे। इसके अलावा पिछले तीन माह से आठ साल पुराने ऑटो से दो साल की इकट्ठा डिम्ट्स शुल्क लिया जाने लगा था। इससे ऑटो चालक नाराज थे। कैबिनेट ने इन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया है। अब परिवहन विभाग इन शुल्कों को वहन करेगा।

इसके अलावा अभी तक फिटनेस जुर्माना के लिए लेट फीस एक हजार रुपये थी इसे घटाकर 300 कर दिया है। लेट फीस के साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना लिया जाता था। इसकी जगह अब 20 रुपये प्रतिदिन वसूले जाएंगे। वहीं वाहन के पंजीकरण का शुल्क एक हजार रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र अब 500 रुपये की जगह 150 रुपये में जारी किया जाएगा। वहीं स्वामित्व हस्तांतरण 500 रुपये की जगह 150 रुपये में हो सकेगा। जुर्माना 500 रुपये की जगह 100 रुपये कर दिया गया है। वहीं हॉयर परचेज अतिरिक्त फीस को 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

दिल्ली कैबिनेट ने परमिट नवीनीकरण शुल्क को भी आधा कर दिया है। नवीनीकरण 1000 रुपये की जगह 500 रुपये में करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। हालांकि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए नियम 59 (1) (ए) में संशोधन की आवश्यकता होगी।

एक सितंबर 2019 से प्रभावी : सभी नए बदलाव एक सितंबर 2019 से प्रभावी होंगे। हालांकि दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक केवल परमिट के नवीनीकरण के लिए नया शुल्क 15 अक्टूबर के बाद लागू होगा। उधर, आम आदमी पार्टी ऑटो यूनियन के संतोष पांडेय व उपेंद्र सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की नजर पौने तीन लाख मतदाताओं पर है। दरअसल, दिल्ली में 90 हजार ऑटो पंजीकृत हैं। हर ऑटो चालक के घर के अगर तीन सदस्य जोड़ें तो करीब पौने तीन लाख मतदाता होते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऑटो चालकों ने खुला समर्थन दिया था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल की थीं। उस समय आलम यह था कि 2015 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई ऑटो चालक आप का सड़कों पर स्वेच्छा से प्रचार करते थे।

दिल्ली में पहाड़गंज के कुछ होटलों में ओयो ग्राहकों की नो एंट्री

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : दिल्ली में पहाड़गंज के कुछ होटलों में एप आधारित कंपनी ओयो के ग्राहकों को नो एंट्री है। बुकिंग के बाद भी होटल संचालक उन्हें कमरा देने से इन्कार कर रहे हैं। इलाके में जगह-जगह 'नो मोर ओयो' के बोर्ड टंगे हैं, जिनमें लिखा है कि ओयो बुकिंग पहाड़गंज में स्वीकार नहीं है। इससे ग्राहक परेशान हैं। एक होटल के संचालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इसके पीछे कमरों का किराया काफी कम होना, छोटी-छोटी बातों पर पैसे काटना और करार की शर्तों को लेकर आने वाली दिक्कतें हैं। एक होटल संचालक के मुताबिक पहले जिस कमरे का किराया औसतन 1200 रुपये प्रतिदिन का था, उसे यह कंपनी 300 रुपये पर देने को कह रही है। बुकिंग का पैसा कई महीने की देरी से दिया जा रहा है। होटल संचालक इससे घाटे में जाने लगे हैं। इसलिए बुकिंग से इन्कार किया जा रहा है।

पहले कमरे का किराया अधिक था, लेकिन बुकिंग कम थी। ओयो के कारण किसी-किसी होटल के कमरों की बुकिंग 100 फीसद तक है। कंपनी की प्राथमिकता में ग्राहक पहले हैं। इसलिए उनकी शिकायत पर होटलों पर कार्रवाई होती है। कुछ लोग विरोध में है, लेकिन उनकी संख्या कम है। उनकी शंकाओं को भी दूर करने का प्रयास हो रहा है। –प्रवक्ता, ओयो

स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल समारोह के दौरान ऐतिहासिक लाल किला प्राचीर से कड़ी निगरानी करते सुरक्षाकर्मी। ध्रुव कुमार

पुरानी दिल्ली-शाहदरा के बीच बंद रहेंगी ट्रेनें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लाल किला में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखकर 15 अगस्त को पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशन के बीच सुबह पौने सात बजे से साढ़े आठ बजे तक रेल परिचालन बंद रहेगा। इस कारण गाजियाबाद-नई दिल्ली ईएमयू (64437) और पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू (64402) रद कर दी गई है। कई ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। समारोह के दौरान कोई भी ट्रेन तिलक ब्रिज रेलवे पुल और भैरो पुल पर खड़ी नहीं होगी।

15 अगस्त को परिवर्तित समय से चलने वाली ट्रेनें : शामली-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54058) तड़के सवा तीन बजे के स्थान पर सुबह साढ़े चार बजे प्रस्थान करेगी। पुरानी दिल्ली से सुबह 06.35 बजे रवाना होने वाली पुरानी दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस (15484) सुबह साढ़े आठ बजे चलेगी। जबकि, पुरानी दिल्ली-कोटद्वार गढ़वाल एक्सप्रेस (14044) सुबह साढ़े सात बजे के स्थान पर पौने नौ बजे पुरानी दिल्ली से रवाना होगी। कालका-हावड़ा मेल और लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस मेल समारोह समाप्त होने के बाद पुरानी दिल्ली से रवाना होगी।

आरएफआइडी पर ईपीसीए सख्त, तीन राज्यों की पुलिस को दिए सहयोग करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के 13 टोल गेटों पर लग चुकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआइडी) तकनीक के अनुपालन को लेकर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सख्त रूख अपना लिया है। इसी कड़ी में ईपीसीए ने तीन राज्यों की पुलिस से इसे बेहतर ढंग से लागू करने में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल और सदस्य सुनीता नारायण ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सहित दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस से कहा गया कि अगर उनकी ओर से आरएफआइडी के क्रियान्वयन में सहयोग किया जाएगा तो इससे दिल्ली में ट्रकों के जरिये फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के अलावा अपराध रोकने व यातायात जाम को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। पुलिस को जिस नंबर के ट्रक की किसी दुर्घटना अथवा अन्य आपराधिक मामले की तलाश होगी, उसे टोल पर पकड़ लिया जाएगा।

जागरण से बातचीत में भूरेलाल ने बताया कि पुलिस अधिकारियों की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 20 मोबाइल टीमें भी टोल गेटों पर तैनाती के लिए रवाना कर दी गई हैं। यह टीमें वहां मौजूद ट्रकों और उनके ड्राइवरों की फोटो खींचकर उनके टैग तैयार करने में मदद करेंगी। इस दिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी अनुबंध किया गया है। भूरेलाल के मुताबिक सप्ताह भर बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर नगर निगम की ओर से कर लगाया जाता है। लेकिन, इसकी वसूली के चलते अक्सर यातायात जाम की स्थिति बन जाती है। इसी को दूर करने के लिए 13 प्रमुख टोल- किलोकरी, गुरुग्राम, कापसहेड़ा, बदरपुर, शाहदरा, डीएनडी, टीकरी, कुंडली, एनएच 24 और घिटोरनी पर कर बैरियर पर आरएफआइडी सिस्टम लगाया गया है। बदरपुर और शाहदरा में दो-दो जगह लगाया गया है।

बाइक बोट कंपनी का सीईओ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा : दो लाख से अधिक लोगों से अरबों की धोखाधड़ी करने वाली फ्रॉड कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (बाइक बोट) के कथित सीईओ तरुण शर्मा को नोएडा आर्थिक अपराध शाखा की एसआइटी (स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम) ने मंगलवार को बरौला टी प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित विकास नगर नई दिल्ली का रहने वाला है। वह कंपनी में 80 हजार रुपये महीने पर कार्य करता था। वर्ष 2018 में बाइक बोट (जीआइपीएल) कंपनी में सीईओ के पद पर वह नियुक्त था। पुणे के एक कॉलेज से एमबीए पास तरुण का कंपनी में मुख्य कार्य बाइक ऑपरेशन का था। उसके पास ड्राइवरों की नियुक्ति करना, कंपनी का एप बनवाना, बाइकों का ऑनलाइन संचालन कराने के अलावा कस्टमर केयर में चेक कंप्लेन संबंधित कार्य था। मीडिया सेल के अनुसार तरुण कंपनी में सीईओ के रूप में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था। कंपनी की तरफ से कार्य संचालन के लिए उसे ब्रेजा कार मिली हुई थी। बाइक बोट कंपनी में काम करने से पूर्व उसने आइटी जैक्स ग्लोबल कंपनी बनाई थी, जो बाद में बंद हो गई थी। इससे पहले वह कई नामी कंपनियों में उच्च पद के रूप में काम कर चुका है।

बदला मौसम, बरसे बदरा सप्ताह भर रहेगी यही फिजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया

कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार को मौसम ने फिर करवट ले ली। दोपहर बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बदरा बरसे। कहीं यह बारिश हल्की रही तो कहीं झमाझम हुई। इससे मौसम का मिजाज भी बदला और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश का यह दौर अभी कई दिनों तक जारी रहेगा। अगले दो दिनों के दौरान कुछ में तेज बारिश भी हो सकती है।

मंगलवार को सुबह के समय हालांकि मौसम साफ था। दोपहर तक सूरज भी निकला रहा और तेज धूप भी खिली रही। इसके चलते लोगों को खासी उमस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आने लगा। दिल्ली में ज्यादातर जगहों घने बादल छा गए। इसी दौरान कहीं अच्छी बारिश हुई तो कहीं हल्की। मौसम विभाग के मुताबिक लोधी रोड में सर्वाधिक 26 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। सफदरजंग में 12.1 मिलीमीटर, पालम में 25.4 मिलीमीटर, रिज में 15.5 मिलीमीटर, आयानगर में 2.1 मिलीमीटर, नजफगढ़ में दो और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में छह मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई।

दूसरी तरफ मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से दो डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। हवा में नमी का स्तर 62 से 92 फीसद दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह भर तक बादल और बारिश का यह दौर दिल्ली में जारी रहेगा। बुधवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बरसात होने की संभावना है। शुक्रवार को हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। शनिवार को फिर घने बादल छाने और झमाझम बारिश के आसार हैं।

दिल्ली में बीच बीच में रूक रूककर हो रही बारिश से हवा भी फिलहाल एकदम बढ़िया चल रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर इंडेक्स के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स महज 69 रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है।

एसिड हमले की पीड़िता पर अस्पताल में हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती एसिड हमले की पीड़ित युवती पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। नजफगढ़ की रहने वाली युवती को 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

शिकायत के मुताबिक घटना गत 26 जुलाई की है जब पीड़िता अस्पताल के वार्ड में थी। तभी एक शख्स वार्ड में दाखिल हुआ और उनका मुंह दबा दिया। इसकी जानकारी देने पर सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वह भागने में सफल हो गया था। पीड़िता के अनुसार उनके साथ छेड़छाड़ करने वालों ने उस हमलावर को भेजा था।

नई दिल्ली जिले के डीसीपी ईश सिंघल ने बताया कि घटना की शिकायत के बाद नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। जांच में पीड़िता पर किसी तरह के हमले का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस मामले में शामिल एक आरोपित मानसिक बीमारी का मरीज है और उसका उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। फिलहाल उसे इलाज के लिए इबहास में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पीड़िता ने वर्ष 2014 में पड़ोस रहने वाले चार युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने ही उसे जबरन तेजाब पिलाया था।

पहल

स्वतंत्रता दिवस पर होगा उद्घाटन, आइएनएस कोलकाता के इस मॉडल को नौसेना ने उपहार के तौर पर दिया है

जामिया में स्थापित होगा युद्धपोत का मॉडल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जामिया मिलिया इस्लामिया में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आइएनएस कोलकाता के एक मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। नौसेना ने इस युद्धपोत के मॉडल को जामिया को उपहार के के तौर पर दिया है। जामिया के साथ भारतीय नौसेना की कई तरह की साझेदारी है। यह मॉडल 12 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। यह जामिया के सेंटर फॉर इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाहर स्थापित किया जाएगा। इससे पहले मिग 29 का मॉडल इंजीनियरिंग फैकल्टी में स्थापित किया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से भेंट दिया गया यह मॉडल 12 लाख रुपये की कीमत का है और इसे स्टील से तैयार किया गया है। 15 अगस्त को जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर इसका उद्घाटन करेंगी। वहीं इस मॉडल को लेकर जामिया के छात्रों में भी काफी उत्साह है। छात्रों का मानना है कि उन्हें इससे भारतीय नौसेना की गाथा को जानने का भी अवसर मिलेगा और समय-समय पर इस मॉडल को देखकर गर्व महसूस करते रहेंगे।

जामिया मिलिया इस्लामिया को नौसेना की ओर से मिले आइएनएस कोलकाता युद्धपोत के मॉडल का 15 अगस्त को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर इसका उद्घाटन करेंगी। सौजन्य : जामिया

प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि इस मॉडल को स्थापित करने का मकसद छात्रों को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह मॉडल छात्रों में गर्व की भावना पैदा करेगा।

जामिया में सरकारी अधिकारियों के साथ कश्मीरी छात्रों का लंच हुआ रद

जासं, नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बुधवार को सरकारी अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के कश्मीरी छात्रों का होने वाला लंच का कार्यक्रम रद हो गया है। जम्मू-कश्मीर के उप सूचना निदेशक की तरफ से इसका आयोजन किया जाना था। विवि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस संबंध में उसे जम्मू-कश्मीर के लायजन ऑफिसर की तरफ से जानकारी दी गई है। बकरीद के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से राज्य के लायजन ऑफिसर को दूसरे शहरों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के लिए एक-एक लाख रुपये आवंटित किए गए थे। माना जा रहा है कि इसी के तहत जामिया में कश्मीरी छात्रों के साथ लंच का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिसे छात्रों ने अस्वीकार कर दिया है।

कश्मीरी छात्रों ने जताया विरोध : कश्मीरी छात्रों ने इस मामले में कहा कि उन्हें जामिया के अधिकारियों से जानकारी मिली थी कि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में जम्मू-कश्मीर सरकार के संपर्क अधिकारी के साथ बुधवार दोपहर लंच का आयोजन होना है। न्याय हित को देखते हुए हमने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

स्कूल में पांच साल की बच्ची से सफाईकर्मी ने किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

ग्रेटर कैलाश-2 स्थित एक निजी स्कूल के सफाईकर्मी ने पांच साल की बच्ची को बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सफाईकर्मी चार दिन तक लगातार बच्ची को डरा-धमकाकर शिकार बनाता रहा और स्कूल प्रबंधन के साथ ही सुरक्षाकर्मियों को भनक तक नहीं लगी। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तब घटना का पर्दाफाश हुआ।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक निजी कंपनी में कार्य करने वाले दक्षिण दिल्ली की एक कॉलोनी निवासी युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि उनकी पांच वर्षीय बच्ची ग्रेटर कैलाश-2 के थाना सीआर पार्क क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है। आरोप है कि सात अगस्त को बच्ची स्कूल से घर गई तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। दवा देने पर भी बच्ची को आराम नहीं मिला तो परिजन उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि स्कूल के सफाई वाले अंकल ने बाथरूम में उसके साथ गंदा काम किया है। बच्ची ने यह भी बताया कि वह कई दिनों से बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गंदा काम कर रहे हैं। डीसीपी साउथ विजय कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपित 45 वर्षीय सफाईकर्मी पिच्चूमुत्तू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित अंबेडकर नगर का रहने वाला है।

स्कूल के बाथरूम में बच्ची से दुष्कर्म की घटना की जानकारी अभिभावकों को मिली तो वह स्कूल पहुंच गए। बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई।

100 कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करेंगे भारत और चीन लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए। जिन क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की जाएंगी उनमें संग्रहालय प्रबंधन, शिक्षा, थिंक टैंक फोरम, फिल्म एवं प्रसारण क्षेत्र में सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपित रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रतुल की याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले निचली अदालत ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकरा दी थी। बता दें रतुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। मंगलवार को रतुल की तरफ से अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका पेश की। रतुल की एक याचिका न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका को गौर की पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। निचली अदालत ने सात अगस्त को रतुल की अग्रिम जमानत की मांग ठुकरा दी थी और 9 अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। रतुल ने अग्रिम जमानत पर फैसला लेने से पहले अन्य सभी आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने की मांग हाई कोर्ट से की थी, जो खारिज हो चुकी। रतुल हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वह नीता और दीपक पुरी के बेटे हैं। दीपक पुरी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया फर्म मोजर बेयर के सीएमडी हैं।

सिक्किम में शून्य से 10 पर पहुंची भाजपा

बड़ा सियासी उलटफेर ▶ पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की पार्टी के दस विधायक भाजपा में शामिल

विधायक बोले, मोदी सरकार की 'लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट' नीति से प्रभावित हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर-पूर्व में भाजपा और राजग के प्रभाव से छूटे एकमात्र राज्य सिक्किम में भी भाजपा का दबदबा स्थापित हो गया है। एक झटके में प्रदेश विधानसभा की 32 सीटों में भाजपा की संख्या शून्य से बढ़कर 10 हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 13 में से 10 विधायकों ने मंगलवार को भाजपा के साथ पार्टी का विलय कर दिया। इन दस विधायकों के शामिल होने के बाद सिक्किम में भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन गई है।

मंगलवार को एसडीएफ के 10 विधायकों ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर महासचिव राम माधव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। विधायकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की 'लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट' नीति से वे प्रभावित हैं। इससे राज्य का विकास होगा। प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर वे भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। बता दें कि त्रिपुरा में भी भाजपा की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी जब तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी में शामिल हुए थे। धीरे-धीरे भाजपा का प्रभाव बढ़ता गया। सिक्किम से सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रभाव है। दस विधायकों के आने के बाद भाजपा की कोशिश होगी कि जमीनी स्तर पर उसकी जड़ें मजबूत हों। अगर ऐसा होता है तो देर-सबेर सिक्किम में भी भाजपा मजबूत ताकत होगी।

सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 10 विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के महासचिव राम माधव भी मौजूद रहे। प्रेट्र

चामलिंग के नाम दर्ज है सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड : पवन कुमार चामलिंग ने 1993 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) की स्थापना की थी। वह ढाई दशक (1994-2019) तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वह सत्ता में वापसी नहीं कर सके। चामलिंग के नाम देश में किसी राज्य का सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। पहले एसडीएफ भाजपा की सहयोगी थी, लेकिन अब सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट भाजपा के नेतृत्व वाले नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस का हिस्सा है।

सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की धड़कनें तेज : पिछले विधानसभा चुनाव में 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के खाते में 17 सीटें आई थीं जबकि एसडीएफ को 15 सीटें मिली थीं। चूंकि इसके दो विधायक दो-दो सीटों से विजयी हुए थे, इसलिए उन्हें एक-एक सीट से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह पार्टी के विधायकों की संख्या 13 रह गई। इन 13 विधायकों में से 10 मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। राज्य में दो सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होना है। अगर भाजपा ये दोनों सीटें जीत जाती है तो सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल में सिर्फ पांच सीटों का अंतर रह जाएगा।

एसडीएफ ने बताया जटिल मुद्दा : पार्टी के 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बारे में एसडीएफ के वरिष्ठ नेता पीडी राय और केटी ग्यालत्सेन ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह जटिल मुद्दा है और बिना यह पता किए कि ऐसा किन वजहों से हुआ, इस कदम का न तो हम आलोचना करते हैं और न ही स्वागत करते हैं। वहीं इस मुद्दे पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने कुछ भी कहने से इन्कार किया है।

हर भारतीय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा है : मोदी

साक्षात्कार

▶ प्रधानमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना देश का मामला है, राजनीति का नहीं

▶ दशकों से राज्य के लोगों को बेड़ियों में कैद रखा गया

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

नई दिल्ली, आइएएनएस : अनुच्छेद 370 को समाप्त समेत कई बड़े फैसले लेने के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी में 75 दिन पूरे कर लिए हैं। कश्मीर समेत तमाम अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में खुलकर अपनी राय रखी। वह कहते हैं कि सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही अभूतपूर्व रफ्तार से काम किया है और इस दौरान स्पष्ट नीति और सही दिशा का प्रदर्शन किया है। वह अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहते हैं, बच्चों की सुरक्षा से लेकर चंद्रयान-2 अभियान तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक की कुप्रथा से आजादी दिलाने तक, कश्मीर से लेकर किसान कल्याण तक सरकार ने दिखाया है कि एक मजबूत शासन क्या कर सकता है।

मोदी से जब पूछा गया कि अनुच्छेद 370 को लेकर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया और कैसे आप मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े होंगे, उन्होंने जवाब दिया-आप कृपया इस फैसले का विरोध करने वाले लोगों की सूची देखिए। वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके अपने हित हैं, जो राजनीतिक विरासत वाले हैं, जो आतंकियों के हमदर्द हैं और कुछ विपक्षी मित्र भी। भारत के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है-भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। यह देश का सवाल है, राजनीति का नहीं। लोग समझ रहे हैं कि आज वे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो देश के लिए जरूरी हैं और जिन्हें पहले लिए जाने से बचा जाता था। जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास से वंचित रखा गया था। आर्थिक अवसर नहीं बढ़ सके थे। आज विकास को एक अवसर देने की बारी है।

आज बीपीओ से लेकर स्टार्ट-अप तक, खाद्य प्रसंस्करण से लेकर पर्यटन तक कई उद्योग निवेश के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं और इससे निश्चित ही स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अनुच्छेद 370 और 35 ए एक बेड़ी की तरह थे, जिन्होंने लोगों को बांध रखा था।

मोदी 2.0 की और अधिक व्याख्या करते हुए पीएम ने कहा, उनकी सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय बनाकर पेयजल की उपलब्धता और जल संरक्षण के लिए बड़ी पहल की है। क्या दूसरी बार बड़े जनादेश के साथ जीतने के बाद अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा-हां, एक हद तक। एक तरह से यह पहले कार्यकाल में किए गए कार्यों का प्रतिफल भी है। हम इस बार पहले 75 दिनों में इतना अधिक काम इसीलिए कर सके हैं, क्योंकि पहले कार्यकाल में इस सबकी बुनियाद बना दी गई थी। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र कामकाज के लिहाज से रिकार्ड रहा है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हमें खुशी है कि हम तमाम बड़ी योजनाएं शुरू कर सके, जैसे कि किसानों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम, मेडिकल क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत, इन्सालवेंसी और बैंकरप्सी कोड में अहम संशोधन, श्रम सुधारों की शुरुआत आदि। यह सूची लंबी है। मूल बात यह है कि जब इरादे सही होते हैं और उद्देश्य की स्पष्टता होती है और लोगों का समर्थन होता है तो उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रह जाती।

जब उनसे पूछा गया कि जो बदलाव किए गए हैं उनके पीछे पूरा विचार-विमर्श किया गया तो पीएम ने कहा, जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी तो मेडिकल शिक्षा के ढांचे को लेकर तमाम चिंताएं जताई गई थीं, कोर्ट ने भी निगरानी करने वाली संस्थाओं को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया था। एक संसदीय समिति ने पूरे सिस्टम का गहन अध्ययन किया और कुप्रबंधन की समस्या को समझा। पहले की सरकारों ने भी इस क्षेत्र में सुधारों की पहल की थी, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सकीं। हमने नेशनल मेडिकल कमीशन के रूप में संस्था की शुरुआत की है, जो तस्वीर बदलेगी।

डायनमिक रोशनी से जगमगाया संसद भवन

संसद भवन की भव्यता मंगलवार को एलईडी की विशेष लाइटिंग सिस्टम से शिखर पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंग बदलने वाली इस लाइटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। भवन के फलक पर लगी 875 एलईडी पल-पल रंग बदलती रहती हैं। ये लाइटें अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली की खपत करती हैं। ध्रुव कुमार

कर्नाटक के अयोग्य करार विधायकों ने कोर्ट से की शीघ्र सुनवाई की मांग

▶ विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती

▶ 29 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जदएस के बागी विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करे। कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की मांग संबंधी मेमो रजिस्ट्रार को सौंपने का निर्देश दिया है। राज्य के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुए इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने पीठ को बताया कि इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।

सदन में शक्ति परीक्षण में सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारखिहोली और महेश कुमाथल्ली और एक निर्दलीय नेता आर शंकर को 25 जुलाई को अयोग्य ठहराया गया था। इन विधायकों ने 29 जुलाई को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने अन्य 14 बागी विधायकों को 28 जुलाई को अयोग्य ठहराया था।

मुसलमान भी मानते हैं यह राम जन्मस्थान

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या की पुकार पांचवें दिन की सुनवाई : रामलला की ओर से रखी गईं दलीलें

अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मुकदमा लड़ रहे रामलला विराजमान की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों ने भी माना है कि यह राम जन्मस्थान है। हाईकोर्ट में इस बाबत दो मुस्लिमों के बयान का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने मंगलवार को पांचवें दिन की सुनवाई के दौरान भगवान रामलला विराजमान की ओर से जन्मस्थान पर मालिकाना हक साबित करने के लिए दलीलें रखीं गईं। मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

पांचवें दिन की बहस की शुरुआत वरिष्ठ वकील के.परासरन ने की उन्होंने वैसे संक्षिप्त बहस कर अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करना सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट क्षेत्राधिकार में आता है। उनके बाद रामलला की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस करनी शुरू की। वैद्यनाथन ने हाईकोर्ट के फैसले, वहां पेश किये गए सुबूतों और गवाहों की जिरह का हवाला देते हुए जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार और आस्था साबित करने की कोशिश की। उन्होंने तुलसीदास की रामचरित मानस का हवाला देते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान विष्णु दशरथ की रानी कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बात के सुबूत हैं कि हिंदू अयोध्या में इसे भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं और यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी माना है कि यह राम जन्मस्थान है। वैद्यनाथन ने हाईकोर्ट में दर्ज मुहम्मद हाशिम के बयान का हवाला दिया जिसमें उसने कहा था कि यह सत्य है कि हिंदू यहां परिक्रमा करते हैं। पंचकोसी परिक्रमा होती है। वैद्यनाथन ने कहा कि मुहम्मद हाशिम जो करीब 72 वर्ष के हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे में एक याचिकाकर्ता भी हैं। हाईकोर्ट में हाशिम का यह बयान गवाह के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा दूसरे गवाह के तौर पर हाजी महमूद का बयान दर्ज है जिसमें उसने कहा है कि यह सच है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है। यहां पंचकोसी परिक्रमा होती है। हिंदू यहां पूजा दर्शन के लिये आते हैं। हिंदुओं का विश्वास है कि यह राम जन्मस्थान है। वैद्यनाथन ने अयोध्या के ही रहने वाले एक अन्य मुस्लिम की गवाही का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू यहां आते थे। यहां मेला लगता था। वैद्यनाथन ने हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं का विश्वास है कि यह स्थान राम जन्मस्थान है। दूसरे पक्ष ने इस दलील को नकारा भी नहीं है। वैद्यनाथन ने कहा हालांकि जन्मस्थान की निश्चित जगह को लेकर अलग-अलग मत जरूर हैं। उन्होंने विभिन्न यात्रियों के वृतांत का भी जिक्र किया जिसमें अयोध्या में राम जन्मस्थान होने की बात कही गई है।

जन्मस्थान स्वयं देवता है और देवता का बंटवारा नहीं हो सकता : राम जन्मभूमि पर हिंदू मुसलमानों का साझा कब्जा होने को लेकर कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल पर वैद्यनाथन ने कहा कि जन्मस्थान स्वयं में देवता है। उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता और देवता का बंटवारा नहीं हो सकता। बिना बंटवारे के किसी चीज पर साझा कब्जा कैसे हो सकता है। उन्होंने यह जवाब तब दिया जब कोर्ट ने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का जन्मभूमि पर साझा कब्जा है तो फिर वह अपने अकेले हक का दावा कैसे कर सकते हैं। वैद्यनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में विभिन्न न्यायाधीशों की विभिन्न राय है। हाईकोर्ट ने अलग-अलग जगह अलग-अलग बात कही है। हाईकोर्ट ने एक जगह कहा है कि जन्मस्थान स्वयं में देवता है। दूसरी जगह कहा है कि जन्मस्थान के मालिक भगवान हैं और एक जगह कहा है कि यहां हिंदू मस्लिम का साझा कब्जा था। उन्होंनें कहा कि अगर हाईकोर्ट की यह बात सही मानी जाए कि जन्मस्थान स्वयं मे देवता है तो फिर उस पर साझा कब्जा नहीं हो सकता। अगर एक बार जन्मस्थान स्वयं में देवता है तो वह हमेशा देवता रहेगा अगर वहां मस्जिद बन भी जाती है तो उससे उस स्थान और देवता की प्रकृति खत्म नहीं होती। वह मंदिर ही रहेगा। मंदिर के लिए मूर्ति होना जरूरी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दी नहीं, पक्षकार अपना समय लें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि उसे इस मामले की सुनवाई में कोई जल्दी नहीं है। पक्षकार अपने हिसाब से समय लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। कोर्ट ने यह बात तब कही जब रामलला की ओर से हो रही बहस के दौरान बीच में उठकर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि कहा कि ये साक्ष्य नहीं पेश कर रहे हैं। पूरा प्रकरण नहीं पेश करते बल्कि टुकड़ों में बता रहें हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह उनका बहस करने का तरीका है जब आपका नंबर आए तब आप साक्ष्य दीजिएगा कोर्ट आपको सुनेगा। धवन ने कहा कि वह ऐसी उम्मीद करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने धवन के तरीके पर एतराज जताते हुए कहा कि ऐसा कहने का क्या मतलब है। आप पहले दिन से ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के हस्तक्षेप के बाद मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि उन्हें मामला सुनने की कोई जल्दी नहीं है पक्षकार अपना समय ले सकते हैं, लेकिन वे आगे से सुनवाई में कोई दखलंदाजी नहीं चाहते।

वहां पहले मंदिर था : वैद्यनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट के दो जजों ने माना है कि वहां पहले मंदिर था, जिसे तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी। तीसरे जज एसयू खान ने कहा है कि वहां मंदिर के अवशेष थे जिन पर मस्जिद बनाई गई थी। इसका मतलब भी यही निकलता है कि वहां पहले मंदिर था। जन्मस्थान पर हिंदुओं के दावे के बारे में एएसआइ की रिपोर्ट, ढांचा ढहने के पहले की वीडियो फोटोग्राफी, शिलालेख, ऐतिहासिक साहित्य है। उन्होंने 1858 की पुलिस शिकायत का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि जहां मस्जिद है और एक निहंग वहां मंदिर बनाना चाहता है।

चिकित्सा क्षेत्र में आएगा सुधार

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) विधेयक लोकसभा से 1 अगस्त को और राज्यसभा से 29 जुलाई को पारित हो गया है। इस नए कानून के तहत एनएमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेगा। साथ ही इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस कदम को चिकित्सा शिक्षा तथा सुविधाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार बताया है।

ये हैं प्रावधान

इस नए कानून के तहत देश भर में सिर्फ एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा, एकल निकास परीक्षा, विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा का प्रावधान है। एनएमसी में एक चिकित्सा सलाहकार परिषद होगी, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा। यूजीसी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक एनएमसी को सलाह देंगे और सिफारिश करेंगे। स्थापना और मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेजों को केवल एक बार अनुमति की आवश्यकता होगी। कॉलेज अपने दम पर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा और वे अपने दम पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकेंगे।

एमबीबीएस छात्रों को देनी होगी एग्जिट परीक्षा

एमबीबीएस पास करने के बाद छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एग्जिट परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के बाद डॉक्टरों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इसमें आने वाले अंक के आधार पर उनका नामांकन पीजी में हो जाएगा। पीजी के लिए अलग से होने वाली एनआइआइटी की परीक्षा स्वत: खत्म हो जाएगी। एग्जिट परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाएगा। फेल होने वाले छात्र दोबारा से यह परीक्षा दे सकेंगे। अपनी रैंक सुधारने के लिए भी दोबारा परीक्षा देने का प्रावधान है। विदेश से आने वाले एमबीबीएस के छात्रों को भी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी।

ये हुआ बदलाव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति की 109वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, जिसमें होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथी दवा लिखने की अनुमित थी।

संस्थानों की फीस

इस कानून के तहत देश भर के सभी निजी मेडिकल संस्थानों में 40 फीसद सीटों की फीस एनएमसी तय करेगा, जबकि शेष बची हुई 60 फीसद सीटों की फीस निजी संस्थान खुद तय करेंगे।

क्यों हुआ बदलाव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट (2016) में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज की जांच की और इसकी तीखी आलोचना की। जांच में पता चला कि एमसीआइ अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अपने निम्नतम स्तर पर है, चिकित्सा शिक्षा का वर्तमान मॉडल अच्छे स्वास्थ्य पेशेवरों का उत्पादन नहीं कर रहा है, जो देश की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चिकित्सा शिक्षा और पाठ्यक्रम हमारे स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरतों के साथ एकीकृत नहीं हैं, मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले कई छात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और यहां तक कि जिलास्तर पर खराब संसाधनों में सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चिकित्सा स्नातकों में सामान्य प्रसव कराने जैसे बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल कार्यों को करने में क्षमता की कमी है। अनैतिक अभ्यास के उदाहरण बढ़ रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टरों के प्रति सम्मान कम हो गया है। जांच में यह भी पता चला कि यदि एमसीआइ में कोई सदस्य भ्रष्ट है तो मंत्रालय के पास उसे हटाने का अधिकार नहीं है। इस तरह के मामलों से संकेत मिलता है कि एमसीआइ समय के साथ विकसित नहीं हुआ है।

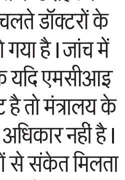

बड़ा कदम

रेलवे ने यात्रियों की हिफाजत और अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन किया है

रेलवे ने तैयार की 'कोरस' कमांडो यूनिट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ रेलमंत्री पीयूष गोयल बुधवार को 'कोरस' को लांच, करेंगे, 'कोरस' को एनएसजी व ग्रे हाउंड्स के केंद्रों में मिली है खास ट्रेनिंग

रेलवे ने पहली बार अपनी कमांडो यूनिट तैयार की है। 'कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी' अर्थात 'कोरस' नाम दिया गया है। इसके कमांडो की तैनाती जम्मू एवं कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी। बुधवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल तथा रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगदी एक समारोह में 'कोरस' को लांच करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल की अपनी कमांडो यूनिट का आइडिया आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार का है। उन्होंने आते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था।

रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, फिलहाल 'कोरस' की पहली बटालियन में रेलवे के सभी 18 जोनों में तैनात आरपीएसएफ की पुरुष बटालियनों के शारीरिक व मानसिक रूप से सर्वाधिक फिट जवानों को शामिल किया गया है। इन्हें विशेष यूनिफार्म, बुलेट प्रूफ जैकेट तथा हेलमेट के अलावा अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों से लैस किया गया है। कोरस के कामकाज की निगरानी, दिशा निर्देशन और तैनाती के बारे में आरपीएफ महानिदेशक स्वयं सीधे फैसला लेंगे।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, कोरस की ट्रेनिंग एनएसजी के मानेसर स्थित मुख्यालय के अलावा नक्सल आपरेशनों के लिए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना पुलिस द्वारा विशेष रूप से तैयार 'ग्रे हाउंड्स' फोर्स के ट्रेनिंग सेंटरों में चार चरणों में हुई है। बेसिक ट्रेनिंग के अलावा 'कोरस' कमांडो को अभी आगे और भी कई प्रकार के विशिष्ट व उन्नत प्रशिक्षणों से गुजारा जाएगा। इनमें सुरंगों तथा आइईडी की खोज व जांच कर उन्हें निष्क्रिय करने, बंधकों को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने, दूरबीन राइफल से निशाना लगाकर दुश्मन को खत्म करने तथा दीवारों और छतों को भेदकर बाहर निकलने जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं।

रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ का गठन केंद्र सरकार ने 1957 में इसी नाम से संसद से पारित एक्ट के जरिये किया था। इसका कार्य रेलवे परिसंपत्तियों जैसे पटरियों, स्टेशनों, कारखानों की रक्षा के अलावा ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। आरपीएफ और आरपीएसएफ में जवानों की स्वीकृत संख्या 76,653 है। इस समय इसमें लगभग इतने ही जवान व अधिकारी कार्यरत हैं। सशस्त्र शाखा को आरपीएसएफ नाम से जाना जाता है। जिसका गठन सशस्त्र सेनाओं की तरह बटालियन पैटर्न पर किया गया है। फिलहाल इसकी 15 बटालियनें हैं। एक बटालियन में अमूमन 600 जवान होते हैं। नवगठित कमांडो बटालियन को 'कोरस' के रूप में जाना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, निकट भविष्य में आरपीएफ का अपना कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हो सकता है।

कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की हालत गंभीर बता सरकार को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पूरी तरह रुकने का दावा करते हुए लाखों नौकरियां जाने की आशंका पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी ने कहा है कि विकास के चार अहम मानकों से जुड़े आंकड़ों से साफ है कि अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ रही है और हालात में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है।

आनंद शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि भारी बहुमत से सत्ता में आई भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को दूर करेगी, लेकिन हालात उलट हैं। औद्योगिक उत्पादन बेहद गिर गया है। बाजार में वस्तुओं की मांग घट गई है। कारखानों की उत्पादन क्षमता का एक तिहाई भाग ठप है। औद्योगिक उत्पादन दर दो फीसद से नीचे चली गई है। निवेश, औद्योगिक क्षमता विस्तार, निर्यात और मांग सभी चार पैमानों पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी ठप हो गई है। पूर्व वाणिज्य मंत्री ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की मंदी का जिक्र करते हुए कहा कि यात्री गाड़ियों का उत्पादन 20 फीसद से ज्यादा घट गया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

1 साल में विमान यात्रियों की संख्या में देश में 11 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में यह बढ़ोतरी 24 फीसद दर्ज की गई है। गुजरात में कुल 19 छोटे–बड़े एयरपोर्ट और एयरस्ट्रिप हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 अगस्त 2019

मनमोहन ने किया नामांकन, राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय

जागरण संवाददाता, जयपुर

- गहलोत और पायलट की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया
- भाजपा नहीं उतारेगी प्रत्याशी, गुलाब चंद कटारिया ने की पुष्टि

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। उधर, भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आलाकमान के हवाले से इसकी पुष्टि की है।

डॉ. मनमोहन सिंह ने नामांकन पत्र के चार सेट विधानसभा सचिव के समक्ष प्रस्तुत किए। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से उनका चुना जाना तय माना जा रहा है। उन्होंने राज्यसभा की जिस सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, वह सीट भाजपा के मदन लाल सैनी के निधन के कारण रिक्त हुई है। देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वह असम से पांच बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विधानसभा भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करने की बात कही।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को जयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। जागरण

गहलोत, पायलट और बसपा विधायक बने प्रस्तावक : मनमोहन सिंह ने नामांकन पत्र के चार सेट किए हैं। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस के 40 विधायकों और बसपा के सभी छह विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 198 विधायक हैं। दो विधायकों के सांसद निर्वाचित होने के बाद सीट रिक्त हैं। 198 विधायकों में से कांग्रेस को 121 विधायकों समर्थन हासिल हैं। इनमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 है। बसपा के छह, रालोद के एक और 12 निर्दलीय विधायकों ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायकों ने भी वोटिंग की जरूरत पड़ने पर मनमोहन सिंह का समर्थन करने की बात कही है।

नीरज शेखर आज दाखिल करेंगे नामांकन पत्र

राब्यू, लखनऊ : पूर्व सांसद नीरज शेखर बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बताया कि नीरज के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए विधान भवन स्थित भाजपा के विधान मंडल दल के कार्यालय में लोग 12 बजे एकत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर अभी हाल ही में राज्यसभा और सपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उप चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश कोटे से नीरज शेखर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

पीएम मोदी कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ

विनोद चौधरी, कुरुक्षेत्र : गीता की जन्मस्थली पर दिसंबर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 2019 के महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया है। हालांकि, अधिकारियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री व राज्यपाल कार्यालय की ओर से ही विधिवत निमंत्रण भेजने की बात कही है।

इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ तीन से आठ दिसंबर तक होगा, जबकि 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक ब्रह्मसरोवर के तट पर क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। इसी महोत्सव को खास बनाने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारी कई माह से तैयारियों में जुटे हैं। करीब डेढ़ माह पहले ही महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता करवाने के लिए बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा अधिकारी स्तर पर चार बैठकें अलग से हो चुकी हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी को भी धर्मनगरी से अच्छा खासा लगाव है। हरियाणा के प्रभारी रहते हुए वह कई बार कुरुक्षेत्र आते रहे हैं। इसके बाद भी चुनावों में और अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचते रहे हैं। उन्होंने ही कुरुक्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए श्रीकृष्णा सर्किट में भी शामिल करवाया था।

'हिंदू पाकिस्तान' वाले बयान पर फंसे थरूर, गिरफ्तारी वारंट जारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- 11 जुलाई, 2018 को तिरुवनंतपुरम में दिया था विवादित बयान
- कोलकाता के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया वारंट

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर के खिलाफ कोलकाता के मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव के कुछ माह पहले शशि थरूर द्वारा दिए गए 'हिंदू पाकिस्तान' वाले बयान के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ता सुमित चौधरी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह वारंट जारी किया है।

11 जुलाई, 2018 को तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो वह भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनाने जैसे हालात पैदा कर देगी। थरूर ने कहा था कि भाजपा एक नया संविधान लिखेगी, जो कि भारत को पाकिस्तान जैसे देश में बदलने का रास्ता साफ करेगा, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। उनका कोई सम्मान नहीं होगा।

थरूर ने आगे कहा था कि भाजपा का लिखा नया संविधान हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होगा, जो अल्पसंख्यकों के समानता के अधिकार को खत्म कर देगा और देश को 'हिंदू पाकिस्तान' बना देगा। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और

शशि थरूर फाइल फोटो

स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों ने ऐसे मुल्क के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी।

थरूर के इस बायन पर भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। भाजपा ने कांग्रेस पर देश के हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता के अधिवक्ता ने थरूर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाजिर होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए तो मंगलवार को कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया।

न्यूज गैलरी

जनवरी में हो सकता है भाजपा अध्यक्ष का चुनाव

नई दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले साल जनवरी महीने में ही संभव होगा। मंगलवार को संगठन चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई कार्यशाला में केंद्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 15 दिसंबर तक का वक्त तय किया है। भाजपा का सदस्यता अभियान अब 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में मंगलवार को संगठनात्मक चुनाव के लिए भी तिथि तय कर दी गई है। बैठक में राधामोहन के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। 30 सितंबर तक बूथ अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव होना है। उसके बाद 31 अक्टूबर तक मंडल अध्यक्ष, 20 नवंबर तक जिला अध्यक्ष और 15 दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाना है। हर चुनाव के बीच दस दिन का अंतराल रखा गया है ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके। जब आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश चुनाव संपन्न हो जाता है तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। (जाब्यू)

शिवानंद ने फिर साधा तेजस्वी यादव पर निशाना

पटना : बिहार में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में शिवानंद ने कहा कि तेजस्वी ने जो रास्ता अपनाया हुआ है उससे पार्टी की चुनावी नैया कैसे पार लगेगी, यह प्रश्न स्वाभाविक है। कुछ माह पहले राजद की राष्ट्रीय कार्यसमिति व स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की थी। तेजस्वी को नसीहत का पाठ पढ़ाया था। तब उन्होंने कहा था कि बड़ा नेता वही बन सकता है जो लाठी खाने को तैयार रहे। जेल भी जाना पड़ सकता है। अब शिवानंद ने कहा कि पार्टी के विधायकों में इस बात को लेकर निराशा है कि वह परिदृश्य से गायब हो गए हैं। (राब्यू)

उप्र में हारने वाले बूथों पर भी अब भाजपा के 70 फीसद सदस्य

लखनऊ : जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भाजपा के अनुकूल माहौल बना है। भाजपा के उत्तर प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने बताया कि सी–ग्रेड के जिन बूथों पर भाजपा हमेशा हारती थी और वहां पार्टी का कोई सदस्य नहीं था, उन बूथों पर भी 60 से 70 फीसद तक सदस्य बनाने में सफलता मिली है। मंगलवार को सुनील बंसल भाजपा मुख्यालय में सभी क्षेत्र एवं जिलों के सदस्यता प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन औसत तीन लाख सदस्य बनाए जा रहे थे, जो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद छह से सात लाख तक बढ़ गए। (राब्यू)

मध्य प्रदेश में जिला सरकार मॉडल की वापसी की तैयारी

योजना ▶ इसे संशोधनों के साथ लागू करेगी कमलनाथ सरकार

हर ब्लॉक को विकास के लिए अलग से मिलेगा फंड

वैभव श्रीधर, भोपाल

मध्य प्रदेश में 16 साल बाद जिला सरकार मॉडल की वापसी हो रही है। कमलनाथ सरकार इसे बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से संशोधनों के साथ लागू करेगी। इसमें हर ब्लॉक (विकास खंड) को विकास के लिए अलग से फंड मिलेगा। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के अधिकार भी जिला सरकार को होंगे। जिला योजना समिति को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मसौदे को सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झंडी के बाद कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

जिला सरकार व्यवस्था लागू होने के बाद प्रभारी मंत्रियों को और अधिकार मिल जाएंगे। जिलों में वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। साल में एक बार जिले के विकास

कमलनाथ फाइल फोटो

की पूरी योजना बनेगी। इसमें सड़क, बिजली, पानी, नगरीय व ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल शिक्षा से लेकर अन्य कामों को मंजूरी दी जाएगी। बड़ी योजनाएं ही प्रदेशस्तर पर निर्णय के लिए आएंगी। विकास का पहिया जिले में बराबर घूमे, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर फंड की व्यवस्था बनाने का विचार है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले में ही हो जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सूत्रों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निराकरण भी जिला सरकार के स्तर पर ही होगा। विधायक, जिला व जनपद पंचायत के साथ नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की सुनवाई न होने की आपत्ति का निराकरण भी इस माध्यम से हो जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि दो करोड़ रुपये तक के बड़े कामों की मंजूरी जिला सरकार ही दे देगी। इसमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि वे काम विभागों की कार्ययोजना में पहले से प्रस्तावित न हों, ताकि दोहराव की स्थिति न बने। प्रशासनिक अधिकारों के तहत जिला सरकार को जिले में विभागीय समीक्षा करने, गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करने, परियोजनाओं के निरीक्षण का अधिकार भी दिया जाएगा। विभिन्न समितियां बनाकर जनप्रतिनिधियों को इनका सभापति बनाया जाएगा। हर दो माह में जिला योजना समिति की बैठक करना अनिवार्य किया जाएगा। विभागीय मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से अधिकारों के विकेंद्रीकरण की पक्षधर रही है। त्रिस्तरीय पंचायतराज और स्थानीय निकायों के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। जिला योजना समितियों को सशक्त बनाया जाएगा। इस मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट में विचार-विमर्श के बाद होगा।

370 पर संविधान को नकारा गया : प्रियंका

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

- कांग्रेस महासचिव ने कहा, इसे लेकर पार्टी में कोई अलग–अलग राय नहीं
- सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से की मुलाकात, कहा–कांग्रेस पर आरोप लगाना भाजपा की आदत

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस में कोई अलग-अलग राय नहीं है। इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान को नकार कर निर्णय लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो राय है, वही सबकी राय है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच किसी बात को लेकर चर्चा नहीं होती, लेकिन हमारे यहां भाजपा की तरह चर्चा की बात को दबाया नहीं जाता है। वह मंगलवार को उप्र के सोनभद्र स्थित उभ्भा गांव पहुंचीं। यहां उन्होंने करीब दो घंटे का समय नरसंहार में मारे गए लोगों के पीड़ित परिजनों व घायलों के बीच बिताया। एक-एक कर सभी से घटना के बारे में पूछा। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मृतक अशोक के घर पहुंचीं। वहां सावां की खीर व खोवा खाकर इस लड़ाई में परिजनों के साथ होने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में भाजपा पर हमला भी बोला। कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाना भाजपा की आदत है। जिम्मेदारी उनकी है, समस्या सुलझानी चाहिए। पीड़ितों पर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस कराने व जमीन दिलाने के लिए हर कदम पर साथ देने का भरोसा दिया।

दोषियों को मिले फांसी : प्रियंका से मुलाकात के दौरान मृतक अशोक की पत्नी लालदेई ने कहा कि आरोपित भूर्तिया परिवार को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं सीता ने कहा कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। गांव में स्कूल होना चाहिए। जब तक खसरा, खतौनी हम लोगों के नाम नहीं हो जाती, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उभ्भा गांव का दौरा कर हाल ही में जमीन विवाद में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। एएनआइ

प्रियंका के निजी सचिव ने मीडियाकर्मी को कहा– ठोक दूंगा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सोनभद्र के उभ्भा गांव में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा कवर करने गए एक मीडियाकर्मी से उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने मारपीट की और ठोक देने तक की धमकी दे डाली। मीडिया कर्मी नीतिश पांडेय ने घोरावल थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। नीतिश के मुताबिक वह कवरेज के लिए काफिले के पीछे जा रहे थे। इसी दौरान उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने मारपीट की। कैमरा मैन के साथ भी अभद्रता करते हुए कैमरे पर हाथ लगा दिया। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बता दें कि संदीप सिंह आइसा के टिकट पर जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मामला राजनीतिक नहीं होता तभी क्यों करते हैं अच्छा काम : सीजेआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीबीआइ के काम–काज को लेकर मुख्य न्यायाधीश की तीखी टिप्पणी

राजनीतिक तौर पर तो सीबीआइ को लेकर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। अब मुख्य न्यायाधीश ने भी उसके काम-काज पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मंगलवार को सीबीआइ के ही कार्यक्रम में उसके काम पर सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि जब कोई मामला राजनीति से जुड़ा नहीं होता, तब वह क्यों अच्छा काम करते हैं? उन्होंने सीबीआइ को भय और किसी के प्रभाव में आए बगैर निष्पक्ष तरीके से काम करने की सलाह दी।

जस्टिस गोगोई सीबीआइ की ओर से आयोजित 18वीं डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में पुलिस की भूमिका विषय पर बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान सीबीआइ को सीएजी (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) जैसे अधिकार देने की भी वकालत की। जिसमें उसके पास वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी हो। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआइ को मौजूदा

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जागरण

जरूरत के हिसाब से तैयार होने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें ज्यादा से ज्यादा तकनीकी और शोध से जुड़े पेशेवर लोगों जोड़ने की जरूरत है। इस बीच उन्होंने सीबीआइ में खाली पदों का भी मुद्दा उठाया।

सीबीआइ के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला सहित सेना प्रमुख बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख वीएस धनोआ आदि भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर बेहतर काम करने वाले सीबीआइ के अधिकारियों, कर्मचारियों और सिपाहियों को सम्मानित भी किया गया।

केन–बेतवा पानी बंटवारे को लेकर मप्र ने मांगी उप्र से पानी के उपयोग की योजना

नईदुनिया, भोपाल

केन-बेतवा परियोजना पन्ना से उत्तर प्रदेश को पानी देने का विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन के लिए परियोजना से 900 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी की मांग कर रही है, जबकि समझौता 700 एमसीएम पानी देने का हुआ था। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश से रबी सीजन में खर्च होने वाले पानी की योजना मांगी है। साथ ही पानी के संग्रहण की तैयारी भी पूछी है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्लान अगले 20 दिन में देना है। इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जिसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है।

परियोजना का अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है और पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। इस मामले में समझौते के प्रयास प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हो चुके हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। दरअसल, परियोजना निर्माण के चलते हुए समझौते के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने 700 एमसीएम पानी की मांग की थी, जो बाद में बढ़ा दी गई। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार उतना ही पानी देने को तैयार है, जो तय हुआ था। इसे लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। मार्च में केंद्रीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी भोपाल आए थे। तब इस मसले पर बैठक हुई थी। इस बैठक में पानी के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश का नया प्रस्ताव सामने आया। उप्र की ओर से मप्र के अफसरों ने 930 एमसीएम पानी की मांग रखी गई थी। इस पर मप्र के अफसरों ने आपत्ति दर्ज कराई तो प्रस्ताव में संशोधन कर इसे 900 एमसीएम कर दिया गया था। मप्र के अफसर इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि समझौते के वक्त जो तय हुआ था, उसी हिसाब से पानी दिया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार के दबाव के चलते मप्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पानी स्टोरेज और रबी सीजन में खर्च होने वाले पानी का प्लान मांगा है, ताकि मप्र को स्पष्ट तौर पर पता चल सके कि उत्तर प्रदेश को वास्तव में कितने पानी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर के पहले हफ्ते में यह प्लान सौंपना होगा।

कमेटी कर चुकी है मुआयना : परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 27 से 30 मार्च तक पन्ना नेशनल पार्क और उससे सटे बांध के हिस्से का निरीक्षण कर चुकी है। कमेटी ने परियोजना की तैयारियों और बांध से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस आधार पर परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिलेगी।

20 दिन में उत्तर प्रदेश को सौंपना होगा प्लान, उसी हिसाब से दिया जाएगा पानी

> दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे को लेकर बैठकों को दौर चल रहा है। हमने उप्र सरकार से पानी के स्टोरेज की क्षमता और रबी सीजन में लगने वाले पानी की जरूरत पर प्लान मांगा है।
> – एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग

वकीलों की हड़ताल पर हाई कोर्ट नाराज

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ : हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन विरोध में धरने पर बैठे वकीलों व न्यायपालिका में टकराव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है, वहीं हाई कोर्ट ने वकीलों द्वारा लिटीगेंट (न्याय चाहने वाले) को कोर्ट में आने से रोकने पर कड़ा रुख अपनाते हुए चंडीगढ़ के सलाहकार, गृह सचिव और डीजीपी को बुधवार को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हाई कोर्ट ने तीन शिकायतों पर संज्ञान लेकर कड़ा रवैया अपनाते हुए लिटीगेंट को रोकने पर कहा कि यह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इंसाफ के लिए किसी को कोर्ट में जाने से रोकना उसका हक छीनना है और ऐसा होने पर हाई कोर्ट मूक दर्शक बनकर देखता नहीं रहेगा। वहीं हाई कोर्ट के जजों की फुल बेंच की बैठक में तय किया गया कि अगर किसी केस में कोई वकील पेश नहीं होगा तो केस को खारिज किया जा सकता है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने काफी संख्या में केस खारिज भी किए। वकीलों की हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है। इस मामले में गठित चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस आरके जैन की फुल बेंच ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को आधार बनाते हुए मंगलवार को सुनवाई आरंभ की।

तैयारी

उत्तर प्रदेश के विधानभवन, सचिवालय व लोकभवन की सुरक्षा के लिए उठाए जाएंगे कई कदम

उप्र में बुलेटप्रूफ होंगे सीएम कार्यालय के शीशे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वैसे तो कोई नया खतरा नहीं है फिर भी उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने लोकभवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में बाहरी तरफ लगे शीशों को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इसलिए राजकीय निर्माण निगम को अब इन शीशों को बुलेटप्रूफ बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

विधान भवन, सचिवालय परिसर और लोकभवन की सुरक्षा के लिए सीआइएसएफ की रिपोर्ट पर अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री कार्यालय के शीशों को बुलेटप्रूफ बनाने के साथ लोकभवन के पंचम तल पर एक एक्स-रे बैगेज स्कैनर भी लगाने को कहा गया है। इन इमारतों में घुसपैठ की आशंका खत्म करने के लिए चहारदीवारी पर लेजर आधारित या इसी तरह का कोई अन्य सिस्टम लगाया जाएगा। चहारदीवारी के पास के पेड़ों की कटाई-छंटाई के साथ नजदीक के बिजली खंभों को भी एक हफ्ते में हटाया जाएगा।

इसके अलावा परिसर के वाच टावरों को भी 10 दिन में नेट से कवर करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई ग्रेनेड से नुकसान न पहुंचा सके। इन परिसरों के पार्किंग स्थल में एंटी सेबोटाज जांच होगी, जबकि लोकभवन के सुरक्षाकर्मियों को एटीएस से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। लोकभवन में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाने और इनके जरिए पूरे परिसर पर नजर रखने की व्यवस्था बनाने को कहा गया है, जबकि लोकभवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी होंगे उपाय : विधान भवन परिसर में चार पहिया वाहन आरएफआइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग से और दोपहिया वाहन स्मार्ट कार्ड से इंट्री पाएंगे। पैदल आने वाले लोकभवन के गेट नंबर छह व छह-ए से अस्थायी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी कराके जांच के बाद प्रवेश पा सकेंगे। लोकभवन के गेट नंबर तीन, चार, आठ व नौ के प्रवेश द्वार पर रंबल स्ट्रिप बनाई जाएगी।

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

अग्निसुरक्षा पर दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि

लखनऊ और सचिवालय के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को यह पता ही नहीं है कि विधान भवन और लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित एनेक्सी को अग्निसुरक्षा के लिहाज से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं। इस पर दोनों अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

कोलकाता की दुर्गा पूजा कमेटियों को नहीं भेजा गया आयकर नोटिस : सीबीडीटी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग की ओर से कोलकाता की दुर्गा पूजा कमेटियों को नोटिस भेजे जाने की खबरों का खंडन किया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस साल कोलकाता की किसी भी दुर्गा पूजा कमेटी को नोटिस नहीं भेजा है। उधर, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कमेटियों को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजे जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को कोलकाता में आठ घंटे तक धरना दिया।

बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग को पिछले साल दिसंबर में सूचना मिली थी कि दुर्गा पूजा कमेटियों के साथ काम करने वाले 30 ठेकेदारों और इवेंट मैनेजरों ने करों का भुगतान नहीं किया था। इस पर आयकर विभाग ने दिसंबर 2018 में दुर्गा पूजा समितियों को नोटिस जारी करके ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर काटे गए टीडीएस की जानकारी मांगी थी। यह पूरी प्रक्रिया विभाग की टीडीएस विंग ने अपनाई थी। इसका मकसद ठेकेदारों और इवेंट मैनेजरों को समय से बकाया करों का भुगतान करने के बारे में सूचित करना था। सीबीडीटी के अनुसार, कई कमेटियों ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने नियमानुसार टीडीएस की कटौती की है और उस धन को सरकारी खाते में जमा करा दिया है। सीबीडीटी ने बयान में कहा है कि कुछ दुर्गा पूजा कमेटियों ने टीडीएस के प्रावधान जानने के लिए एक विशेष शैक्षणिक सेशन आयोजित करने की मांग की थी। कमेटियों की मांग पर आयकर विभाग ने 16 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित कर टीडीएस के प्रति जागरूक किया था। इस विशेष सेशन में आठ समितियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आयकर विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी तरह से दुर्गा पूजा कमेटियों के खिलाफ नहीं है। साथ ही विभाग चाहता है कि सभी ठेकेदार और इवेंट मैनेजर अपने सभी बकाया टैक्स समय पर जमा कर दें।

बंगाल सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे प्रशांत किशोर : भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त किए गए प्रशांत किशोर पर एक बार फिर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, तृणमूल कांग्रेस को बचाने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और इसके एवज में एक बड़ी धनराशि का लेन-देन भी होना है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि कोई भी वर्तमान परिस्थिति में तृणमूल कांग्रेस को नहीं बचा सकता।

उल्लेखनीय है कि पहले भी भाजपा नेता ने इस तरह के आरोप लगाए थे, जिस पर तृणमूल की ओर से सफाई दी गई थी। तृणमूल ने कहा था कि प्रशांत की टीम ने किसी भी सरकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया है।

72.6 वर्ष है जम्मू-कश्मीर में जीवन प्रत्याशा दर यानी एक व्यक्ति का औसत जीवन काल। इस मामले में सिर्फ केरल (74.9) और दिल्ली (73.2) ही इससे आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास इंडेक्स के मुताबिक, भारत में जीवन प्रत्याशा 67.9 वर्ष है।

राहुल ने कश्मीर जाने का राज्यपाल का न्योता कुबूला

- मलिक के न्योते पर कांग्रेस नेता ने विपक्षी नेताओं संग कश्मीर आने की बात कही
- कहा-खुले आसमान के नीचे घूमने और लोगों से मिलने की आजादी दी जाए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घाटी आने की चुनौती स्वीकार कर गेंद एक बार फिर राज्यपाल के पाले में डाल दी है। राहुल ने कहा है कि वे दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ कश्मीर जाने को तैयार हैं। इसके लिए विशेष विमान की जरूरत नहीं, लेकिन राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि विपक्षी नेताओं को वहां खुले आसमान के नीचे घूमने और लोगों से मिलने की आजादी मिलेगी। कांग्रेस ने भी जम्मू-कश्मीर में संपूर्ण नाकेबंदी की खबरों पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से विपक्षी नेताओं को घाटी जाने की इजाजत देने का आग्रह किया है।

कांग्रेस की ओर से घाटी में स्थिति गंभीर होने के दावे को खारिज करते हुए मलिक ने कहा था कि वह राहुल को हालात का जायजा लेने के लिए न केवल आमंत्रित करते हैं, बल्कि विशेष विमान भेजने को भी तैयार हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल की चुनौती पर जवाबी दांव चलते हुए अपने साथ विपक्षी

राहुल गांधी फाइल फोटो

सत्यपाल मलिक फाइल फोटो

नेताओं को भी वहां ले जाने की इजाजत मांगी। राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'प्रिय राज्यपाल, विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के आपके गरिमापूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करने को तैयार हैं। हमें इसके लिए विमान की जरूरत नहीं। केवल इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि हमें वहां घूमने, लोगों, मुख्यधारा के नेताओं और वहां तैनात हमारे जवानों से मिलने की आजादी होगी।' कांग्रेस ने भी प्रेस कांफ्रेंस में जम्मू-कश्मीर में संचार नेटवर्क पर पूरी तरह से पाबंदी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक छवि का अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि भारत दुनिया का बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और हमारे लोगों के मौलिक संवैधानिक अधिकार हैं। ऐसे में नौ दिनों से जारी संपूर्ण नाकेबंदी की स्थिति चिंता की बात है। इस चिंता का निवारण करने के लिए विपक्षी राजनीतिक नेताओं को कश्मीर जाने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा कि जब सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही है तो फिर कुछ विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही जबरन वापस क्यों भेज दिया गया। हालात ठीक हैं तो राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा?

मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं राहुल : जम्मू-कश्मीर राजभवन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राहुल गांधी के बयान पर जम्मू-कश्मीर राजभवन ने कहा है कि वह विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर आने की बात करके मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिससे हालात खराब होंगे और आम लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सीमा पार की फर्जी खबरों पर राहुल गांधी का यह कहना कि कश्मीर में हालात खराब हैं, यह बिलकुल गलत है।

हताशा में बिखरी पाक की कूटनीतिक मोर्चेबंदी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत के फैसले के खिलाफ दुनियाभर में कूटनीतिक पेशबंदी में लगा पाकिस्तान खुद अपनी ही चालों में उलझ गया है। एक तरफ, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी परोक्ष रूप से हार स्वीकारने लगे हैं तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के तर्कों को खास तवज्जो नहीं मिलते देख उसके राजनयिकों के मतभेद भी सामने आने लगे हैं। पाक की हताशा इसलिए भी ज्यादा है कि चीन और इस्लामिक देशों की तरफ से भी अभी तक उसे वैसा समर्थन नहीं मिला है जैसा कि हुक्मरान उम्मीद कर रहे थे। इस्लामिक देश इस मुद्दे पर चुप हैं। वहीं, शुरुआती नाराजगी दिखाने के बाद चीन का रुख भी बदला हुआ है।

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत जाहिद नसरुल्लाह खान ने यह मानने से इन्कार कर दिया है कि भारत ने कश्मीर में जो कदम उठाया है वह अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता को प्रभावित करेगा। वहीं, अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद एम. खान का कहना है कि, कश्मीर को लेकर विवाद बढ़ते देख पाक को अपनी सेना पश्चिमी सीमा से हटा कर पूर्वी सीमा पर तैनात करनी पड़ सकती है।

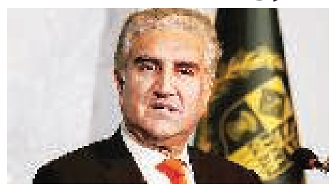

शाह महमूद कुरैशी फाइल फोटो

उन्होंने सीधे तौर पर इसे अफगानिस्तान में चल रहे शांति समझौते से जोड़ा है। पाक के विदेश मंत्री कुरैशी ने भी यही बात कुछ दिन पहले कही थी। पाकिस्तान की कूटनीति को मंगलवार को दो और झटके लगे हैं। सबसे पहले तो भारत व चीन के विदेश मंत्रियों की सोमवार को हुई मुलाकात में चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई खास टीका-टिप्पणी नहीं की गई है। इसमें कश्मीर का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई गई है कि भारत दक्षिण एशिया में शांति व स्थायित्व के लिए रचनात्मक प्रयास करेगा। बैठक में चीन की तरफ से कश्मीर मुद्दा उठाया गया था, लेकिन भारत ने बेहद ठोस शब्दों में अपना पक्ष रखा था कि यह उसका आंतरिक मामला है और अनुच्छेद 370 हटाने से मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा झटका पोलैंड ने दिया है। पोलैंड अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मौजूदा अध्यक्ष है। यही वजह है कि कुरैशी ने उनसे बात की और कश्मीर में हस्तक्षेप की गुजारिश की, लेकिन नई दिल्ली में पोलैंड के राजदूत ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में साफ कर दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे द्विपक्षीय आधार से ही सुलझाना चाहिए।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, किसी भी देश ने समग्र तौर पर पाक के रुख का समर्थन नहीं किया है जबकि कई देश यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है। यह बता रहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ अब नहीं चल रहा। यही बात भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल भी मानते हैं। उनके मुताबिक, 'पाकिस्तान यह समझ नहीं पा रहा कि कश्मीर पर पूरी स्थिति बदल चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर अब दोनों देशों के बीच बातचीत का मुद्दा नहीं रहा।' यही नहीं पाक का यह तर्क भी टूट गया है कि अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप की पेशकश की है। वाशिंगटन में भारत के राजदूत हर्ष श्रृंगला ने मंगलवार को साफ किया कि, मध्यस्थता का कोई भी प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नही किया गया है।

पाक की खुफिया एजेंसी आतंकी हमले की फिराक में

जताई आशंका ▸ कुछ रेडियो संदेश भी पकड़े गए, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

प्रशासन ने वादी में जारी पाबंदियों को और दो दिनों तक जारी रखने का किया फैसला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से तनावग्रस्त वादी में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन अगले दो दिन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। कुछ रेडियो संदेश भी पकड़े गए हैं। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। सभी संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया है।

प्रशासन ने वादी में बीते आठ दिनों से जारी प्रशासनिक पाबंदियों को एहतियातन अगले दो दिनों तक जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी स्वतंत्रता दिवस के दौरान आतंकी खतरे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा कवायद को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति चुनौतीपूर्ण है।

सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को लेकर बीते एक सप्ताह के दौरान जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उससे आतंकियों के आका हताश हो चुके हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जिस तरह अलग-थलग पड़ चुका है, उसे देखते हुए आइएसआइ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कुछ रेडियो संदेश भी पकड़े गए हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि बीते एक सप्ताह से अपनी मांद में छिपे आतंकियों को गुलाम कश्मीर में बैठे उनके कमांडर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार कह रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी ने बताया कि आतंकी अपनी उपस्थिति का अहसास कराने के लिए किसी सॉफ्ट टारगेट को चुन सकते हैं। वह किसी जगह बम विस्फोट या सुरक्षाबलों के कैंप पर हमला कर सकते हैं। किसी जगह विशेष पर किसी वर्ग विशेष को भी निशाना बना सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में एहतियात के तौर पर हिरासत में लिए गए शरारती तत्वों और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों को पहले ईद के मद्देनजर छोड़ने का फैसला लिया गया था, जिसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। सभी अस्पतालों, सरकारी प्रतिष्ठानों, पुलिस थानों, सीआरपीएफ व सैन्य शिविरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईवे पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।

आतंकग्रस्त इलाकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ाई : आतंकी खतरे से निपटने के लिए चिह्नित स्थानों पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी व पुंछ समेत राज्य के सभी आतंकग्रस्त इलाकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

'घाटी में सेना जनता से बनाएगी करीबी रिश्ते'

- सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा, एलओसी पर पाक सेना का जमावड़ा चिंता की बात नहीं
- बोले, भारतीय सुरक्षा बल हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार

नई दिल्ली, एएनआइ : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) के उस तरफ पाकिस्तानी सेना की तैनाती को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वह उनका एहतियाती कदम है। जनरल रावत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी हम जनता के साथ हैं। घाटी में सेना के जनता के साथ संबंधों को छठे व सातवें दशक की तरह सामान्य बनाया जाएगा।

जनरल रावत ने मंगलवार को कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में छठे और सातवें दशक में सेना आम जनता के साथ मिलकर रहती थी। हम एक-दूसरे से बिना बंदूकों के मिला करते थे। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो हमारे आपसी संबंध पहले जैसे हो जाएंगे।

सेना के वरिष्ठ कमांडर जम्मू-कश्मीर के हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काकर उसे अशांत करने के लिए आइईडी धमाके और आत्मघाती हमले कर सकता है। इसके बाद से ही कश्मीर में 38 हजार जवान और तैनात किए गए हैं।

समचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल रावत ने पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा के पास अपनी सेना का जमावड़ा करने को सामान्य घटना बताया है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में एकदम शांति है। भारतीय सुरक्षा बल क्षेत्र में हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि हरेक देश को ऐहतियाती कदम उठाने का हक है। इसलिए पाकिस्तान के एलओसी के इर्द-गिर्द अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करने में कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ गलत होने पर हम हर बात के लिए तैयार हैं। अगर वह चाहते हैं कि नियंत्रण रेखा पर सक्रियता बनी रहे तो यही सही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर बड़ी तोपें तैनात कर रही है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाने के पहले से ही सीमा पर हाई अलर्ट घोषित है।

नई दिल्ली में मंगलवार को विज्ञान भवन में डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान के दौरान विमर्श करते थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत और वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ। डीपी कोहली सीबीआइ के संस्थापक निदेशक थे। एएनआइ

370 पर चिदंबरम का बयान हताशा का प्रतीक : जावडेकर

- कांग्रेस नेता पर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का लगाया आरोप
- कहा, नई व्यवस्था से खुश हैं जम्मू-कश्मीर के लोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 को हटाने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम के विवादास्पद बयान को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बेईमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस से आ रही अलग-अलग आवाजें निराशा, हताशा और दिशाहीन राजनीति को दिखाती हैं। चिदंबरम पर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए जावडेकर ने कहा कि अनुच्छेद-370 को खत्म करने के फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग खुश हैं।

चिदंबरम ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 को इसलिए खत्म किया, क्योंकि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है। अगर वह हिंदू बहुल राज्य होता तो राजग सरकार यह फैसला नहीं लेती। जावडेकर ने कर्ण सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह और अन्य नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रमित है और उसका कभी स्पष्ट रुख नहीं रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग प्रगति करेंगे और उन्हें वे अधिकार मिलेंगे, जिनसे वे 70 साल से वंचित रखे जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस हमें इस सवाल का जवाब दे कि वह अपने राज के दौरान जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून

प्रकाश जावडेकर फाइल फोटो

और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून लागू क्यों नहीं करा सकी थी?

कांग्रेस नेता चिदंबरम पर हमला बोलते हुए जावडेकर ने कहा कि कुछ लोग यदि कश्मीर में फलस्तीन देखते हैं, तो यह उनकी नकारात्मक सोच है। चिदंबरम मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और यह गंदी राजनीति है। जावडेकर ने दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न अंग है। इसीलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीओके की सीटें खाली रहेंगी।

कश्मीर पर अपने पत्र के लिए अमेरिकी सांसद ने मांगी माफी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने भारतवंशियों से बातचीत किए बिना जम्मू-कश्मीर के हालात पर विदेश मंत्री माइक पोंपियो को पत्र लिखने के लिए माफी मांगी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के बाद डेमोक्रेट सांसद टॉम सूजी ने नौ अगस्त को पोंपियो को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारत सरकार के फैसले से कश्मीर में सामाजिक अशांति बढ़ने की आशंका जताई थी। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्य सूजी ने लिखा था, 'जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता पर लगी नई पाबंदियां कट्टरपंथी और आतंकियों को प्रोत्साहित करने वाली हो सकती हैं।' इस पत्र से भड़के भारतीय-अमेरिकियों ने सांसद को नाराजगी भरे संदेश भेजे थे। इसके बाद सूजी ने भारतवंशी समुदाय के साथ बैठक की। बैठक में शामिल होने आए भारतीय-अमेरिकियों ने उनसे पत्र वापस लेने की मांग की। इस पर सूजी ने कहा, 'मुझे पहले आपसे चर्चा करनी चाहिए था। ऐसा करने से मैं अपनी चिंता सही तरीके से पेश कर सकता था।' भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों की बात करते हुए उन्होंने खुद को भारत की संप्रभुता का समर्थक बताया।

नई सोच, नई उम्मीद...

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जनमानस पर छाए हुए हैं। पीएम मोदी के दृढ़ इरादों का असर ऐसा है कि जम्मू-कश्मीर अब नई सोच, नई उम्मीद की राह पर है। यहां आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है और स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियो में मशगूल हो गया है। नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली चीजों की मांग बढ़ गई है। मंगलवार को जम्मू में पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंगें बेचता दुकानदार। प्रेट्र

महिला अधिकारी शांति बनाए रखने में निभा रहीं अहम भूमिका

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य के लोगों का विश्वास जीतने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महिला अधिकारी भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर कश्मीर में तैनात महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) की अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हैं।

इनमें सूचना निदेशक के पद पर तैनात 2013 बैच की आइएएस अधिकारी डॉ. सहरीश असगर और 2016 बैच की आइपीएस पीके नित्या शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटाने से कुछ दिन पहले ही सहरीश असगर को सूचना निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका काम मुख्य रूप से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना था, लेकिन अब उनकी भूमिका पूरी तरह बदली हुई है। वह राज्य के हालात से निपटने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। वह बाहरी राज्यों में रह रहे कश्मीर के युवाओं से उनके परिजनों की बात करवा रही हैं। उनकी शिकायतों का समाधान कर रही हैं। डॉ. सहरीश असगर एमबीबीएस डॉक्टर थीं, लेकिन आइएएस में चयन के बाद उन्होंने डॉक्टर के पेशे को छोड़ दिया। उनका कहना है कि इस समय अलग चुनौती है। यहां पर एक तरफ सख्ती बरतनी पड़ती है तो दूसरी ओर लोगों को भावनात्मक सहयोग भी देना पड़ता है। यह उनके लिए खुशी की बात है कि महिलाएं समाज में बदलाव ला रही हैं। आइपीएस पीके नित्या छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। उन्हें श्रीनगर के राम मुंशी बाग और हारवान डाची गांव क्षेत्र का सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह वह क्षेत्र है, जहां डल झील के अलावा राजभवन है और कई वीआइपी रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें आम नागरिकों के साथ वीआइपी की सुरक्षा को भी देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह दुर्ग से आती हैं जो शांत क्षेत्र है, लेकिन यहां पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जम्मू में डिप्टी कमिश्नर की कमान सुषमा चौहान को सौंपी गई है। उन्होंने भी तमाम विपरीत हालात में जम्मू में स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। जम्मू संभाग में रियासी जिले की कमान इंदू कंवल को सौंपी गई है। यह वह जिला है, जहां श्री माता वैष्णो देवी का तीर्थस्थल है। इस जिले में भी तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन उन्होंने भी स्थिति को बखूबी संभाला हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस के बाद चरणबद्ध तरीके से हटेंगे प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने कहा है कि कश्मीर घाटी में हालात ज्यों ज्यों सुधरते जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।

रोहित कंसल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा,कश्मीर में स्थानीय प्रशासन अलग-अलग जगह पर हालात की समीक्षा करेगा। उसी के आधार पर प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया जाएगा। लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। पाबंदी के दौरान साढ़े 13 हजार से अधिक लोगों ने अस्पतालों में ओपीडी में स्वास्थ्य जांच करवाई, जबकि 14 सौ लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। जीवन रक्षक सहित सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है। रोजाना सौ गाड़ियां एलपीजी सहित सभी जरूरी सामान लेकर कश्मीर आ रही हैं। 14-15 सौ छोटी बड़ी गाड़ियां भी यात्रियों को लेकर आ जा रही हैं।

रोहित कंसल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। हर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। मंगलवार को हर जिले में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है।

तैयारी

जम्मू-कश्मीर में 107 से बढ़ाकर 114 विधानसभा सीटें करने का प्रस्ताव, चुनाव आयोग ने की अहम बैठक

केंद्र से हरी झंडी मिलते ही शुरू होगा परिसीमन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर मंगलवार को पहली अहम बैठक बुलाई, जिसमें आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से नए परिसीमन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

जानकारी के अनुसार, आयोग जल्द ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय लोगों से विचार के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा-60 के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी।

मंगलवार को दो घंटे चली चुनाव आयोग की बैठक में परिसीमन के बारे में विस्तार पूर्वक विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, परिसीमन की पूरी रूप रेखा के बारे में आयोग की एक टीम ने मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा को एक प्रस्तुति भी दी है।

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में परिसीमन होते ही विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव होगा और विधानसभा क्षेत्रों का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में आज तक कश्मीर का ही पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि विधानसभा में कश्मीर की विधानसभा सीटें, जम्मू के मुकाबले ज्यादा रही हैं। लेकिन अब परिसीमन होने से जम्मू की सीटें बढ़ सकती हैं।

मौजूदा स्थिति में जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में कुल 87 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें घाटी में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें हैं। परिसीमन में सीटों के बदलाव में आबादी और वोटरों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है।

लद्दाख बगैर विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश

बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद से पास करवाया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत प्रदत्त कानूनों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन 2019 विधेयक को पेश किया था। इस विधेयक के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा होगा। लद्दाख बगैर विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा। अभी जम्मू-कश्मीर में कुल 111 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 87 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं। बाकी 24 गुलाम कश्मीर के लिए खाली रखी जाती हैं। अब नए परिसीमन के तहत लद्दाख के खाते की 4 सीटें हट जाएंगी।

सरकार ने अब कश्मीर में विरोध की घटना की बात मानी

नई दिल्ली, आइएएनएस : सरकार ने मंगलवार को स्वीकार किया कि कश्मीर घाटी में पिछले हफ्ते शुक्रवार को नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन की घटना हुई थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने संयम रखा और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं की। इससे पहले सरकार ने विरोध प्रदर्शन को लेकर मीडिया में आई खबरों का खंडन किया था।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि श्रीनगर के सौरा में विरोध प्रदर्शन की मीडिया में खबर आई थी। नौ अगस्त को स्थानीय मस्जिद से नमाज अदाकर लौट रहे लोगों के बीच शरारती तत्व घुस गए थे और अशांति पैदा करने के लिए बिना किसी वजह के ही सुरक्षा बलों पर पथराव किया था। सुरक्षा बलों ने संयम के साथ हालात काबू में करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की तरफ से गोली नहीं चलाई गई। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग की एक भी घटना नहीं हुई है।

जम्मू-कश्मीर की ओर होगा वित्तीय संस्थानों और सीएसआर का रुख

- दोनों नए केंद्र शासित राज्यों को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिशें शुरू

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को उद्यमिता से जोड़ने और दोनों नए केंद्र शासित राज्यों को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दो दिन पहले मुंबई में फाइनेंशियल इन्क्लूजन विषय पर हुए दो दिवसीय समिट में कई वक्ताओं ने माना कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों को अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आर्थिक उन्नयन के लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग करना चाहिए।

'वे टू पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉसपेरिटी' विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय समिट में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने एक शेर सुनाकर अपनी विशेष शैली में शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'अब कश्मीर में नहीं चलेंगे पत्थर, क्योंकि हट गया है तीन सौ सत्तर।' लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास में सीएसआर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आठवले की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि फाइनेंशियल इन्क्लूजन का मतलब ही वित्तीय बाजार में सभी को समान अवसर प्रदान करना है। इसके लिए आर्थिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है। उनके अनुसार, केंद्र सरकार की करीब 106 योजनाएं चल रही हैं। न सिर्फ इसकी जानकारी सभी को दी जानी चाहिए, बल्कि इनका लाभ भी जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए।

समिट में आए आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ गोपाल वी. कुमार के अनुसार, अभी तक जे एंड के बैंक एवं ओएनजीसी जैसी संस्थाएं ही जम्मू-कश्मीर में अपना सीएसआर फंड खर्च करती रही हैं। अन्य कंपनियां किसी न किसी कारण वहां जाने से कतराती रही हैं।

100 वां रेल इंजन का निर्माण कार्य झारखंड के दानकुनी चितरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) की सहायक इकाई ने वर्तमान 2019-20 में पूरा कर लिया है। चिरेका महाप्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि यह एक गौरवान्वित करने वाला कीर्तिमान है।

बारिश-बाढ़ से आफत में आधा हिंदुस्तान

कुदरत की मार से न उत्तर भारत बचा है न ही दक्षिण भारत। आसमान से आफत बसर रही, नीचे लोग त्राहीमाम-त्राहीमाम कर रहे हैं। बारिश-बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ओडिशा में आये जलप्रलय से अबतक 200 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 12 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यहीं नहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है।

केरल

केरल के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम जिले में स्थित कवलप्पारा व पुथुमाला गांव और वायनाड जिला सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यहां अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण केरल में अगले दो दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है।

महाराष्ट्र

यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। जबकि लगभग 4.48 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है, जिसमें कोल्हापुर और सांगली से 4.04 लाख लोग शामिल हैं। सभी को राहत शिविरों में सुरक्षित भेज दिया गया है।

ओडिशा

राजधानी भुवनेश्वर समेत पूरे राज्य में हो रही लगातार बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ मालकानगिरी जिले में बाढ़ की स्थिति ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जिले से होकर गुजरने वाली कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कंधमाल और गंजम जिले में भी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं और सैकड़ों लोग पानी के घेरे में आ गए हैं।

गुजरात

पिछले पांच दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं में लगभग 31 लोग मारे गए हैं। कच्छ जिले में बाढ़ में फंसे 125 लोगों को भारतीय वायु सेना द्वारा बचाया गया।

उत्तराखंड

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के तीन अलग-अलग गांवों में भूस्खलन में एक महिला और उसकी नौ महीने की बेटी सहित छह लोग जिंदा दफन हो गए। बाढ़ से घिरे चुफलागड़ नदी के पानी के बहाव में दो इमारतें बह गईं।

अन्य राज्यों में बाढ़ का खतरा

बाढ़ को लेकर मध्य प्रदेश के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी कुदरत का कहर बरपा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर है। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। गोवा के भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं।

कर्नाटक

यहां बाढ़ की चपेट में आने से अबतक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 12 लोग लापता हैं।

बाढ़ से मरने वालों की संख्या

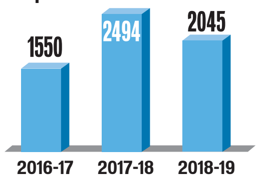

होता है भारी नुकसान

भारत में लगभग 15 फीसद बाढ़ का खतरा रहता है। इससे हर साल औसतन 2,000 लोग मारे जाते हैं और 80 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, जिससे हमें लगभग 1,800 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

बाढ़-बारिश में ढहे घर (लाखों में)

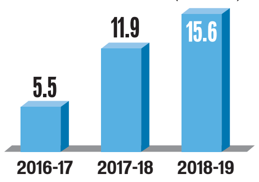

जिम्मेदार कौन?

ज्यादा बारिश ही नहीं हमारी योजनाओं में कमी भी बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे बनाने की तुलना में हम बाढ़ से प्रभावित लोगों पर अधिक खर्च करते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ फ्लड के मुताबिक जिन क्षेत्रों को बाढ़ से खतरा रहता है उन्हें सही समय पर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है ताकि जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके। 2017 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए 1997 से 2016 के बीच लगाए गए 375 टेलीमेट्री स्टेशनों में से 60 फीसद स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं।

न्यूज गैलरी

वर्धमान बम धमाकों में फरार आतंकी इंदौर से गिरफ्तार

इंदौर : वर्धमान बम धमाकों में फरार आतंकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। करीब दो साल से वह अलग-अलग क्षेत्रों में मजदूर बनकर रह रहा था। आजाद नगर थाना पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकी का नाम जहील उर्फ जाकिर पुत्र जूद अली शेख है। वह हैटरपारा थानेपर जिला नादिया (बंगाल) का रहने वाला है। उसे कोहिनूर कॉलोनी से शाकिर खान के मकान से पकड़ा गया। जहील, जमात-उल-मुजाहिद (जेएमबी) मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य है और उसे तीन लाख रुपये के इनामी मो. रिजाउल करीम का बेहद करीबी माना जाता है। वह अक्टूबर 2014 में खगड़ागढ़ (वर्धमान) में हुए बम विस्फोट में शामिल था, जिसमें जेएमबी के दो आतंकी भी मारे गए थे। जहील पर आतंकियों को विस्फोटक और हथियारों का प्रशिक्षण देने में महारत हासिल है। वह आतंकी ट्रेनिंग कैंप और बम बनाने का प्रशिक्षण ले चुका है। एनआइए जहील की एक वर्ष से निगरानी कर रही थी। एजेंसी को उसके एक रिश्तेदार के मोबाइल की जांच के दौरान इंदौर की लोकेशन मिली थी। (नईदुनिया)

दारोगा और कॉलेज प्रबंधक के बेटे निकले हथियार तस्कर

प्रयागराज : प्रयागराज की शाहगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात मुठभेड़ के दौरान 12 पिस्टल के साथ दो हथियार तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए युवकों में एक के पिता सब इंस्पेक्टर हैं तो दूसरे के पिता कॉलेज प्रबंधक। युवक बिहार से पिस्टल मंगाकर यहां दोगुने दाम पर बेचते थे। एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव के अनुसार एसओ शाहगंज बृजेश सिंह ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर खुसरोबाग की तरफ से तेज गति से आ रही कार को स्टेशन चौराहे पर घेरा तो उसमें एक युवक गोली चलाकर भागने लगा। उसे घेरकर पिस्टल समेत दबोच लिया गया। दूसरे युवक को भी पकड़ लिया गया। ड्राइविंग सीट के बगल में रखे थैले में प्वाइंट 32 बोर की 10 पिस्टल मिली। बरामद कार भाष्कर की है। एसपी सिटी ने बताया कि इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ चुके नवील के पिता सुहैल अहमद बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। फिलहाल उनकी तैनाती मधुबनी में है। भाष्कर के पिता इंद्रदेव तिवारी कौशांबी, उप्र में कई कॉलेजों का संचालन करते हैं। (जासं)

दरभंगा डीएम ने नहीं भेजी रिपोर्ट, अटकी सतीश की रिहाई

पटना : बांग्लादेश की जेल में कैद सतीश चौधरी की रिहाई दरभंगा के जिलाधिकारी की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अटकी हुई है। ढाका (बांग्लादेश की राजधानी) उच्चायोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी कि सतीश भारत देश के किस शहर या कस्बे का निवासी है? दरभंगा के अंचलाधिकारी ने सतीश के घर और पते का सत्यापन कर एडीएम को रिपोर्ट सौंप दी थी। अब डीएम उस रिपोर्ट को बांग्लादेश के भारतीय उच्चायोग को देंगे, तभी सतीश की रिहाई हो सकती है। इधर, डीएम की कार्यशैली को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। (जासं)

दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय

उन्नाव कांड ▶ दुष्कर्म के मामले में सेंगर पर पहले ही तय किए जा चुके हैं आरोप

पुलिस और विधायक के बीच बातचीत का डाटा भी कोर्ट में सीबीआइ ने पेश किया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के पिता की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में हुई। सत्र न्यायाधीश ने मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की अदालत से भी आरोप तय हो गए थे, लेकिन दिल्ली की अदालत ने हत्या और ऑर्म्स एक्ट के मामलों को मिलाते हुए आरोप तय किए हैं। पिछले सप्ताह दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

हत्या और झूठे केस के मामले में कुलदीप सेंगर व उसके भाई अतुल सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, एसआइ कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान सहित कुल 10 आरोपित हैं। मंगलवार को अदालत ने आरोपपत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के पिता को मारा गया था। इस दौरान उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई। इससे घटना के चौथे दिन पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। यह पूरा षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि पीड़िता शिकायत दर्ज न करा पाए। पुलिस ने जिस दौरान पीड़िता के पिता को पीटा, उस वक्त के गवाहों के बयान से साफ है कि सेंगर पुलिस के संपर्क में था। जांच एजेंसी ने यह तथ्य अपने आरोप पत्र में दर्ज किया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में गलत फंसाया गया था। पुलिस कर्मी विधायक की मदद कर रहे थे। पुलिस और विधायक के बीच बातचीत का डाटा भी कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता के पिता को पहले भीड़ ने पीटा, उसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआइ के आरोपों को नकार दिया और ट्रायल का सामना करने की बात कही। इस पर अदालत ने दोनों मामलों को मिलाते हुए आरोपितों पर आरोप तय किए।

आरोपित विधायक पर लगाया धमकी देने का आरोप : पीड़िता की तरफ से तीस हजारी अदालत में पैरवी कर रहे अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर पर धमकी देने का आरोप लगाया। अधिवक्ता मिश्रा के मुताबिक कुलदीप सेंगर ने अदालत में अपनी गर्दन पर हाथ घुमाते हुए धमकी भरा इशारा किया।

जमानत रद कर भेजा जेल

माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, एसआइ कामता प्रसाद और सिपाही आमिर खान जमानत पर थे। मंगलवार को अदालत ने तीनों की जमानत रद कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट का 20 मामलों की स्थिति रिपोर्ट मांगने से इन्कार

- कहा, सुनवाई के दायरे को बढ़ाना नहीं चाहते, चार मामले को लेकर चिंतित
- उत्तर प्रदेश दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ दर्ज हैं 20 मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ दायर 20 मामलों के बारे में स्थिति रिपोर्ट तलब करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह पीड़िता के परिवार और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के बीच चार मामलों को लेकर चिंतित है।

दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के वकील ने जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष कहा था कि पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं, अदालत को उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर स्थिति रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि वो इस मामले के दायरे को बढ़ाना और राज्य में उनके खिलाफ दायर अन्य मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है।

शीर्ष अदालत को इस मामले में पेश वकील ने बताया कि दिल्ली ट्रांसफर किए गए चार मामलों की यहां की एक विशेष अदालत में रोजना सुनवाई की जा रही है। इस मामले में अब 19 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में चार आपराधिक मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया था। इसमें 2017 का दुष्कर्म मामला, दुष्कर्म पीड़िता के पिता के खिलाफ शस्त्र कानून के तहत दर्ज फर्जी मामला, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला शामिल है। तीस हजारी अदालत में जिला जज धर्मेश शर्मा की अदालत में इन चारों मामलों पर रोजाना सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत ने 45 दिन के भीतर सुनवाई खत्म करने का निर्देश दिया है।

भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में महिला से दुष्कर्म का आरोप है। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। हाल ही में पीड़िता की कार का रायबरेली में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वह और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़िता की रिश्तेदार दो महिलाओं की हादसे में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता को दिल्ली के एम्स लाया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर अप्रैल, 2018 से ही जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता चाचा महेश सिंह को उत्तर प्रदेश की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया गया है।

खर्च बढ़ने के कारण बढ़ाया गया परीक्षा शुल्क : सीबीएसई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

10 वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने के मामले में दी सफाई

फाइल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने के मामले में सफाई दी है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सीबीएसई के कई खर्च बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। पिछले पांच साल में शुल्क नहीं बढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बोर्ड ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए करीब पांच हजार परीक्षा केंद्रों में 100 फीसद तक नए पांच हजार पर्यवेक्षकों और पांच हजार डिप्टी सेंटर सुपरिंटेंडेंट की नियुक्तियां की थीं। मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या भी 40 फीसद तक बढ़ाई गई, जिससे हम जल्द नतीजों की घोषणा कर सके। मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या एक लाख 25 हजार से बढ़ाते हुए 2 लाख 50 हजार तक की गई। इन्हें और अन्य हितधारकों को उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नतीजों को जल्द घोषित करने का आदेश दिया था। पेपर का खर्च, गोपनीय दस्तावेजों की प्रिंटिंग और उनका परिवहन व इन सबको रखने की जगह जैसी चीजों के खर्चे भी बढ़े। नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कई सॉफ्टवेयर तैयार किए गए, नई तकनीक की मदद ली गई। इन सब खर्चों के कारण परीक्षा शुल्क बढ़ाना पड़ा। अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि दोनों कक्षाओं के परीक्षा शुल्क को दोगुना ही बढ़ाया गया है। यह गलत सूचना है कि बोर्ड ने कई गुना परीक्षा शुल्क बढ़ाया है।

200 करोड़ रुपये का हुआ था घाटा : अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सीबीएसई एक स्वायत्त निकाय है। यह बोर्ड खुद से फंड जुटाता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हमें कई साल से वित्तीय घाटा हो रहा था। पिछले वित्त वर्ष 2018-2019 में 200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पहले बोर्ड घाटे को काबू करने के लिए दूसरे प्रोफेशनल कोर्स जैसे जेईई, नीट के शुल्क से इसे पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन इन प्रोफेशनल कोर्स के लिए परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दे दी है। अब बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) आयोजित करता है। ऐसे में बोर्ड को खर्चों को देखने के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ाना बेहद जरूरी था।

बोर्ड के अधीन 22 हजार स्कूल

देश भर में सीबीएसई के अधीन 22 हजार स्कूल हैं, जिसमें 16 हजार निजी और 6 हजार सरकारी स्कूल शामिल हैं। इनमें से दिल्ली के 1500 निजी स्कूल और एक हजार सरकारी स्कूल हैं। 2010 से लेकर 2019 तक सीबीएसई से संबद्ध 10 हजार स्कूल बढ़े। बोर्ड ने बीते कुछ वर्षों में छह नए रीजनल सेंटर भी स्थापित किए।

मानसरोवर यात्रियों की सुविधा के लिए भारत को कई कदम उठाने की जरूरत

नीलू रंजन, कैलास मानसरोवर

- चीन की ओर लिपुलेख दर्रे तक दो लेन की सड़क तैयार
- भारत में अभी 59 किलोमीटर तक करनी पड़ती है पैदल चढ़ाई

हिंदू तीर्थयात्रियों की आस्था के प्रतीक कैलास मानसरोवर तक जाने के दुरूह मार्ग पर भारत की ओर से काफी काम करना होगा। दरअसल दूसरी ओर चीन ने पक्की सड़क पहुंचाकर भारत के लिए चुनौती बढ़ा दी है। यात्रियों के लिए अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं के विकास के बाद चीन अब भारत से भी ऐसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की उम्मीद कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक तीर्थयात्री कैलास मानसरोवर का दर्शन कर सकें।

फिलहाल, चीन की तरफ लिपुलेख दर्रे के बिल्कुल करीब तक दो लेन की सड़क बनकर लगभग तैयार है। यहां तक यात्रियों को लेकर सीधी बस पहुंचती है। एक किलोमीटर से कम की चढ़ाई के बाद यात्री लिपुलेख तक पहुंच जाते हैं। वहीं भारत की ओर कैलास मानसरोवर के यात्री काठगोदाम से पिथौरागढ़ जिले के नजंग तक सड़क मार्ग से जाते हैं। नजंग से लिपुलेख तक 59 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। इसमें चार दिन लगते हैं। नजंग से मालपा, बूंदी तक पहला दिन, बूंदी से छियालेख, गर्ब्यांग, गुंजी तक दूसरा दिन, गुंजी से कालापानी तक तीसरा दिन और कालापानी से नाभिढांग लिपुलेख तक चौथे दिन की यात्रा पूरी होती है। समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर पैदल चढ़ाई में आने वाली मुश्किल को समझा जा सकता है।

यात्रा के दौरान सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले तिब्बत के प्रांत अली प्रीफेक्चर के डिप्टी कमिश्नर जी किंगमिन कहते हैं कि चीन अपनी तरफ से यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन बूथ लगाने के अलावा चीन सरकार अन्य जरूरतों को पूरा करने में लगी है। भारत को भी यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे ही प्रयास करने चाहिए।

आत्मसमर्पण...

अगरतला के समीप अंबासा में मंगलवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब के समक्ष नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा-सबीर देबबर्मा (एनएलएफटी-एसडी) के कैडर्स ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। केंद्र, त्रिपुरा सरकार और इस उग्रवादी संगठन के बीच शनिवार को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। जिसके तहत यह आत्मसमर्पण हुआ। प्रेट्र

दृश्य हटाकर व वैधानिक चेतावनी के साथ रिलीज होगी 'बटला हाउस'

जासं, नई दिल्ली : बटला हाउस मुठभेड़ पर बनी फिल्म 'बटला हाउस' को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ 15 अगस्त को रिलीज करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता व निर्देशक से कहा कि वह फिल्म के अंत में लगाए गए पुलिस अधिकारियों के फोटो हटाएं। साथ ही पीठ ने कहा कि एक अभियुक्त के दर्ज कराए जा रहे इकबालिया बयान व विस्फोटक बनाते हुए दिखाए दृश्य को भी फिल्म से हटाएं। इसके अलावा पीठ ने कहा कि फिल्म की शुरुआत में वैधानिक चेतावनी के रूप में लिखें कि इसका वास्तविक घटना से संबंध नहीं है। पीठ ने कहा कि फिल्म निर्माता घोषणा करें कि वह किसी भी विचार का समर्थन नहीं करता है। इसके साथ ही यह भी वैधानिक चेतावनी दें कि यह फिल्म कल्पना पर आधारित है और इससे किसी घटना का लेना देना नहीं है।

याचिकाकर्ता अरिज खान व शाहजाद अहमद की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बटला हाउस के एक फ्लैट में छापेमारी की थी, जोकि मुठभेड़ में तब्दील हो गई। इस बहुचर्चित घटनाक्रम पर यह फिल्म बनी है, जो 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए प्रस्तावित है।

अजीब दास्तां

भाई पुलिस में है जबकि बहन नक्सली, मुठभेड़ के दौरान भाई बोला- सरेंडर कर दे, इस बार राखी बंधवाएंगे, नहीं मानी बहन, फायरिंग करते जंगल में हो गई ओझल

मुठभेड़ में आमने-सामने आए भाई-बहन

नईदुनिया, सुकमा

अरसा पहले नक्सल संगठन के बहकावे में नक्सली बन गई बहन को भाई ने काफी दिन बाद देखा था। आमना-सामना हुआ भी तो मुठभेड़ में। 29 जुलाई का दिन था। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का बालकातोंग इलाका। दोनों ओर से चलती फायरिंग के दौरान भाई पुलिस के जवान के सामने पेड़ की आड़ लेकर फायरिंग करती नक्सली बहन थी। भाई के हाथ फिर भी नहीं कांपे। अलबत्ता, भाई ने आने वाले रक्षा बंधन की दुहाई देकर कहा- मान जा बहना। कर दे सरेंडर। इस बार राखी बंधवाएंगे। बहन नहीं मानी। फायरिंग करती हुई जंगलों में ही ओझल हो गई।

पुलिस पार्टी को खुफिया इनपुट मिला था कि जंगल में बड़ी तादाद में नक्सली एकत्र हैं। इसी आधार पर पुलिस पार्टी वहां पहुंची। पुलिस पार्टी के आने की खबर लगते ही नक्सली सतर्क हो गए और दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। पुलिस टीम में सहायक आरक्षक वेट्टी रामा गाइड के रूप में शामिल था। उससे उसके एक साथी ने मुठभेड़ के दौरान कहा कि वो देखो तुम्हारी बहन कन्नी नजर आई। वह हथियार थामे कन्नी के नजदीक तक पहुंच गया। भाई ने बहन को आवाज भी दी। दोनों के बीच महज दो सौ मीटर की दूरी थी, लेकिन वह वहां से फरार हो गई। दरअसल, भाई पुलिस की ओर से मैदाने जंग में उतरा था और दूसरी ओर नक्सल वर्दी में उसकी बहन नक्सलियों की ओर से लड़ रही थी।

भाई को भी ले गए थे नक्सली, लौट आया मुख्यधारा में : बचपन में वेट्टी रामा की बहन वेट्टी कन्नी ने भी उसकी कलाई पर राखी बांधी थी और उससे अपनी रक्षा का वचन लिया था। एक दिन ऐसा आया जब नक्सली इनके गांव में आए और भाई-बहन दोनों को अपने साथ ले गए। उन्हें नक्सल संगठन में बाल नक्सली के रूप में शामिल कर लिया गया। इसी संगठन में रह कर दोनों बड़े हुए और एक दिन वेट्टी रामा को महसूस हुआ कि नक्सलियों की विचारधारा पूरी तरह खोखली है। संगठन से उसका मोह भंग हो गया। करीब एक वर्ष पहले उसने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया। इसके बाद वेट्टी रामा को पुलिस विभाग में सहायक आरक्षक बना लिया गया। वेट्टी के हाथ में अब नक्सल उन्मूलन की जिम्मेदारी है।

> वेट्टी रामा मुठभेड़ में साथ था, जो पिछले साल नक्सल संगठन छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ा है। उस दिन की मुड़भेड़ में वेट्टी रामा की बहन वेट्टी कन्नी, जो नक्सली है वह भी वहां मौजूद थी। दोनों का वहां आमना-सामना हुआ था। फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उस मुड़भेड़ में नक्सली वेट्टी कन्नी बच निकली।
>
> **— शलभ सिन्हा, एसपी सुकमा**

> हम लोगों पर फायरिंग कर रहे नक्सलियों में मेरी बहन वेट्टी कन्नी भी शामिल थी। वहां मैंने बहन को देखा फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैंने पहले भी अपनी बहन से नक्सल संगठन छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने को कहा था, लेकिन उसने जवाब में मुझसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। रक्षा बंधन है फिर से बहन से अपील की, पर वह नहीं मानी।
>
> **— वेट्टी रामा, सहायक आरक्षक**

केदारनाथ में अन्नकूट महोत्सव आज

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग : बारह ज्योतिर्लिंग में शामिल विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व रात्रि से आयोजित होने वाले अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग पर लगाए गए पके हुए नए अन्न के लेप का श्रृंगार दर्शन करने की परंपरा है। इस बार महोत्सव बुधवार रात नौ बजे से शुरू होकर गुरुवार सुबह चार बजे तक चलेगा। इसके अलावा गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर समेत कई अन्य स्थानों पर भी इसी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट महोत्सव (भतूज) धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार यह तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। महोत्सव में सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केदार लिंग भगवान शिव के स्वयंभू लिंग की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। इसके पश्चात अनाज (झंगोरा, चावल, कौंणी आदि) का लेप लगाकर स्वयंभू लिंग का श्रृंगार किया जाएगा। श्रद्धालु सुबह चार बजे तक बाबा के इस अलौकिक रूप का दर्शन कर सकेंगे।

मॉरीशस में गूंजेगी राम की महिमा

रघुवरशरण, अयोध्या

20 को रवाना होगा 18 कलाकारों का दल

रामलीला वैश्विक स्तर पर परवान चढ़ रही है। इसी क्रम में 20 अगस्त को 18 सदस्यीय रामलीला मंडली अयोध्या शोध संस्थान से मॉरीशस के लिए रवाना हो रही है। यह दल 22 अगस्त को मॉरीशस पहुंचेगा। 29 अगस्त तक प्रवास के दौरान स्थानीय कलाकारों का दल रामायण सेंटर में रामलीला के विविध प्रसंगों की प्रस्तुति देगा।

आधुनिक शोध के मुताबिक, रामलीला का मंचन विश्व के 29 देशों में होता है। अयोध्या शोध संस्थान रामकथा की व्यापकता को नए सिरे से समीकृत कर रहा है। शोध संस्थान का प्रयास 2012 में फलीभूत हुआ, जब संस्थान के आमंत्रण पर पहली बार विदेशी कलाकारों का दल प्रस्तुति के लिए रामनगरी पहुंचा। यह त्रिनिडॉड, टोबैको एवं सूरीनाम के कलाकारों का दल था। 2012 के ही उत्तरार्ध में थाईलैंड के कलाकारों का दल रामलीला मंचन के लिए शोध संस्थान पहुंचा और इस सच्चाई को परिभाषित किया कि पूर्वी एशियाई देश में भी रामलीला की परंपरा विद्यमान है।

2014 में यदि थाईलैंड के कलाकारों का दल दूसरी बार रामलीला की प्रस्तुति के लिए रामनगरी पहुंचा तो इसी साल इंडोनेशिया और कंबोडिया का दल भी आया। इसी साल रामनगरी के कलाकार थाईलैंड गए और वहां रामलीला प्रस्तुति की छटा बिखेरी। 2016 में फिजी, न्यूजीलैंड और थाईलैंड के कलाकार रामलीला की प्रस्तुति के लिए अयोध्या आए।

2017 में 10 जुलाई से चार अगस्त तक रामलीला के स्थानीय कलाकारों ने त्रिनिडॉड, टोबैको, फिजी एवं सूरीनाम की यात्रा कर अपनी कला की छटा बिखेरी। इसी साल 18 अक्टूबर को दीपोत्सव में इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि के कलाकार आए। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य कहते हैं कि भगवान राम और सनातन धर्म अनादि हैं। कोई शक नहीं कि इस्लाम एवं ईसाइयत में विभाजित दुनिया से पूर्व राम पूरे विश्व की सांस्कृतिक एकता के महानायक थे।

2.60 लाख किलो चावल चोरी का मामला दर्ज किया है सीबीआइ ने। भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों और एक निजी कंपनी ने करीब 85 लाख रुपये के चावल की चोरी की। यह चावल असम से मणिपुर जाने थे।

विधि के पाठ्यक्रमों में अब अनुच्छेद-370 होगा इतिहास

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के फैसले के बाद अब संविधान में यह इतिहास हो गया है। अब अनुच्छेद का सिर्फ खंड-एक प्रभावी रहेगा। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है। ऐसे में विधि के विद्यार्थियों को बतौर इतिहास अनुच्छेद-370 पढ़ाया जाएगा।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व हरिश्चंद्र पीजी कालेज के विधि विभाग के अध्यापकों का कहना है कि अब अनुच्छेद-370 के खंड एक को छोड़ कर कोई खंड प्रभावी नहीं है। ऐसे में अब विधि में अनुच्छेद-370 के अन्य खंडों को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अनुच्छेद-370 को विधि के पाठ्यक्रमों में से हटाया नहीं जाएगा। इसे इतिहास के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब यह नहीं पढ़ाया जाएगा कि जम्मू-कश्मीर में रक्षा, विदेशी मामले व संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके स्थान पर यह पढ़ाया जाएगा कि देश के अन्य राज्यों की भांति जम्मू-कश्मीर में भी केंद्र सरकार के सभी कानून लागू होंगे। जम्मू-कश्मीर में दो झंडे की बात भी खत्म हो जाएगी।

रविदास समाज के बंद से ठहर गया पंजाब

बवाल ▶ पथराव के बाद हवाई फायरिंग, जबरन दुकानें बंद कराने पर प्रदर्शनकारियों से दुकानदारों की झड़प

दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली शताब्दी व शान-ए-पंजाब लुधियाना से लौटाई गई

जेएनएन, जालंधर

दक्षिणी दिल्ली में श्री गुरु रविदास जी का मंदिर कोर्ट के आदेश पर हटाए जाने पर उपजे विरोध में रविदास समाज के पंजाब बंद का कई शहरों में व्यापक असर दिखा। होशियारपुर में मुकेरियां कस्बे के गांव हरसेमानसर में बाजार बंद करने को लेकर प्रदर्शनकारी दुकानदारों से भिड़ गए। घटना में तीन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद दुकानदारों और गांववासियों ने एकत्र होकर जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने वालों पर हमला कर दिया।

प्रदर्शनकारी खुद भाग गए, लेकिन लोगों ने उनकी आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें तोड़ दीं। दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में लोग आमने-सामने हो गए और पथराव किया गया। पुलिस ने किसी तरह हवाई फायरिंग कर दोनों पक्षों को खदेड़ा। शाम तक गांव में तनाव का माहौल बना रहा। जालंधर में भी कुछ जगह मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। नवांशहर में भी दुकानदारों व प्रदर्शनकारियों में जबरन दुकानें बंद कराने को लेकर टकराव हो गया। होशियारपुर में कांग्रेस के झंडे को लेकर बसपा व कांग्रेस कार्यकर्ता उलझ गए।

गुरदासपुर में बटाला में मंगलवार को रविदास भाईचारे के बंद के दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ट्रेन रोककर प्रदर्शन करते हुए। जागरण

प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्रियों पर पथराव किया। गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी भी धरने पर बैठीं। जालंधर-लुधियाना, जालंधर-अमृतसर व फगवाड़ा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे शाम तक बंद रहे।

वहीं, रेल यातायात पर भी बंद का असर पड़ा। दिल्ली-अमृतसर शताब्दी और शान-ए-पंजाब को लुधियाना से ही लौटा दिया गया। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। दोपहर 12 बजे रवाना होने वाली शहीद एक्सप्रेस दोपहर 3.30 बजे रवाना की गई। अमृतसर से दिल्ली जाने वाले यात्री भी परेशान हुए। गुरदासपुर के बटाला में भी प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर-कादियां ट्रेन को आधे घंटे तक रोके रखा।

स्कूल कॉलेज रहे बंद

होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर, कपूरथला व लुधियाना में स्कूल व कॉलेज बंद रहे। कई जगह बैंक भी बंद रहे। जगह-जगह धरना-प्रदर्शन होने से बसें भी नहीं चलीं। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

भीम आर्मी के प्रवक्ता बोले, इंदिरा गांधी के हश्र को न भूले सरकार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

▶ फेसबुक लाइव पर पीएम मोदी का नाम लेते हुए दिया आपत्तिजनक बयान

▶ दिल्ली में संत रविदास मंदिर को हटाए जाने को लेकर दिया विवादित बयान

दिल्ली में कोर्ट के आदेश पर संत रविदास मंदिर हटाए जाने को लेकर भीम आर्मी के प्रवक्ता मंजीत नौटियाल ने आपत्तिजनक बयान दिया है।

उन्होंने फेसबुक लाइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए आपत्तिजनक भाषा में कहा कि यह सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हश्र को न भूले। अगर तोड़ी गई प्राचीन प्रतिमा 21 अगस्त तक फिर से स्थापित नहीं की तो वे मरने-मारने पर उतर आएंगे।

मंगलवार सुबह नौटियाल ने फेसबुक लाइव पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 600 साल पुराने संत रविदास मंदिर को तुड़वा डाला। न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि 21 अगस्त से पहले मामले का संज्ञान लेकर मूर्ति को फिर से उसी स्थान पर स्थापित कराया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। अगर हमारे संत, महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़कर भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो हम कटने-काटने को तैयार हो जाएंगे।

वीडियो का परीक्षण कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने दिया जाएगा। सहारनपुर के कप्तान को भी कहा गया कि वह मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें।
–प्रशांत कुमार, एडीजी जोन

मैंने यह वीडियो नहीं देखा है। एसएसपी को मामले की पड़ताल करने व आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
–उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीआइजी, सहारनपुर परिक्षेत्र

20 मिनट 10 सेकंड के इस लाइव वीडियो में नौटियाल ने भीमआर्मी से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें खून-खराबे के लिए भी उकसाया।

रविदास मंदिर हटाने पर राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र से हटाए गए गुरु रविदास मंदिर को लेकर राजनीति करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त चेतावनी दी। अदालत ने इस मुद्दे पर धरना और प्रदर्शन भड़काने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी। शीर्ष अदालत के आदेश पर ही इस मंदिर को हटाया गया था।

जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष गुरु रविदास जयंती समारोह समिति के वकील ने इस मुद्दे पर पंजाब में हो रहे आंदोलन का उल्लेख किया। इस पर पीठ ने कहा, 'यह मत समझिए कि हम अधिकारहीन हैं। हमें मामले की गंभीरता पता है।' पीठ ने समिति के वकील से कहा, 'एक शब्द मत बोलें और आग में घी डालने का काम न करें। आप अवमानना कर रहे हैं। हम आपके पूरे प्रबंधन को लपेट देंगे। हम देखेंगे कि क्या करना है।' पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया।

पीठ ने कहा कि वह शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले की आलोचना को बर्दास्त नहीं करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट है। यहां राजनीति ना करें। अदालत ने कहा कि एक बार आदेश पास हो जाता है तो इस तरह की गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता है। हम अवमानना की कार्यवाही शुरू करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील ने पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक ढांचे को हटा दिया गया है।

एसटीएफ की हिरासत में एएसआइ ने खुद को मारी गोली, मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर: हेरोइन तस्करी और जाली करंसी रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एएसआइ अवतार सिंह ने मंगलवार सुबह अमृतसर के माल मंडी स्थित एसटीएफ हवालात में खुद को गोली मार ली। इससे उसकी मौत हो गई। एसटीएफ और अमृतसर देहात पुलिस ने थाना घरिंडा में तैनात एएसआइ अवतार सिंह को एएसआइ जोरावर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था।

बताया गया है कि अवतार सिंह ने अपनी निगरानी में तैनात संतरी को दम घुटने की शिकायत कर पानी मांगा। जब संतरी अपनी एके-47 वहीं छोड़कर पानी लेने दूसरे कमरे में गया तो अवतार ने एके-47 उठाकर ट्रिगर दबा दिया। दो गोलियां उसके चेहरे पर लगीं और तीन गोलियां हवालात की दीवार पर जा लगीं। आवाज सुनकर एसटीएफ का स्टाफ हवालात की तरफ दौड़ा लेकिन तब तक अवतार सिंह की मौत हो चुकी थी।

अवतार सिंह और जोरावर सिंह को 15 ग्राम हेरोइन और दस हजार जाली करंसी के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों से 15590 भारतीय करंसी, दो लाइटर, दो कारें और एक सिल्वर पेपर का रोल बरामद हुआ था।

साढ़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से निकाला गया बाघ शावक

नईदुनिया, उमरिया/कटनी

▶ मप्र के कटनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र के पिपरिया कलां बीट की घटना

▶ बेहोश करने के बाद जाल से निकाला कुएं से बाहर

मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र के पिपरिया कलां बीट में कुएं में गिरे करीब 11 महीने के बाघ शावक को साढ़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। बचाव कार्य में 70 लोगों की टीम लगी। बाघ शावक को बेहोश करने के बाद जाल में भरकर बाहर निकाला गया।

बाघ शावक दो दिन पहले कुएं में गिरा था। हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों को मंगलवार सुबह पिपरिया कलां के कोटवार से इस बारे में सूचना मिली। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार शाम से ही बाघिन कुएं के आसपास मंडरा रही थी। उन्होंने सोमवार शाम को ही शावक को कुएं में देख लिया था, लेकिन डरकर किसी ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को नहीं दी थी।

पैरों और सिर में लगी चोट: रीवा के मुकुंदपुर से आए डॉ. राजेश सिंह ने शावक को बेहोश किया। बाघ शावक के पिछले पैरों और सिर में जख्म हैं, इसलिए उसे जंगल में छोड़ने के बजाय झिरिया नर्सरी ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुएं में गिरने के दौरान नीचे बड़े पत्थरों से टकराने के कारण उसे चोट लगी है। जख्म भरने के बाद शावक को जंगल में छोड़ा जाएगा।

कुएं में गिरा बाघ शावक। नईदुनिया

पत्नी को मायके से लाने के लिए युवक ने बस ही चुरा ली

जागरण संवाददाता, सोनीपत: एक युवक पत्नी को मायके से लाने के लिए रोडवेज की बस ही चोरी कर ससुराल चल पड़ा। काउंटर से बस गायब होने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाद में रोडवेज अधिकारियों को एक बस के पेड़ से टकराने की सूचना मिली तो अधिकारी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसमें चालक की सीट पर एक युवक फंसा हुआ मिला, जिसे क्रेन की मदद से निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

रोडवेज बस चालक नरेंद्र ने सोमवार रात को बस को जयपुर जाने के लिए काउंटर पर खड़ा दिया। बस को वहां खड़ी करके चालक नरेंद्र दूसरी बस लेने के लिए वर्कशॉप में चला गया। जब थोड़ी देर के बाद वह दूसरी बस को लेकर स्टैंड परिसर में आया तो वहां से बस नहीं थी। उसने मामले की सूचना यार्ड मास्टर रमेश कुमार और ड्यूटी क्लर्क रविंद्र कुमार को दी। मामले की सूचना अधिकारियों व गीता भवन चौकी पुलिस को दी गई। युवक ने बताया कि उसकी ससुराल रोहतक में है और उसकी पत्नी वहीं गई हुई थी। पत्नी को मायके से लाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो उसने बस चुरा ली।

आतंकी कमरुज्जमां के फरार साथियों की कुर्की की तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर

▶ एनआइए कोर्ट ने जारी किया कुर्की का नोटिस, टीम जाएगी किश्तवाड़

▶ सिद्धि विनायक मंदिर घंटाघर पर हमले की साजिश में पकड़ा गया था

हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी कमरुज्जमां के तीन फरार साथियों ओसामा बिन जावेद, जहांगीर सुरूरी और रियाज अहमद उर्फ हजारी के खिलाफ नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। गैरजमानती वारंट के बाद अब कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही एनआइए, सेना के साथ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जाकर कुर्की प्रक्रिया शुरू करेगी। कमरुज्जमां को पिछले साल सिद्धि विनायक मंदिर घंटाघर पर हमले की साजिश रचते एटीएस ने पकड़ा था।

पिछले साल 13 सितंबर को एटीएस ने चकेरी स्थित एक घर से असम निवासी कमरुज्जमां उर्फ कमरुद्दीन उर्फ डॉ. हुरैरा को पकड़ा था। जांच में पता लगा कि वह गणेश चतुर्थी पर हमले की योजना बना रहा था। घंटाघर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की रेकी कर मोबाइल फोन में साढ़े पांच मिनट की वीडियो क्लिप बनाई थी। साथ ही ब्लैकबेरी मैसेंजर से साथियों के संपर्क में था और जम्मू-कश्मीर से हथियार मंगाने वाला था। एनआइए ने जांच में पता चला कि कमरुज्जमां जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ निवासी हिजबुल आतंकी ओसामा बिन जावेद का साथी है। दोनों ने आतंकी कैंप में साथ ट्रेनिंग ली थी। ओसामा कानपुर में भी आकर रुका था। जांच के दौरान आतंकी साजिश में किश्तवाड़ निवासी ओसामा के साथ ही वहीं के जहांगीर सुरूरी व रियाज अहमद उर्फ हजारी का भी नाम सामने आया पर एनआइए किसी को भी ढूंढ़ नहीं सकी।

2017 में ओसामा से जुड़ा कमरुज्जमां: कमरुज्जमां अप्रैल 2017 में कश्मीर के किश्तवाड़ में ओसामा बिन जावेद के संपर्क में आया। दोनों ने एक साथ हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर नौ महीने ट्रेनिंग ली। इसके बाद जम्मू से कानपुर आए, तभी से जम्मू-कश्मीर की खुफिया एजेंसियां दोनों की तलाश में थीं। कमरुज्जमां तो पकड़ लिया गया पर ओसामा का पता नहीं लगा।

2016 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में आई 41 फीसद की कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में पराली (धान की फसल के अवशेष) जलाने की घटनाओं में 2016 के मुकाबले 41 फीसद की कमी आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक 1151 करोड़ की केंद्रीय योजनाओं की सहायता से यह संभव हो सका है। बता दें कि पराली का जलाया जाना वायु प्रदूषण का बड़ा माना जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र ने 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकारी और निजी प्रयासों के माध्यम से देश ने यह दिखा दिया कि इस तरह की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। उन्होंने एक बयान में कहा, ' पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में पराली के प्रबंधन के लिए चलाई गई केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। इन सभी राज्यों में सेटेलाइट के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2017 के मुकाबले जहां इन घटनाओं में 15 फीसद की कमी आई है, वहीं 2016 के मुकाबले 41 फीसद की कमी है।' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष पराली जलाने में और कमी आएगी।

जौमेटो ने कहा- मामला भोजन या धर्म से नहीं, रेट कार्ड में संशोधन से जुड़ा है

जेएनएन, कोलकाता : बंगाल के हावड़ा में अपने डिलीवरी स्टाफ की हड़ताल पर जोमैटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल ने कर्मचारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि यह मामला रेट कार्ड में हाल में किए गए संशोधन से जुड़ा है, भोजन अथवा धर्म से नहीं। इस मामले को जान-बूझकर गलत तरीके से पेश किया गया।

▶ डिलीवरी स्टाफ की हड़ताल पर कंपनी के सीईओ ने कर्मचारियों को लिखा पत्र

कंपनी के कर्मचारियों को लिखे इस पत्र में गोयल ने आगे कहा-'हमने हमारा आर्डर डेटाबेस देखा है। पिछले तीन महीने में उक्त इलाके में पोर्क के किसी फूड आइटम की डिलीवरी नहीं हुई है। बीफ के फूड आइटम का सिर्फ एक आर्डर किया गया था, उसे भी डिलीवरी से पहले रद कर दिया गया था। मामला रेट कार्ड में किए गए संशोधन को लेकर है। हम किसी शहर में शुरुआत करते वक्त हमारे डिलीवरी पार्टनर को प्रति आर्डर निर्धारित व स्थायी भुगतान करते हैं, जिससे उन्हें प्रति सप्ताह/महीने में निश्चित आय होती है। जैसे-जैसे हमारा आर्डर बढ़ता जाता है, डिलीवरी पार्टनर की आय भी बढ़ने लगती है इसलिए हम रेट कार्ड में संशोधन करते हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है। कभी-कभी कुछ डिलीवरी राइडर्स रेट कार्ड में संशोधन को समझ नहीं पाते और इस बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं।'

यह है मामला

हावड़ा में जोमैटो के डिलीवरी राइडर्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी उनसे ऐसे खाने की डिलीवरी करा रही है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू डिलीवरी स्टाफ की शिकायत है कि उनसे बीफ की डिलीवरी कराई जा रही है। मुस्लिम डिलीवरी स्टाफ की भी शिकायत है कि उनसे पोर्क कस्टमर तक पोर्क पहुंचाने को कहा जा रहा है।

सुषमा जी ने सख्त प्रोटोकॉल वाले विदेश मंत्रालय को जनता तक पहुंचाया : पीएम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्व विदेश मंत्री व भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को मंगलवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों ने अपने राजनीतिक करियर में सुषमा स्वराज जी के साथ बिताए पलों के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सख्त प्रोटोकॉल वाले विदेश मंत्रालय को भी सुषमा जी ने सरल बना दिया है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय मुसीबत में होता तो एक ट्वीट पर सुषमा जी उसे मदद पहुंचाती थीं। अब सुषमा जी द्वारा दी गई इस विरासत को हम संभाल लें, उसे आगे ले जाएं। समझिए यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। मोदी ने कहा कि जब वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र में बोलने गए थे तो सुषमा जी ने उनका लिखित भाषण तैयार करवाया था। वह दृढ़ता के साथ अपनी बात रखती थीं। मोदी ने कहा कि सुषमा की बेटी बांसुरी स्वराज में उनकी झलक दिखती है।

नई दिल्ली में मंगलवार को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की स्मृति में आयोजित सभा में उनके पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

पार्टी के लिए समर्पित थीं सुषमा : पीएम ने कहा कि सुषमा जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। उन्हें संगठन और सरकार में जो भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बड़े ही मन से काम किया। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। इसके बावजूद जब हमने उनसे कर्नाटक जाकर पार्टी के लिए काम करने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई थीं।

आज पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़ चलेगा चंद्रयान-2

बेंगलुरु, प्रेट्र : चांद के सफर पर निकला भारत का चंद्रयान-2 बुधवार को धरती की कक्षा छोड़कर चांद की ओर रवाना हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के दूसरे चंद्र अभियान को लांच किया था। तब से यह यान धरती की कक्षा में घूम रहा था।

बुधवार की सुबह करीब साढ़े तीन बजे वैज्ञानिकों द्वारा कक्षा में बदलाव के बाद यान चांद की ओर रवाना हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ट्रांस लुनार इंसर्शन (टीएलआइ) कहा जाता है। इसरो के अनुसार, 20 अगस्त को यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद चांद की अलग-अलग कक्षाओं में घूमते हुए सात सितंबर को चांद पर इसकी लैंडिंग होनी है। लांचिंग के बाद से इसरो अब तक पांच बार इसकी कक्षा में बदलाव कर चुका है। पांचवां बदलाव छह अगस्त को किया गया था।

22 जुलाई को इसरो के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 3 की मदद से चंद्रयान-2 को लांच किया गया था। लांचिंग के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट ने इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था। चंद्रयान-2 के तीन हिस्से हैं- ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान'। ऑर्बिटर सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद पर उतरेंगे। इनके प्रयोग की अवधि 14 दिन की रहेगी। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस हिस्से में उतरेंगे, जहां अब तक कोई यान नहीं पहुंचा है। चांद पर लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कर चुके हैं।

चांद के रहस्य जानने की दिशा में यह भारत का दूसरा अभियान है। 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 लांच किया था। यह ऑर्बिटर मिशन था। इसने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा की थी। चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है।

तैयारी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मंजूर की योजना, प्रथम चरण में 95 न्याय पंचायतों में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन, चयनित ग्राम में लगेगी कांपेक्टर मशीन, हरिद्वार में रिसाइकिलिंग प्लांट

प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे उत्तराखंड के गांव

केदार दत्त, देहरादून

पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड के गांव भी अब प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के कचरे से मुक्त हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायतीराज विभाग की इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजना में प्रथम चरण में 95 न्याय पंचायतों में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में प्लास्टिक- पॉलीथिन एकत्र करने के मद्देनजर कांपेक्टर मशीन लगेगी। इसके बाद कचरे को हरिद्वार के अलीपुर में लगने वाले रिसाइकिलिंग प्लांट में भेज जाएगा। प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने का जिम्मा महिला समूहों को दिया जाएगा और उनसे चार रुपये प्रति किलो की दर से इसे खरीदा जाएगा। ऐसे में गांव में आजीविका के साधन भी विकसित होंगे।

शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण इलाके भी प्लास्टिक-पॉलीथिन के कचरे से अछूते नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर फोकस किए जाने के बाद राज्य में भी हलचल हुई। राज्य के 92 नगर निकायों में इसकी व्यवस्था की गई है, जबकि अब ग्राम पंचायतों में यह मुहिम शुरू की जा रही है। इस कड़ी में पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर विभाग की ओर से मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया। इसे अब मंजूरी मिल गई है।

अपर सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गांव प्लास्टिक-पॉलीथिन के कचरे से मुक्त तो होंगे ही, यह आजीविका का साधन भी बनेगा। प्रथम चरण में राज्य की 670 न्याय पंचायतों में से 95 न्याय पंचायतों के एक-एक गांव को लिया जा रहा है। इन गांवों में पॉलीथिन- प्लास्टिक एकत्र करने के लिए शेड बनाने के साथ ही वहां कांपेक्टर मशीन लगाई जाएगी।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हरिद्वार के अलीपुर में रिसाइकिलिंग प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट में इससे पीवीसी पाइप, प्लास्टिक के दरवाजे जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

प्रतीकात्मक

छह माह में आकार लेगी मुहिम

अपर सचिव सेमवाल के मुताबिक यह मुहिम अब छह माह के भीतर आकार ले लेगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में लगने वाले रिसाइकिलिंग प्लांट पर 3.75 करोड़ की लागत आएगी, जिसे केंद्र वहन करेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में शेड निर्माण व कांपेक्टर मशीनें लगाने में 12.25 करोड़ की लागत आएगी। कांपेक्टर मशीनें केंद्र की मदद से लगेंगी। एक मशीन की लागत 5.50 लाख रुपये है। बाकी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

पायलट की सतर्कता से टली अनहोनी, 158 यात्री थे सवार

नागपुर, प्रेट्र : इंडिगो फ्लाइट के पायलट की सतर्कता से मंगलवार को एक बड़ी अनहोनी टल गई। विमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 158 यात्री सवार थे। विमान के इंजन को स्टार्ट करते ही पायलट की नजर चेतावनी संदेश पर पड़ गई, जिसके बाद विमान को उड़ान से हटा लिया गया।

▶ इंडिगो विमान को स्टार्ट करते समय चेतावनी संदेश आने के बाद उड़ान रद

▶ विमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे सवार

इंडिगो ने एक बयान में बताया कि पायलट 'क्षणिक चेतावनी संदेश' देखते ही विमान को आवश्यक जांच के लिए तुरंत बे में वापस लेकर चला गया। बे में जांच के दौरान दोबारा यह संदेश सामने आया। इसके बाद विमान को उड़ान से हटा लिया गया और नागपुर में ही उसकी मरम्मत की जा रही है। एयरलाइन ने कहा कि विमान में उड़ान भरते वक्त कोई गड़बड़ी नहीं आई थी। इंजन को स्टार्ट करते ही चेतावनी संदेश मिलने पर उचित संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इससे पहले, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट के वरिष्ठ निदेशक विजय मुलेकर ने कहा था कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमान दो बार कोशिशों के बावजूद उड़ान नहीं भर सका था। फ्लाइट संख्या 6ई-636 को सुबह 7.50 पर उड़ान भरना था और दिल्ली में सुबह 9.35 उसकी लैंडिंग थी। इस विमान के यात्रियों को दोपहर 1.54 बजे दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।

यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नितिन गडकरी इस विमान में सवार थे या नहीं। एयरलाइंस के अधिकारी ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उसने इतना कहा कि शायद गडकरी ने दूसरा विमान बुलाया था या किसी दूसरी उड़ान से चले गए। गडकरी के दफ्तर से यह तो बताया गया कि सुबह की फ्लाइट से उन्हें आना था, लेकिन वह दूसरी फ्लाइट से आये या कोई दूसरी फ्लाइट पकड़े इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

राजद्रोह में आरोपित जीतू फौजी समेत सात की जमानत मंजूर

बुलंदशहर हिंसा : जागरण संवाददाता, बुलंदशहर : उप्र के बुलंदशहर में हुई हिंसा मामले में जीतू फौजी समेत सात आरोपितों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद्रोह की धारा में भी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले उक्त आरोपितों को हाई कोर्ट से बवाल की धाराओं में भी जमानत मिल चुकी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि शासन की अनुमति के बाद सीजेएम ने जेल गए सभी आरोपितों पर राजद्रोह की धारा 124 (ए) भी लगा दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने बताया कि जीतू फौजी उर्फ जीतेंद्र मलिक आदि आरोपितों को बलवा आदि की धाराओं में हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने जीतू फौजी, सचिन, सौरभ व छोटू, हेमू, कलुवा व रोहित राघव की राजद्रोह की धारा में भी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। तीन दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने पर चिंगरावठी चौकी के पास खूनी बवाल हुआ था।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

समय का महत्व समझने से ही जीवन सार्थक बनता है

पाबंदियों पर सही रुख

सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि इस राज्य के हालात संवेदनशील हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी और याचिकाकर्ता को लगाई गई फटकार से उन लोगों को जवाब मिल जाना चाहिए जो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हालात नियंत्रण में रखने के लिए लगाई गईं तमाम पाबंदियों को गलत ठहरा रहे हैं। यदि कोर्ट को यह कहना पड़ा कि याचिकाकर्ता को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है तो फिर यह अपने आप साफ है कि प्रतिबंध हटाए जाने की मांग कितनी अतार्किक है। बेहतर हो कि इन पाबंदियों से असुविधा महसूस कर रहे लोग यह समझें कि ये खुद उनकी और राज्य के अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। मौजूदा हालात में सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों को एक झटके में वापस नहीं लिया जा सकता। कश्मीर के मामले में तो यह और अधिक आवश्यक है कि सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू-कश्मीर में ऐसे तत्वों को कोई मौका नहीं दिया जा सकता जो भारत को हजार घाव देने के मंसूबे पाले हुए हैं और किसी भी समय कोई बड़ी आतंकी घटना अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका उद्देश्य ऐसे ही तत्वों के मंसूबों को नाकाम करना है।

केंद्र सरकार का फैसला जम्मू-कश्मीर को एक नए युग में ले जाने के लिए कड़वी औषधि की तरह है। इसका असर होने में वक्त भी लगेगा और कुछ तकलीफें भी होंगी। इन तकलीफों को सहने के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। अब जब राज्य प्रशासन की ओर से यह बताया गया है कि हालात की समीक्षा करते हुए पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है तब उचित यही है कि सरकार को अपना काम करने दिया जाए। वैसे भी यह कोई पहला अवसर नहीं है जब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आम जनता के आवागमन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं पर पाबंदियां लगाई गई हों। बेहतर हो कि जम्मू-कश्मीर की जनता सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के इस संकल्प पर गौर करे जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना स्थानीय लोगों के साथ वैसे ही मिलकर रहेगी जैसे वह 30-40 साल पहले रहती थी। रावत के इस कथन का संदेश साफ है कि आतंकवाद के कारण सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेना और आम जनता के बीच यदि कोई दूरी बन भी गई थी तो वह अब समाप्त होने वाली है।

बदलाव पर विचार

34 वर्षों तक लगातार शासन करने वाली माकपा आज बंगाल में अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वाममोर्चा अन्य घटक दलों को साथ लेकर लड़ने के बावजूद इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अपने दम पर चुनाव लड़ना भी मुश्किल है। इस विकट परिस्थिति में पश्चिम बंगाल में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के दो महीने बाद माकपा राज्य के लोगों तक खास संदेश देने के लिए अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी के सभी स्तरों पर अपने पुराने दिग्गज नेताओं की जगह पर नए चेहरे को मौका देने पर विचार कर रही है। 1977 से लगातार 34 वर्षों तक बंगाल पर शासन करने वाली माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा को 2019 के चुनाव में एक भी सीट हाथ नहीं लगी। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 40 पर तो पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वाम दल को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की राजनीति में उभरी भाजपा से कड़ी चुनौतियां मिल रही है। मई में आए चुनाव परिणाम के बाद से वामदल ने राज्य समिति की दो बैठकें आयोजित की हैं। चुनाव नतीजे में साफ तौर पर दिख गया कि राज्य में पार्टी की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है। बैठकों में पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संगठनात्मक परिवर्तन न केवल जमीनी स्तर और मध्य स्तरों पर, बल्कि मतदाताओं को 'एक संदेश भेजने' के लिए शीर्ष स्तर पर भी होना चाहिए। वाम दल सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य हन्नान मोल्लाह का कहना है, 'पार्टी एक असाधारण स्थिति से गुजर रही है और इस स्थिति में असाधारण उपायों की जरूरत है। इससे पहले हमारे सामने केवल तृणमूल थी। अब हम तृणमूल और भाजपा की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।' परंतु, यहां सबसे बड़ा सवाल माकपा के लिए यह कि आखिर युवा नेता लाएंगे कहां से? माकपा की युवा एवं छात्र शाखा डीवाईएफआइ हो या फिर एसएफआइ आज दयनीय स्थिति में है। आज के युवाओं को माकपा की घीसीपीटी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि वामपंथी दलों ने कन्हैया जैसे कुछ युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनकी जो सोच व विचारधारा है उसे लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में माकपा के लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि पिछले एक दशक से बंगाल ही नहीं पूरे देश की राजनीति काफी बदल चुकी है।

संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा दांव

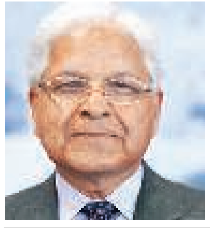

अश्विनी कुमार

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के निर्णय पर लोकप्रिय राष्ट्रीय धारणा नि :संदेह इसके पक्ष में है, लेकिन इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधानिकता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं

मोदी-शाह की जोड़ी ने एक बड़ा दांव खेला है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 समाप्त करते हुए राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया है। सरकार ने कश्मीरी लोगों के लिए शांतिपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य का वादा करते हुए यह कदम उठाया। अब यह इतिहास ही तय करेगा कि सरकार ने जो हिम्मत दिखाई है, क्या वह वक्त से पहले उठाया गया कदम मानी जाएगी या फिर उसे इस तरह याद किया जाएगा कि ऐसे फैसले का समय आ गया था। चूंकि यह निर्णय देश को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखा गया तो निःसंदेह लोकप्रिय राष्ट्रीय धारणा इसके पक्ष में है, लेकिन इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है जो कदम मुख्य रूप से राजनीतिक लिहाज से उठाया गया प्रतीत होता है।

संवैधानिक दृष्टि से देखें तो याचिकाकर्ता सहित इसके आलोचकों को लगता है कि सरकार का यह कदम देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। वे महसूस करते हैं कि यह विलय की संधि में कश्मीरियों के साथ किए गए वादे का शर्मनाक तरीके से किया उल्लंघन है। वे इस कदम को 'संवैधानिक विरूपता' की संज्ञा भी दे रहे हैं। बहस हो रही है कि अनुच्छेद 370 की धारा तीन को संवैधानिक गारंटी के मूल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी कोई भी व्याख्या कानूनी तौर पर असंभव है। आलोचकों की दलील है कि चूंकि संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है तो इस स्थिति में वह किसी केंद्रशासित प्रदेश को अवश्य पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकता है, लेकिन एक संप्रभु शक्ति के रूप में उसने कभी किसी प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म नहीं किया। केंद्र सरकार के एकतरफा निर्णय के खिलाफ मुख्य कानूनी आपत्ति यही है कि इसमें राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सहमति नहीं ली गई है जो कि मूल संवैधानिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। नवगठित केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा के दायरे को सीमित करना 'एक बड़े तबके को पूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी के अधिकार से वंचित करने' के रूप में देखा जा रहा है। यहां बहुसंख्यक भावनाएं भुनाने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया। यह कार्यकारी शक्ति के अतिक्रमण के विरुद्ध पूरक संवैधानिक संरक्षण की अवहेलना के क्रम में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

वहीं इसके पक्ष में भी उतनी ही मजबूती से तर्क दिए जा रहे हैं। इस पर संसदीय हस्तक्षेप में गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता का सिद्धांत और राज्य में शांति एवं तरक्की की उम्मीद का हवाला दिया। वहीं केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों से कश्मीरियों को भी अन्य नागरिकों की तरह विकास के पूरे लाभ मिलेंगे। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित होगा। यह दावा भी किया गया कि बीते सात दशकों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो विशेष दर्जा और खास अधिकार मिले थे उनसे मकसद हासिल नहीं हुआ और ऐसे में कश्मीरियों के लिए समय आ गया है कि वे राज्य में शांति और स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक नई राष्ट्रीय कड़ी से जुड़ें। इस दृष्टि से फैसले को मूल संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप पेश किया जा रहा है।

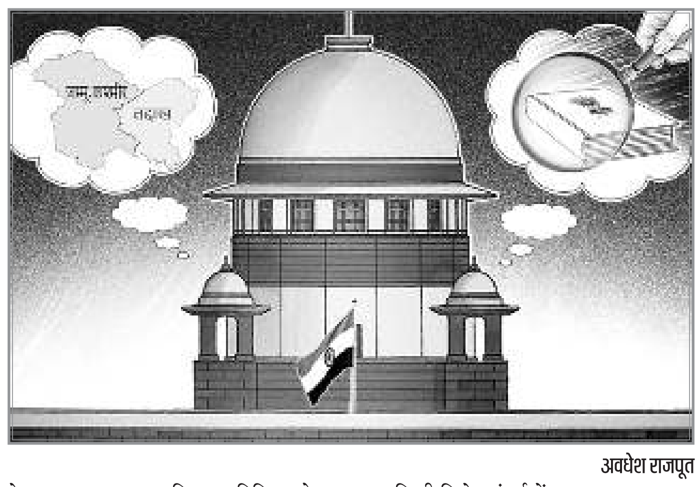

अवधेश राजपूत

सरकार की बुनियादी दलील है कि संविधान को किसी कालखंड के दायरे में समेटकर नहीं रखा जा सकता। राष्ट्र और लोकतंत्र समकालीन स्थितियों के संदर्भों में विकसित होते हैं। एक स्थिर समाज का विकास अपने अंतर्निहित प्रभावों से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की बेड़ियों से मुक्त होकर अपने अनुभवों के आधार पर नए रास्ते तलाशने चाहिए। सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान है, जिसका उपयोग एवं प्रासंगिकता पर निर्णय करने का अधिकार सरकार के पास है कि वह किसी विशेष संदर्भ में इसका आकलन कर सकती है। केंद्र सरकार शायद इसमें अदालत के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती देते हुए दलील दे कि एक चुनी हुई सरकार को भारत की एकता और कश्मीरी लोगों की प्रगति को ध्यान में रखकर एक नीति आधारित राजनीतिक निर्णय करने का अधिकार है। इस लिहाज से यह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता और यह 'न्यायिक शासनीय मानदंडों' के दायरे में नहीं आता। अदालत को आगाह किया जाएगा कि वह किसी 'राजनीतिक झंझावात' में न पड़े। इस विषय पर संवैधानिक नीतिशास्त्र की भी दुहाई दी जाएगी और स्मरण कराया जाएगा कि संवैधानिक गारंटी स्थिर नहीं होती और यह समय के अनुसार बदलती रहती है। अपने निर्णय के समर्थन में सरकार आवश्यकता के सिद्धांत का हवाला भी दे सकती है कि अतीत में भी अनुच्छेद 370 को लेकर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जा चुकी हैं।

इसमें न तो कोई बुद्धिमानी है और न ही यह संभव है कि इस मामले में अदालती रुख के आकलन का जोखिम लिया जाए। हालांकि राजनीतिक संदर्भों को देखते हुए यह कड़ी परीक्षा अवश्य होगी। मौजूदा राष्ट्रीय मिजाज को देखते हुए संविधान की व्याख्या में 'मूलवाद (ओरिजिनलिज्म) की ऐतिहासिक अस्वीकार्यता' बड़ी लुभावनी प्रतीत होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक सक्रियता दिखाई है, उसमें मामले को नकारने की गुंजाइश नहीं है। जैसे समाज में बदलाव जीवन का नियम है, वैसे ही समाज में आ रहे बदलावों पर प्रतिक्रिया भी कानूनी जीवन का हिस्सा है। वास्तव में न्यायिक समीक्षा की विस्तृत शक्ति स्वयं ही इस सिद्धांत पर संचालित होती है कि किसी संविधान को नए प्रारूप में सार्थकता देनी होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिर न्यायिक व्याख्या द्वारा संविधान की भावना को धता बताने के खतरे को लेकर आगाह किया है।

फिर भी कानूनी चुनौतियों के परिणामों के लिहाज से स्पष्ट है कश्मीर को लेकर विरोधाभासी विमर्श की निर्णायक लड़ाई अदालती कक्षों या लुटियंस दिल्ली की बैठकों में और कश्मीर की सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी। कश्मीर में शांति और समृद्धि की लड़ाई में हार-जीत का फैसला इसी से तय होगा कि भारतीय लोग अपने दिल और दिमाग में क्या रखते हैं। कश्मीर की नियति राजनीतिक विमर्श में अपने यही अर्थ प्रस्तुत करती है कि देश केवल रोटी के सहारे ही जिंदा नहीं रहते। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह कश्मीरी लोगों की पहचान और गरिमा का सम्मान करते हुए उनमें स्वैच्छिक देशभक्ति का जज्बा जगाने में सफल हो। उम्मीद है कि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के आश्वस्तकारी बयान से जुड़ी योजना जल्द ही मूर्त रूप लेगी। इससे ही भारत की 'सभ्य' देश वाली छवि मुखरित होगी, जो उसके मूल्यों से 'सॉफ्ट पावर' में परिलक्षित होती है।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

गांधीवाद की ओर लौटने की दरकार

एक दिन बाद हम आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे। इस अवसर पर स्वत्रंतता दिलाने वाले सेनानियों का स्मरण भी स्वाभाविक रूप से किया जाएगा। यह भी एक संयोग है कि इस वर्ष दो अक्टूबर को आजादी के सबसे बड़े नायक माने जाने वाले महात्मा गांधी के जन्म के 150 वर्ष पूरे होंगे। इस उपलक्ष्य में अनेक संस्थाओं ने गांधी के समय के मूल्यों, स्वतंत्रता के बाद के भारत की संकल्पनाओं के साकार होने की स्थिति तथा देश में जनतंत्र के स्वरूप पर विचार-विमर्श आयोजित किए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की ओर से उन्हें स्वच्छ भारत की सौगात देने का संकल्प लिया था। पहले तो सुनकर लोगों को अचंभा हुआ, मगर धीरे-धीरे स्वच्छता के महत्व को समझा गया। बड़े उत्साह से शौचालयों के निर्माण का कार्य सारे देश में हुआ। आज 27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हैं और 98.6 प्रतिशत परिवारों को शौचालय उपलब्ध हैं। स्वच्छता महात्मा गांधी को अत्यंत प्रिय थी। वह इस सौगात से प्रसन्न अवश्य होते, लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ करना शेष है।

नरेंद्र मोदी की कर्मठता और जीवन शैली का प्रभाव प्रशासन के अंतिम छोर तक तो पहुंचा है और उसके परिणामस्वरूप शौचालय केवल कागजों पर नहीं बने हैं, मगर उनके निर्माण में जो गुणवत्ता-स्तर अपेक्षित था, उसमें कमी रही होगी। अब लोग सरकारी धन के अपव्यय को देखकर शिकायत नहीं करते। उसे सामान्य मान चुके हैं। यह चिंता का विषय है। महात्मा गांधी के जीवनकाल में ही उनके आदर्श देश भर में पहुंच चुके थे। उस समय यदि ऐसे किसी कार्य में थोड़ा भी क्षरण होता तो लोग सशक्त विरोध करते। यदि वे जीवन मूल्य तिरोहित न हो गए होते तो संभवतः स्वच्छ भारत की संकल्पना इन वर्षों में सही स्वरूप ले चुकी होती, जिस पर समूचा विश्व आश्चर्य करता। स्वच्छता आवश्यक है, मगर और भी बहुत कुछ फिर से पाना है। आज भी देश में तमाम लोग राष्ट्र के कार्य में इस आशा के साथ जुटे हुए हैं कि यह देश महात्मा गांधी के मूल्यों से स्वयं को कभी अलग नहीं कर पाएगा। नरेंद्र मोदी की स्वच्छता-सोच उसी का एक उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने वाले लोग भी हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी संख्या कैसे बढ़े, उनका विश्वास कैसे बढ़े और इनकी ओर अधिकाधिक लोग कैसे आकर्षित हों, इस पर भी आज चर्चा होनी चाहिए।

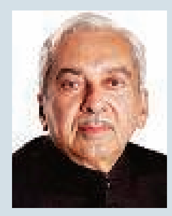

जगमोहन सिंह राजपूत

महात्मा गांधी के मूल्यों को भुलाने से ही अपरिग्रह की संस्कृति आज संग्रह की धारा बनकर क्षति पहुंचा रही है

भारतीय प्रशासनिक सेवा के नामचीन अधिकारी रहे महेश नीलकंठ बुच का प्रकाशित संकलन वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के कारणों का एक अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ उन संभावनाओं को भी चिन्हित करता है जो राष्ट्र-निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यों को पुनः जागृत कर सकती हैं, जिनके आधार पर देश स्वतंत्र हो पाया था। अपनी कर्मठता, लगनशीलता तथा सिद्धांतपरकता के लिए सदा सराहे गए 'एमएन बुच' ने आठ साल पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली थी, क्योंकि वह राजनीतिक दबाव में अपने नैतिक मूल्यों से हटने को तैयार नहीं थे! दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमुख पद पर रहते हुए 1978 में उन्होंने पाया कि 92 प्रतिशत आवंटन विवेकाधीन/तरजीही कोटे में आते हैं। इसमें सामान्य व्यक्ति के लिए केवल आठ प्रतिशत बचता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलकर वह इसमें संशोधन कराने में सफल हुए। जैसा अपेक्षित था, व्यवस्था में लोग नाखुश हुए। उन्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा! बुच के लेखों में कुछ ऐसे प्रकरणों की चर्चा है जो आज भी लोगों के अंतर्मन को झकझोर सकने की क्षमता रखते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि महात्मा गांधी के समय के मूल्य किस अनुपात में तिरोहित हो चुके हैं और इसके दुष्परिणाम सामान्य व्यक्ति पर कैसे पड़ रहे हैं।

केंद्र सरकार में मंत्री तथा असम के राज्यपाल रहे स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रकाश महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे, देश के हर बड़े नेता के साथ उन्होंने कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन उनकी पोती ने उन्हें उदास देखकर कारण पूछा। उन्हें बंबई से मद्रास जाना था, मगर रेल का टिकट उपलब्ध नहीं था। उनकी पोती ने उन्हें टिकट लाकर दिया! दादा जी के पूछने पर उसने बताया कि किसी एजेंट को पचास रुपये अलग से दिए थे, काम हो गया! दादा जी ने टिकट स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि वह गांधी के देश में पैदा हुए हैं, वे ऐसे टिकट पर यात्रा कैसे कर सकते हैं? उनकी पोती नें कहा कि मैं भी गांधी के देश में ही पैदा हुई हूं! इस पर जो उत्तर उसे मिला वह किसी के भी सामने पूरा परिदृश्य खोल कर रख देता हैः 'बेटी, मेरे गांधी थे मोहनदास करमचंद गांधी और तुम्हारी गांधी हैं इंदिरा गांधी!' महेश बुच ने 1967 के बाद आए परिवर्तन का बड़ा ही सटीक वर्णन अन्य कई प्रकरणों में भी किया है। मंत्री के स्तर पर मानवीय संवेदनाओं से युक्त कर्तव्यनिष्ठ आचरण की एक घटना अत्यंत मर्मस्पर्शी है। काका साहेब गाडगील पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे। वह महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं के निकट सहयोगी रहे थे। एक बार बंबई दौरे पर उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के कुछ कार्यों का निरीक्षण किया। उस विभाग के मुख्य अधिकारी नें उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपने सचिव से कहा कि चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया था। इस अधिकारी के आचरण और ईमानदारी की जांच की जाए! उनके सजग सहयोगी ने बताया कि वे थालियां तो एक अतिथि गृह से मंगाई गई थीं, और ऐसा उन पर मुद्रित था। काका साहेब को लगा कि उन्होंने गलत अनुमान के आधार पर उस अधिकारी के बारे में धारण बनाई। इस गलती के प्रायश्चित के लिए काका साहेब ने उसी समय उस अधिकारी के घर जाकर उनसे क्षमा मांगी।

आज राजनीति के पटल पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुछ नामों की चर्चा अवश्य होती है कि कहां से चले थे, कहां तक पहुंच गए! जाहिर है महात्मा गांधी को भुलाने से ही अपरिग्रह की संस्कृति संग्रह की धारा बन गई है! साफ है कि महात्मा गांधी को भुलाकर पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। भारत में गांधी जी के द्वारा अपनाए गए शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना ही विकल्प है।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मानव जीवन

मानव जीवन प्राप्त होना इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट उपहार है। मानव जीवन प्राप्त होने का आशय है आनंद का द्वार खुलना। हमारे ऋषियों ने इस मानव जीवन को मोक्ष रूपी मंदिर का प्रवेश द्वार माना है। यही स्वर्णिम काल है जिसमें मनुष्य भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। मनुष्य योनि आत्म कल्याण करने का सबसे उत्तम साधन है। पुण्य कर्म संपादित करके नूतन पथ तैयार करने का अवसर इसी मानव जीवन में उपलब्ध होता है। मनुष्य जीवन साधना, उपासना के माध्यम से आत्म तत्व का साक्षात्कार करने की स्वर्णिम वेला है। सद् ग्रंथों के उपदेशों तथा उच्च कोटि के साधकों के मार्गदर्शन में इस मानव जीवन में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धियों को अर्जित किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर पर पड़े जन्म जन्मांतरों के संस्कारों तथा तामसिक वृत्तियों को आध्यात्मिक साधना के माध्यम से दूर करने का पावन अवसर इसी जीवन में प्राप्त होता है। इस दृश्य जगत में रहते हुए निःस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन को आनंदमय बनाना मनुष्य के हाथ में है।

यह जीवन दुखों से निवृत्ति के लिए प्राप्त हुआ है। इस जीवन में यदि मनुष्य दुखी, चिंताग्रस्त होकर अज्ञानी बनकर अपना समय व्यतीत कर देता है तो यह उसका दुर्भाग्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक शक्ति रूपी आभूषण से अलंकृत करके इस संसार में भेजा है। मनुष्य को प्रतिपल आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे स्वयं की चिकित्सा कहा गया है। मन, वाणी, शरीर से कभी भी पाप कर्म न हो इसलिए सदैव सजग रहें। इस बहुमूल्य धरोहर को प्राप्त करके मनुष्य को अपने जीवन में उल्लास, आनंद एवं समृद्धि का संचार करना चाहिए। भौतिक संपत्ति के साथ-साथ आध्यात्मिक संपत्ति अर्थात पुण्य कर्मों का संचय भी अवश्य करना चाहिए। भौतिक धन से तो केवल इस संसार की यात्रा सुखद बनती है, परंतु आध्यात्मिक धन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

कम हो रही है खेती योग्य जमीन

मंजूषा

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी समिति यानी आइपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन और भूमि संबंधी अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें कई चिंताजनक तथ्य उभरकर सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में 23 प्रतिशत खेती करने योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। वहीं भारत में 30 प्रतिशत भूमि अब कृषि योग्य नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया लगातार जारी है। दरअसल जब किन्हीं प्राकृतिक कारणों या फिर इंसानी गतिविधियों की वजह से उस क्षेत्र विशेष की भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाने को भू-क्षरण कहते हैं। ऐसी जमीन में खेती करना संभव नहीं होता। यह अपनी तरह की पहली ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें इस तरह की हकीकत बयां की गई है। इससे पहले इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बता चुका है कि भारत के कुल भू-क्षेत्र का करीब 30 प्रतिशत भाग उपजाऊ लायक नहीं रहा यानी इतना हिस्सा रेगिस्तान या मरुभूमि में तब्दील हो चुका है।

दुनिया में 23 प्रतिशत खेती योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। वहीं भारत में 30 प्रतिशत भूमि अब कृषि योग्य नहीं रह गई है

अब तक जिन इलाकों में भू-जल खत्म हो जाता है या फिर जहां पानी की मौजूदगी नहीं होती उन्हें मरु भूमि घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि जल के अभाव में वहां किसी तरह की खेतीबारी नहीं हो पाती है। लेकिन हाल के दिनों में भू-क्षरण की एक बड़ी वजह शहरीकरण भी बन कर उभरी है। चूंकि शहरीकरण के चलते नए नए सड़कों, पुलों, उद्योग धंधों, आवासीय कॉलोनियों और रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण खेती योग्य जमीने तेजी से खत्म हो रही हैं। इसके अलावा तीव्र जलवायु परिवर्तन, वन क्षेत्र का लगातार कम होने और कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग के चलते भी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई है। भू-क्षरण के इन कारणों पर अभी दुनिया का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया है। लिहाजा इस समस्या के निवारण पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हो पा रही है।

यह समस्या इस वजह से भी विकराल होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसके कारण विभिन्न उपभोग की वस्तुओं की पैदावार में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही जो खाद्य पदार्थ पैदा हो रहे हैं उनमें पोषक तत्वों भी कम होते जा रहे हैं। जाहिर है इससे हमारी खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। पैदावार में गिरावट की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। वर्ष 2050 तक खाद्य वस्तुओं की कीमतें 23 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।

हालांकि आइपीसीसी ने इस गंभीर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। मसलन उसने जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने के साथ-साथ खेती के तौर-तरीकों में बदलाव करने, शाकाहार को बढ़ावा देने और जमीन का सोच-समझकर इस्तेमाल करने का अहम सुझाव दिया है। जाहिर है यदि हमें समय रहते इस समस्या से निजात पाना है तो हमें अपनी विकास की दिशा बदलनी होगी, क्योंकि विकास की हमारी मौजूदा प्रक्रिया हमें विनाश की ओर ले जा रही है। इसमें प्रकृति को हमें अपना साथी बनाना होगा। इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा और जमीन की गुणवत्ता बरकरार रहेगी।

(लेखिका शिक्षिका हैं)

बदले हालात में कश्मीर को संवारना जरूरी

कश्मीरियों से सच्चे संवाद की जरूरत शीर्षक से लिखे अपने लेख में शंकर शरण ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अस्थायी अनुच्छेद-370 और 35-ए के खात्मे के बाद कश्मीरियों से जिस सार्थक संवाद की जरूरत पर बल दिया है, वह उचित है। वस्तुतः बदले हालात में अब केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को संवारने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसके प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कश्मीर को संवारने की जैसी प्रतिबद्धता जताई है, वह गौर करने लायक है। ऐसे में कश्मीरी मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि कश्मीर में उनके बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों और सिखों का भी कश्मीर पर बराबर का हक है। देश की उस पंथनिरपेक्ष पहचान को शेष भारत की तरह कश्मीर में भी बनाए रखने की जरूरत है, जिसे कश्मीर की झूठी आजादी की ओट में पाक पोषित आतंकवादी और अलगाववादी पिछले तीन दशकों से छिन्न-भिन्न करने की कोशिश में लगे हुए थे। आतंक पीड़ित अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों और सिखों का सामूहिक नरसंहार इनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा था, जिसे मोदी शासन में नाकाम कर दिया गया। मोदी सरकार ने ही कश्मीरियों सहित अन्य देशवासियों को इस बात की अनुभूति कराई कि कश्मीर संप्रभु भारत राष्ट्र का एक हिस्सा है जो अब संवैधानिक रूप से केंद्र शासित है। इस दृष्टि से बदलते परिवेश में 1990 से पहले की महकती कश्मीरियत को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी अब वहां के उन स्थानीय नागरिकों की भी है जो अभी तक अलगाववादियों और आतंकवादियों के बहकावे में आकर अपनी रक्षक भारतीय सेना पर ही पत्थर बरसाते रहे हैं। निःसंदेह यह काम आपसी संवाद से ही संभव है, जिसकी पहल भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। आतंकवाद की कोख मानी जाने वाली कश्मीर घाटी की वह युवा शक्ति जो अभी तक शेष भारत से कटी रही, उसे अपनी दक्षता से बदलते कश्मीर को संवारना होगा। इसके लिए भारत और उसकी भारतीयता से कटने की नहीं अपितु जुड़ने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

चिदंबरम का बचकाना बयान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 पर अपना बयान देते हुए इसे हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ने की कोशिश की। यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले भी उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर लोकतंत्र की हत्या होने वाला बयान दिया था, जिसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा हुई थी। चिदंबरम जैसे नेताओं के बयानों को ना तो सरकार को और ना ही मीडिया को महत्व देना चाहिए। ऐसे नेताओं के कारण ही दुश्मन देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का मौका मिल जाता है। पी चिदंबरम जैसे नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ऐसे नेताओं के कारण ही शायद कांग्रेस खत्म हो रही है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

दोहरे चरित्र वाला पाकिस्तान

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान उनके मंत्री और नोबल पुरस्कार विजेता मलाल युसुफजई का जम्मू-कश्मीर में रह रहे मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। काश यही प्रेम पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के प्रति भी उमड़ता तो लोग यही कहते कि पाकिस्तान के लोगों का नजरिया एक है। लेकिन जब देखने का नजरिया दोहरे स्तर का हो तो सवाल उठना लाजिमी है। पाक में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ वहां की सेना और प्रशासन जिस तरह का व्यवहार करता है, वह बेहद दुखद है। लेकिन सेना के खिलाफ न तो इमरान खान और न ही मलाला की जुबान खुलती है। कम से कम अपने यहां हो रही ज्यादती पर भी उन्हें चिता करनी चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

महंगी शिक्षा का हो मूल्यांकन

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुल्क प्रत्येक विषय पर 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया हैं। पहले विद्यार्थियों के कुल विषयों का व्यय 750 रुपये था, लेकिन अब उन्हें 1500 रुपये कुल व्यय करने पड़ेंगे। अभिभावकों को पहले ही शुल्क अदा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। सरकार को इस विषय का मूल्यांकन करना चाहिए।

विनीत, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

35 अरब पेड़ बचे हैं भारत में पत्रिका नेचर की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार। वहीं रूस में 641 अरब, कनाडा में 318 अरब, ब्राजील में 301 अरब और अमेरिका में 228 अरब पेड़ हैं।

आजकल

जल-जंगल को बचाने का संदेश

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफएसआइ ग्लोबल से संबद्ध

यह सिर्फ संयोग नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में मशहूर डिस्कवरी चैनल के खास शो- मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आए हैं। असल में देश की राजनीति के शीर्ष पर मौजूद प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में शामिल होने और इस शो के चर्चित प्रस्तोता बेयर ग्रिल्स के साथ उत्तराखंड के जंगलों में कुछ समय बिताने का अर्थ देश-दुनिया को जंगलों के महत्व के बारे में संदेश देना है। इस कार्यक्रम के जरिये उन्होंने प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक नई कोशिश की है

कुदरत को अगर चलते रहना है तो यह तय है कि जल, जंगल और जमीन की सतत हिफाजत जरूरी है। ऐसे में यह सिर्फ संयोग नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में मशहूर डिस्कवरी चैनल के खास शो- मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आए हैं। असल में देश की राजनीति के शीर्ष पर मौजूद प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में शामिल होने और इस शो के चर्चित प्रस्तोता बेयर ग्रिल्स के साथ उत्तराखंड के जंगलों में कुछ वक्त बिताने का अर्थ देश-दुनिया को जंगलों के महत्व के बारे में संदेश देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में भारत की प्राकृतिक विविधता और प्रकृति संरक्षण के उपायों की चर्चा की है। ऐसे वक्त में, जबकि लगता है कि जंगल, वन्यजीव और प्राकृतिक विविधता के संरक्षण के तमाम पहलू हमारी नजरों से ओझल होने लगे हैं, तब इस कार्यक्रम के जरिये प्रधानमंत्री और बेयर ग्रिल्स वन जागरूकता की एक नई कोशिश देश में कर रहे हैं। लंदन में वर्ष 1974 को जन्मे बेयर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। उन्हें 2004 में रॉयल नेवी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक देकर सम्मानित किया जा चुका है। बाद में धारावाहिक शो मैन वर्सेस वाइल्ड से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बहरहाल बेयर ग्रिल्स के शो में प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, टेनिस स्टार रोजर फेडरर आदि आ चुके हैं।

यहां कुछ अहम सवाल हैं। जैसे कि पहला यह कि क्या हमारे देश में जंगल और वन्यजीवों के लिए हालात सही नहीं हैं। दूसरा, भविष्य की पर्यावरणीय जरूरतों के नजरिये से वन और जंगली जनजीवन के सुरक्षित रहने की क्या गारंटी है। दोनों ही सवालों के मूल में यह जानकारी अपेक्षित है कि आखिर देश में जंगल और उसके जीवन की क्या चुनौतियां हैं। हाल में देश में बाघों की संख्या में अपेक्षित सुधार की खबरों से एक भरोसा जगा है। विश्व बाघ संरक्षण दिवस (29 जुलाई) पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 2,967 बाघ हैं, जो 2014 में हुई पिछली गणना से लगभग एक तिहाई ज्यादा हैं। मौजूदा संख्या 2006 में बाघ बचाने का संकल्प लिए जाते वक्त की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की सूचनाओं से लगता है कि हमारे जंगल अच्छी हालत में हैं, पर ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। असल में हमारे देश में बाघ की रिहाइश का संकट खड़ा होने लगा है।

जंगल किनारे आवासीय परियोजनाओं, विकास के लिए सड़क, रेलवे लाइनों के विस्तार आदि के कारण बाघों के रहने के आवास सिकुड़ने लगे हैं। फिलहाल भारत में बाघ अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख 80 हजार वर्ग किलोमीटर है, जबकि गिने गए लगभग तीन हजार बाघों को रहने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर प्रति बाघ के हिसाब से 6 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग दोगुनी जगह की जरूरत पड़ेगी। जगह कम हुई तो तीन नतीजे निकलते हैं। पहला, या तो बाघ आपस में लड़कर मर जाते हैं। दूसरा, खुराक पूरी करने के लिए वे इंसानी बस्तियों में आते हैं, जहां इंसानों और खुद की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। हाल के वर्षों में इंसान और बाघ के बीच शहरी-कस्बाई इलाकों में भिड़ंत की घटनाओं में वृद्धि इसी की सूचक है। तीसरा, कई बार उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता और वे लगातार भुखमरी से ग्रस्त होकर कहीं मरे पाए जाते हैं। ऐसी भी खबरें देश के तमाम हिस्सों से लगातार मिलने लगी हैं। ध्यान रहे कि बाघ को जंगल में जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वहां हिरन, नीलगाय और सूअर जैसे तमाम दूसरे जीव भी हों, जिनसे बाघों की खुराक में कमी न आने पाए। कहने का अर्थ है कि पर्याप्त संख्या में बाघ एक स्वस्थ जंगल की निशानी है, पर इन कसौटियों पर अपने जंगलों को कसने पर अब निराशा हाथ आने लगी है। हाल की गिनती में देश के तीन टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ का खोजा नहीं जाना-इसी निराशा का एक पहलू है। इससे देश के जंगलों और जैव विविधता पर आए संकटों का खुलासा होता है।

यूं उल्लेखनीय है कि दुनिया के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में से एक भारत है। इस जैव विविधता का एक मतलब यह है कि इस देश की जमीन पर जंगल हैं और उनमें विविध प्रकार के वन्य जीवन, जड़ी-बूटियां, घने वृक्ष और समूची पारिस्थितिकी मौजूद हैं। पर जैव विविधता को सहारा देने वाले जंगलों का दायरा हमारे देश में लगातार घट रहा है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में फैल जाने वाली जहरीली धुंध के रूप में अक्सर दिख जाता है।

जैसे-जैसे जंगल घटेंगे, स्मॉग, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं का दायरा बढ़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं, जिनसे देश में तेजी से घटते वन क्षेत्रों का पता चलता है। वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित जर्नल-नेचर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में अब सिर्फ 35 अरब पेड़ बचे हैं। देश की आबादी से तुलना करें तो हर व्यक्ति के हिस्से 28 पेड़ आते हैं। देखने में यह आंकड़ा सुकून देने वाला लग सकता है, पर इसमें कुछ पेच हैं। जैसे-ये ज्यादातर पेड़ हमारे शहरों-कस्बों में नहीं, बल्कि जंगलों में हैं और वहां भी उनकी संख्या अवैध कटाई और बांध-सड़क जैसे निर्माण कार्यों आदि कारणों से लगातार घट रही है। भारत से अच्छी स्थिति में रूस (641 अरब पेड़), कनाडा (318 अरब पेड़), ब्राजील (301 अरब पेड़) और अमेरिका (228 अरब पेड़) हैं। इन देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति इसलिए ज्यादा खराब है, क्योंकि एक तरफ वृक्षारोपण का काम बहुत धीमी गति और कई लापरवाहियों के साथ किया जा रहा है और दूसरे, अवैध कटाई का सिलसिला निरंतर जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया हर साल करीब 15.3 अरब पेड़ खो रही है, यानी कि प्रति व्यक्ति के अनुसार दो पेड़ से भी ज्यादा का नुकसान हर साल हो रहा है। दूसरी ओर की तस्वीर यह है कि हम बहुत कम संख्या में पौधे लगा रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश ने इस बारे में एक कीर्तिमान बनाया है, पर देखा गया है कि मानसून सीजन में किए जाने वाले ऐसे वृक्षारोपण आगे देखरेख के अभाव में बेमानी साबित होते हैं, क्योंकि रोपे गए ज्यादातर पौधे सूख जाते हैं।

बहरहाल ऐसा माना जाता है कि सभ्यता की शुरुआत से अब तक पूरी दुनिया में तीन लाख करोड़ से ज्यादा पेड़ इमारती लकड़ी, ईंधन और कागज के निर्माण के वास्ते काटे जा चुके हैं। सभ्यता की शुरुआत में जितने पेड़ पृथ्वी पर थे, उनमें अब तक 46 फीसद की कमी आ चुकी है यानी तकरीबन आधे जंगलों का सफाया हो चुका है। आगे भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दुनिया में पेड़ों के काटे जाने का सिलसिला जारी है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में सघन वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। 1999 में सघन वन 11.48 प्रतिशत थे, जो 2015 में 2.61 प्रतिशत रह गए। इस कसौटी पर देखें तो 2013 से 2015 के बीच ही मिजोरम में 306 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड में 268 वर्ग किमी, तेलंगाना में 168 वर्ग किमी, नगालैंड में 78 वर्ग किमी और अरुणाचल प्रदेश में 73 वर्ग किमी वन-क्षेत्र घट गया। इनके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और दादर नागर हवेली में भी वन घटे हैं। कुल मिलाकर देश के 16 राज्यों में जंगल घट गए हैं।

सघन वनों को ही वास्तविक जंगल मानना चाहिए, क्योंकि वन्यजीवन से लेकर पर्यावरण तक को इन्हीं से कुछ लाभ है। सघन वनों में गिरावट के कारण ही वन्यजीव अपने आश्रय छोड़कर शहरों-कस्बों में घुस रहे हैं, जिससे इंसानों से उनकी मुठभेड़ बढ़ रही है। जंगल नहीं रहने पर पर्यावरण क्षति किस तरह हानिकारक हो जाती है, उत्तर भारत की जहरीली हवाएं यही साबित कर रही हैं।

दावानल से दहलते दुनिया भर के जंगल

यूं आग से दुनिया का कोई जंगल बचा नहीं है, लेकिन हमारे देश के कुछ इलाकों में तो यह एक सालाना उपक्रम की तरह लौटती रहती है। अक्सर इन जंगलों की बेकाबू आग जंगली जीवों के लिए मुसीबत बन जाती है और इससे जंगल की बेशकीमती लकड़ी जलकर खाक हो जाती है। खास तौर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में हर साल लगने वाली आग तमाम विनाश रचती है, लेकिन तमाम उपायों के बावजूद उस पर कोई खास रोक नहीं लग पा रही है। इस आग से सिर्फ जंगल स्वाहा नहीं हो रहे, बल्कि इससे पैदा होने वाली धुंध और धुएं के कारण आम जन जीवन भी प्रभावित होता है।

उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, चमोली से लेकर बदरीनाथ और केदारनाथ वन प्रभाग के जंगलों में आग से लगातार वन संपदा का नुकसान होता रहा है और वन्य जीवों का वजूद भी संकट में पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल (2018 में) तो आग में काफी तबाही मचाई थी। वहां कसौली में वायुसेना डिपो तक आग पहुंच गई थी, जिसे रोकने के लिए विमानों के जरिए पानी का छिड़काव करना पड़ा। कुछ मौकों पर कालका-शिमला ट्रेन को रोकना पड़ा था। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में वैष्णोदेवी के रास्ते त्रिकुटा के जंगलों में लगी आग ने श्रद्धालुओं का रास्ता रोक दिया था। वर्ष 2018 में नासा द्वारा बताया गया था कि यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के अलावा दक्षिणी राज्यों में आग से 6 हजार हेक्टेयर वनक्षेत्र स्वाहा हो गया था।

वनक्षेत्रों में लगी आग को बुझाना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे पैदा होने वाले धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है, इसलिए हेलीकॉप्टरों के जरिये विशाल बाल्टियों से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश करना बेहद जोखिम वाला काम बन जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के जंगलों की आग के पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। यहां के जंगलों में चीड़ की बहुतायत है। जब कभी चीड़ की पत्तियों के ढेर ज्यादा लग जाते हैं तो जंगलों में जरा सी चिंगारी विशाल रूप ले लेती है। जंगल की इस आग को बुझाने के तीन तरीके विशेषज्ञ सुझाते हैं। पहला, मशीनों से जंगलों की नियमित सफाई हो, चीड़ आदि की पत्तियों को समय रहते हटाया जाए, लेकिन यह बेहद महंगा विकल्प है। दूसरा, वहां नियंत्रित ढंग से आग लगाई जाए। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में यही किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी काफी संसाधन चाहिए। तीसरा यह है कि पर्वतीय इलाकों में पलायन रोक कर जंगलों पर आश्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जंगलों की साफ-सफाई होगी और आग के खतरे कम होंगे।

चूंकि हमारे नेतागण और योजनाकारों ने जंगलों की आग की अहमियत को ठीक से समझा नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी तरीका उन्हें रास आएगा। ऐसे में इकलौता तरीका यही है कि सूचना मिलते ही विशालकाय बाल्टियों से लैस हेलीकॉप्टर पानी के साथ दहकते जंगलों की तरफ रवाना किए जाएं और गांव, प्रशासन समेत सेना भी ऐसे नाजुक मौकों पर अलर्ट रहे।

खरी-खरी

राग कश्मीर और खां साहब!

कुमार विनोद

आज हम आपका संक्षिप्त परिचय ऐसे राग से करवाने जा रहे हैं, जो सुनने को तो अक्सर मिल जाता है, लेकिन जिसका उल्लेख संगीत की किसी पुस्तक में नहीं मिलता।

नाम : राग कश्मीर

जाति : इसके आरोह-अवरोह में सत्य-स्वर का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। ये राग 'षड्यंत्र-परिपूर्ण' जाति का है। कुछ विशेषज्ञ इसकी गिनती 'भ्रमित' रागों में भी करते हैं। **स्वर** : कोमल व तीव्र, समयानुसार व जरूरतानुसार इसमें दोनों तरह के विकृत-स्वर प्रयुक्त होते हैं। तीव्र इच्छानुसार और कोमल-स्वर मजबूरी वश। इस राग के गायन का आरंभ करते समय अब तक पाकिस्तानी शासक तीव्र धमकियों व ऊलजलूल विकृत आरोही स्वरों का इस्तेमाल करते आए हैं। मगर अब भारत ने अपना स्वर ऐसा ऊंचा किया है कि उनका स्वर अवरुद्ध हो चला है। इन दिनों उन्हें मजबूरी-वश तीव्र के बजाय कोमल विकृत अवरोही स्वरों का प्रयोग करना पड़ रहा है। **सम प्राकृतिक राग** : चीन के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा से ठीक पहले, भारत में चीन के राजदूत द्वारा छेड़े जाने वाले 'राग तवांग' से ये काफी मिलता-जुलता है।

गायन-काल : पाकिस्तान में इसे गाने-बजाने का सर्वोत्तम समय आम चुनावों या 14 अगस्त यानी पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले होता है। विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा से पहले भी ये अक्सर गाया-बजाया जाता रहा है। मगर इस बार पाकिस्तान इस राग का र तक भूलता दिख रहा है। **विशेष** : हाल ही में उस्ताद खां साहब द्वारा अंकल सैम के समक्ष, उन्हीं के देश में इस राग की विशिष्ट एकल प्रस्तुति दी गई। उसके बाद अंकल द्वारा छेड़ी गई झूठी-तान भी चर्चा के केंद्र में रही। किंतु भारतीय केंद्र ने मीडियम वेव-370 मेगाहर्ट्ज पर बजने वाले इस राग को इस बार ऐसा उल्टा बजाया कि उस्ताद खां साहब के तो बोल ही बंद हैं, अंकल सैम भी भौचक हैं।

प्रकृति : बेसिर-पैर के दावों के अलावा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने की वजह से इस राग को 'वक्र-प्रकृति' का माना गया है। यह कुटिल व कर्कश मनःस्थिति में ही गाया जाता है। इसे पाकिस्तान अक्सर गाता रहा है। **वाद्य-यंत्र** : इस राग को गाते-बजाते समय बंदूक, टैंक, तोप, फाइटर जेट जैसे वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किंतु इस बार भारत ने 'चनकट राग' बजाकर पाकिस्तान की ध्वनि बंद कर दी है।

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा के एक नेता ने बताया कैसे अनुच्छेद 370 को लेकर वाजपेयी सरकार के समय पार्टी को ताने सुनने पड़ते थे कि इसे हटाया क्यों नहीं जाता। तब प्रमोद महाजन ने कहा था कि यह तभी हटेगा जब 370 सांसद होंगे। संयोग देखिए कि लोक सभा में इसे हटाने के लिए 370 सांसदों ने ही वोट किया था।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

सोनिया गांधी को इस समय अमित शाह जैसे एक नेता की जरूरत है। इसके बजाय वह किसी मनमोहन सिंह सरीखे नेता को ही नियुक्त करेंगी। बरखा दत्त@BDUTT

अमित शाह को तलाशने के लिए सोनिया गांधी को खुद नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

यह अच्छी बात नहीं कि कुछ शरारती तत्वों के चलते फिल्मकार अनुराग कश्यप को ट्विटर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह अपने परिवार को मिलने वाली धमकियों से आजिज आ चुके हैं। मैं अक्सर उनसे असहमत होता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता।
शेखर कपूर@shekharkapur

छत्तीसगढ़ डायरी

अतीत से भविष्य गढ़ने की कोशिश

आलोक मिश्रा
राज्य संपादक, नईदुनिया, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार अब कुछ-कुछ अपनी चाल तय करती लग रही है। इस ऑनलाइन के जमाने में उसकी चाल 'जमीनी' है। किसानों के पत्ते पर सत्ता में आई कांग्रेस यहां के पुराने दौर से भविष्य गढ़ने में जुटी है। अभी यहां का पुराना त्योहार हरेली सरकारी स्तर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री गेड़ी पर चढ़े, मंत्रियों ने ढोल बजाए, भूले-बिसरे खेल खेले गए, नाच नाचे गए, घर-आंगन मोह से देखा गया, किसानी यंत्र पूजे गए... एक उत्सव सा रूप दिया गया। फिर कुछ दिन बाद आदिवासी दिवस मनाया गया...फिर वही रौनक दिखी। दोनों दिन सबकी छुट्टी। इस दौरान पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया नजर आया।

राजनीति में निपटती कांग्रेस की पतली हालत किसी से छुपी नहीं है। बस एक छत्तीसगढ़ ही है जहां पांच साल के लिए उसका पांव 'अंगद पांव' रहेगा (मजबूत संख्या बल के कारण), नहीं तो कर्नाटक में धोबी पछाड़ पड़ने के बाद मध्यप्रदेश एवं राजस्थान भी कमजोर से लगने लगे हैं। देश में राष्ट्रवाद का भाव जागृत है और उसके केंद्र में मोदी सरकार है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में भूपेश छत्तीसगढ़ वाद से लोगों को छूने में लगे हैं। हरेली पर 988 गौठान शुरू किए गए। इन गौठानों में बेसहारा घूम रही गायों को रखकर उनके गोबर से गैस एवं खाद बनाने की योजना है। लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर आय बढ़ाने की कवायद है। हरेली में खुद के संसाधनों से रोजगार के बारे मे बताया गया और एक सवाल छोड़ दिया गया कि अवसर बुरा नहीं है।

भूपेश जानते हैं कि लोकसभा की हार भले ही देश भर की हार की आड़ में छुप जाए, लेकिन साल के आखिरी में होने वाले निकाय चुनाव उनकी कड़ी परीक्षा हैं। 168 में से 153 निकायों में चुनाव होने हैं। इसलिए इसके अलावा भी सरकार अब हर वर्ग को साधने में जुट गई है। नगरीय निकायों में अध्यक्षों को वित्तीय अधिकार दे दिए हैं, जो अब तक आयुक्तों और सीएमओ के पास थे। सफाई दीदियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। विकास कार्यों के लिए 50 लाख से 10 करोड़ रुपये तक देने को कह दिया गया है। रियल एस्टेट कारोबार को उबारने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क चार से दो फीसद कर दिया है और इसी बीच पिछली सरकार में अनुसूचित जाति का 14 से 12 फीसद हुआ आरक्षण कोटा एक फीसद बढ़ाकर इस वर्ग को भी साधने की चाल भी चल दी है। हालांकि इससे अन्य वर्गों में कुछ असंतोष भी बढ़ा है कि बढ़ा कोटा कटेगा किससे?

इधर भाजपा के सामने भी निकाय चुनाव की चुनौती कम बड़ी नहीं है। विधानसभा चुनाव में उसकी गति उसके कामों का फल थी और लोकसभा चुनाव में जीत मोदी के कारण। अब यह चुनाव भूपेश सरकार के कामकाज और उसके प्रभाव का फैसला करने वाला है। प्रदेश में चले सदस्यता अभियान में 11 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य मिला था, उसमें भी लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। 20 दिन में 5 लाख तक ही आंकड़ा पहुंच सका। इस बीच अनुच्छेद 370 क्या हटा, इनकी ठहरी गाड़ी चल निकली। अब यह संख्या 10 लाख तक पहुंची बताई जा रही है। वहीं अजीत जोगी फिर इन दिनों चर्चा में हैं। इस बार इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच एक महीने में पूरी करने के निर्देश देते हुए भूपेश ने बिना उनका नाम लिए उन पर छींटा कस दिया कि बहुत से लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे न केवल सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि राजनीति भी कर रहे हैं। बस आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। विश्व आदिवासी दिवस से पहले जोगी की पार्टी ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ कर उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अजीत जोगी को नकली आदिवासी कह दिया।

इस पर भड़के जोगी ने मरकाम को उन दिनों की याद दिला दी, जब मरकाम टिकट के लिए जोगी के चक्कर लगाते थे और दंडवत करते थे। इस खेमे से आजकल कांग्रेस की इसी तरह ठनी है। जबकि जोगी की पत्नी रेणु जोगी सार्वजनिक मंच पर भूपेश सरकार की तारीफ के पुल बांध रही हैं। किसान ऋण माफी तिहार के अवसर पर कांग्रेसियों से खचाखच भरे मंच से उन्होंने काम की तारीफ की। कांग्रेस व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच छिड़े वाक् युद्ध में रेणु का बयान बड़प्पन माना जा रहा है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या श्रेयस अय्यर एकदिवसीय मैचों में चौथे स्थान के लिए बेहतर विकल्प हैं?

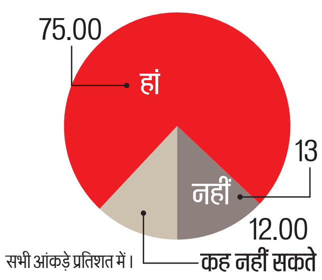

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सरकार को गुलाम कश्मीर को लेकर तत्काल कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गिला कुरैशी साब को साथ न कोई देश,
चिंता क्यों करते मियां साथ खड़ी कांग्रेस।
साथ खड़ी कांग्रेस, उमर, महबूबा, फारुख,
दिखा रहे ये लोग विभीषण वाला ही रुख!
घर के भेदी आज कर रहे ऐसी - तैसी,
फिर क्यों करते आप बेवजह गिला कुरैशी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

उलझते रिश्तों की अबूझ गांठें

सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं का सीधा संबंध हमारी विकृत जीवन शैली और असात्विक विचारों के साथ-साथ विकृत मनोविकारों से है

श्रीप्रकाश शर्मा
प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मिजोरम

हाल ही में पंजाब के मोगा जिले के नत्थूवाला गरबी गांव में दो अगस्त शुक्रवार की रात को एक 25 वर्षीय युवक ने अपने परिवार के छह सदस्यों को सोते हुए गोलियों से भून डाला और खुद को भी गोली मार ली। वहीं एक दूसरी घटना में पश्चिमी राजस्थान में स्थित बाड़मेर जिले में एक परिवार के ननद-भाभी और देवर के द्वारा जान देने की खबर समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। पूर्व के पांच सप्ताहों में इस तरह की यह 12वीं दुखद घटना है। इससे भी बदतर उत्तरी दिल्ली में एक ही परिवार के 11 सदस्यों के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटना ने जीवन और मृत्यु तथा इसके दर्शन से काफी करीबी से जुड़े कई प्रश्नों को और भी उलझा कर रख दिया है।

1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के उत्तर संक्रमण काल में जिस तरह से दुनिया में तब्दीलियों की तेज आंधी चली है, उसके परिप्रेक्ष्य में कदाचित इस सत्य से इन्कार करना आसान नहीं है कि मानव सभ्यता की करिश्माई भौतिक प्रगति के साथ जीवन जीने की इच्छा में इस प्रकार की अजीबोगरीब गिरावट ने हमारे सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। परिवार की खुशी और इसके सदस्यों का वर्षों तक साथ-साथ जीने की दिली इच्छा की पूर्ति के लिए जहां मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में मन्नतें मांगी जाती हैं, वहीं पर किसी परिवार के सदस्यों में सामूहिक रूप से अपने जीवन को खत्म करने की बढ़ती खतरनाक प्रवृत्ति से सामाजिक और पारिवारिक जीवन की शुचिता, आदर्श व्यावहारिक और चारित्रिक संहिता पर कई प्रश्नचिन्ह अपने आप खड़े हो जाते हैं।

प्रथम दृष्टया सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं के तार पारिवारिक संबंधों में अविश्वास और संदेह से जुड़ते हैं। अवैध संबंधों के कारण पारिवारिक जीवन में शक और विश्वास के अभाव की सेंध इस प्रकार की सामूहिक आत्महत्या के उत्प्रेरण की मुख्य वजह मानी जाती है। निर्धनता के कारण अपने ही कलेजे के टुकड़े को भूख से बिलखते देखकर मां-पिता की मजबूरियों को भी इस तरह से खुद के साथ-साथ अपने बच्चों की जीवन-लीला को खत्म करने की एक प्रमुख वजह मानी जाती है। वैसे कुछ लोग इस प्रकार की सामूहिक आत्महत्याओं को आध्यात्मिकता के आईने से भी देखते हैं और इस प्रकार के अमानवीय कुकृत्य को मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम मानते हैं।

सामूहिक रूप से जीवन को खत्म करने की वारदातों से संबंधित दलीलों और तर्कों का बाजार गर्म है। इसके कारणों की एक सुई प्रगति की तेज रफ्तार के बदौलत हमारे उस पारिवारिक व्यवस्था की ओर भी जाती है जिसमें संयुक्त पारिवारिक प्रथा की असमय मौत हो गई है। और साथ ही एकल परिवार की नई रवायत के फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से सिर पर हाथ रखनेवाले और आर्थिक संकट की स्थिति में अपने साथ किसी का साया होने के अहसास की मजबूती में काफी क्षरण आया है। यही कारण है कि मानसिक निर्वात, वैचारिक शून्यता और आर्थिक विपन्नता सरीखे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की कोशिश में संघर्ष करने के लिए आवश्यक साहस का सर्वथा अभाव होता जा रहा है और आत्महत्या जीवन से पलायन के एक सहज विकल्प के रूप में सुलभ हो गया है। कदाचित इस सत्य से भी हम इन्कार नहीं कर सकते हैं कि आज जिस प्रकार से इंटरनेट आम जनता तक सहज रूप से सुलभ हुआ है, उसके सह-उत्पाद के रूप में सोशल मीडिया ने चाहे-अनचाहे हमारे जीवन में कई तरह के बदलावों को ला दिया है। इसने आपसी संबंधों की निजता और पवित्रता को मलिन किया है। भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति की अंधी चाह में किसी तांगे के घोड़े की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बेतहाशा दौड़ता हुआ आज का मशीनी मानव हताशा और अवसाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है।

अपने चेहरे पर खुशी और आत्मसंतुष्टि के छद्म आवरण के साथ अपने परिवार के बीच और समाज में जीनेवाले अपनों की पहचान आज हमारी सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में खड़ी है। लिहाजा रिश्तों में गलतफहमियों और आपसी मन-मुटाव के मकड़जाल को नियमित रूप से साफ करते रहने की दरकार है। देखा-देखी की संस्कृति में अपने पांव अपनी चादर तक ही फैलाने के अमूल्य दर्शन को जीवन में धार्मिक रूप से फॉलो करने की जरूरत है। जीवन में खुश रहने के लिए खुद को किसी-न-किसी कार्य में व्यस्त रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब मन खाली होता है तो इसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है और यह मन में अनुत्पादक और जहरीले विचारों को जन्म देता है।

मूल रूप से आशय यही है कि सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं का सीधा संबंध हमारी विकृत जीवन शैली और असात्विक विचारों और विकृत मनोविकारों से है। जीवन जीना आसान तो नहीं होता है, लेकिन जीवन का जीना कठिन और कष्टमय होना ही जीवन का आकर्षण है और यही जीवन की गाड़ी के लिए आवश्यक ऊर्जा का कार्य करता है। जीवन में सपने देखना स्वाभाविक है, किंतु उसके साकार न होने की स्थिति में मन को दुखी कर लेना और जीवन को बेकार समझ लेना सबसे बड़ी समस्या है। जीवन में हमेशा विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने और जीने की जरूरत है। इस नश्वर संसार में जीवन कभी रुकता नहीं, वक्त कभी ठहरता नहीं और दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है। घोर अंधेरे के बाद हर एक सुरंग के मुहाने पर रोशनी का संसार फैला होता है और इसी दर्शन में जीवन का सार छुपा हुआ है। इसके साथ ही हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आत्महत्या जीवन के अपरिहार्य दुखों और संघर्षों से पराजय है, पलायन है। यह कुदरत के नियमों का उल्लंघन है। इससे बड़ी जीवन की दूसरी कोई भी हार नहीं हो सकती है।

बीएस-6 नियमों से दोपहिया वाहनों के दाम 15 फीसद तक बढ़ेंगे

नई दिल्ली : इंडिया यामाहा मोटर (आइवाईएम)] ने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन नियमों का अनुपालन करने से स्थानीय स्तर पर निर्मित दोपहिया वाहनों के दाम 10 से 15 फीसद तक बढ़ सकते हैं। कंपनी के मंगलवार को कहा कि वह चरणबद्ध तरह से बीएस-6 मानकों के अनुरूप मोटरसाइकिलों और स्कूटरों में बदलाव करेगी। मोटरसाइकिल के लिए यह प्रक्रिया नवबंर, 2019 और स्कूटर के लिए जनवरी, 2020 से शुरू होगी। यामाहा मोटर ने बयान में कहा कि यामाहा की टीम कंपनी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काम कर रही है। (प्रेट्र)

पेट्रोकेमिकल्स में क्षमता विस्तार के लिए हम दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। हमारी योजना कंपनी को शीर्ष पोजीशन पर बरकरार रखने की है।
— **संजीव सिंह**
चेयरमैन, आइओसी

सेंसेक्स	36,958.16	▼ 623.75
निफ्टी	10,925.85	▼ 183.80
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,370	▼ ₹100
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 45,000	▲ ₹2000
डॉलर	₹ 71.40	▲ ₹0.62
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 60.69	

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 16.82 फीसद की गिरावट

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

जहां तक दोपहिया वाहनों का प्रश्न है, तो जुलाई के दौरान बिक्री में 16.82 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। इस महीने दोपहिया कंपनियों ने 15,11,692 यूनिट वाहन बेचे। इसके मुकाबले पिछले वर्ष जुलाई में 18,17,406 दोपहिया वाहन बिके थे। बिक्री में गिरावट का सिलसिला वाणिज्यिक वाहनों में भी बना हुआ है। इन वाहनों की बिक्री में जुलाई 2019 में 25.71 फीसद की कमी आई है। माथुर का कहना है कि उद्योग बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रयास कर रहा है। 'लेकिन अब समय आ गया है जब उद्योग को वास्तव में सरकार की मदद की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि उद्योग को फिर से पटरी पर लाने और बिक्री में गिरावट को रोकने के लिए राहत पैकेज की आवश्यकता है।

नौकरियों पर बुरा असर : माथुर ने कहा कि पिछले दो से तीन महीने में ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों में करीब 15000 नौकरियां जा चुकी हैं। इनमें अधिकांश नौकरियां अस्थायी और कैजुअल स्तर की हैं। इसके अतिरिक्त कंपोनेंट उद्योग में भी लाखों नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, माथुर के मुताबिक बिक्री में गिरावट के चलते करीब 300 डीलरों को अपना धंधा समेटने पर मजबूर होना पड़ा है। इससे भी दो लाख लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं।

पूरे सेक्टर पर दबाव : माथुर ने कहा कि इस बार की मंदी पिछली मंदी से काफी अलग और गहरी है। साल 2008-09 और 2013-14 में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ हिस्सा ऐसा था जिसकी बिक्री में वृद्धि का सिलसिला बना रहा था। 'किंतु इस बार समूचा सेक्टर मंदी की चपेट में है और बिक्री कम हो रही है।' सियाम का कहना है कि अगर उद्योग में गिरावट का सिलसिला बना रहा तो इसका असर देश के जीडीपी पर भी दिखेगा।

चौतरफा गिरावट में रिलायंस का जश्न फीका

बदहाली ▸ 623.75 अंक फिसलकर 36,958.16 अंक पर आया सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : विदेशी बाजारों की अस्थिरता और घरेलू बाजार में मासिक बिक्री के मोर्चे पर ऑटो सेक्टर की लगभग दो दशकों सबसे बड़ी दुर्गति के चलते शेयर बाजारों पर गिरावट पूरी तरह हावी रही। चीन-अमेरिका के बढ़ते ट्रेड वार, हांगकांग में प्रदर्शन गहराने और अर्जेंटीना की मुद्रा का बुरा हाल होने की वजह से विदेशी बाजार दबाव में रहे। इसके चलते कई सेक्टरों में चौतरफा बिकवाली की वजह से बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ। बिकवाली का आलम यह था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के शेयरों में करीब 10 फीसद के उछाल का जश्न भी फीका पड़ गया। दिन के कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 623.75 अंक यानी 1.66 फीसद टूटकर 36,958.16 अंक पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी 183.80 अंकों यानी 1.65 फीसद की गिरावट के साथ 11,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आते हुए 10,925.85 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में यस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील और एलएंडटी जैसे दिग्गज शेयर 10.35 फीसद तक टूट गए। अगर आरआइएल के शेयरों में लगभग 10 फीसद का उछाल नहीं आया होता, तो घरेलू शेयरों में मंगलवार को और बड़ी गिरावट होती। सन फार्मा और पावरग्रिड के शेयर भी गिरावट से बचे रहे। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई के टेलीकॉम, ऑटो, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, टेक, पावर, इंडस्ट्रियल्स व आइटी इंडेक्स 4.34 फीसद तक गिरे।

जानकारों का कहना था कि कंपनियों के उम्मीद से कमतर नतीजों और डॉलर के मुकाबले रुपये की मंदी का भी नकारात्मक असर घरेलू शेयर बाजारों पर दिखा। दिन के कारोबार के बारे में सेंट्रम ब्रोकिंग के रिसर्च प्रमुख (वैल्थ) जगन्नाधम थुनुगुंटला ने कहा कि अमेरिका-चीन में ट्रेड वार गहराने और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी अन्य कई चिंताओं के चलते घरेलू शेयर बाजारों में निवेशकों ने बिकवाली को हवा दी। हांगकांग में दिनोंदिन हिंसक हो रहे प्रदर्शन के चलते हैंगसेंग दो फीसद से ज्यादा टूट गया। शंघाई कंपोजिट (चीन) में भी 0.63 फीसद की गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में यूरोप के ज्यादातर बाजार दबाव में दिखे।

अगर आरआइएल में तेजी नहीं आती, तो बाजार में बड़ी गिरावट तय थी। प्रतीकात्मक

गिरावट के पांच बड़े कारण

- ऑटो सेक्टर में चौतरफा बिकवाली
- डॉलर के मुकाबले रुपये का करीब 50 पैसे टूटना
- रिलायंस जियो की नई योजना से टेलीकॉम सेक्टरों में बड़ी गिरावट
- विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार निकासी
- हांगकांग की स्थिरता और अर्जेंटीना की मुद्रा की दुर्गति से विदेशी बाजारों पर दबाव

आरआइएल के शेयर 10 फीसद तक उछले

नई दिल्ली, प्रेट्र : चौतरफा गिरावट वाले शेयर बाजार में मंगलवार को निवेशकों के लिए आरआइएल के शेयर एकमात्र सहारा बने। दिन के कारोबार में कंपनी के शेयर 113 रुपये यानी 9.72 फीसद चढ़कर 1,295 रुपये पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कंपनी के शेयरों का बंद भाव 9.74 फीसद उछाल के साथ 1,275.30 रुपये रहा। बीएसई में इंट्रा-डे में कंपनी के शेयर 1,300 रुपये के भाव के ऊपर चले गए थे।

शेयरों में इस उछाल के दम पर बीएसई में आरआइएल का बाजार पूंजीकरण 71,638 करोड़ रुपये बढ़कर 8,08,233 करोड़ रुपये के पार चला गया। सोमवार को एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) की 42वीं सालाना आमसभा में भविष्य के लिए जिस तरह की घोषणाएं की थीं, उसे लेकर शेयर बाजारों में मंगलवार को इसके शेयरों का धमाकेदार प्रदर्शन अपेक्षित था। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की सरकार नियंत्रित पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरैमको ने आरआइएल के पेट्रोलियम बिजनेस का 20 फीसद हिस्सा खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंबानी ने पांच सितंबर को जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा भी लांच करने की घोषणा की।

टैक्स नोटिस पाए स्टार्ट-अप को भी एंजल टैक्स में राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने उन सभी पंजीकृत स्टार्ट-अप को एंजल टैक्स से राहत दे दी है, जिनसे आयकर विभाग ने टैक्स वसूल करने का आदेश दिया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य वास्तविक उद्यमियों को राहत देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सीबीडीटी ने उन स्टार्ट-अप को एंजल टैक्स में राहत दी थी जो स्क्रूटनी के दायरे में तो आए हैं लेकिन अब तक टैक्स वसूली का नोटिस नहीं मिला है।

आयकर कानून की धारा 56(2)(सात) के तहत अगर कोई उद्यमी एक शेयर को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य यानी प्रीमियम पर बेचता है, तो उसे आय माना जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा। बहुत से स्टार्ट-अप ने इस तरीके से एंजल निवेशकों से धनराशि जुटाई। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से स्टार्ट-अप को आयकर के नोटिस जाने लगे। ऐसे मामले एंजल टैक्स के नाम से चर्चित हुए। लोकल सर्किल्स के चेयरमेन सचिन तापड़िया ने कहा, सरकार ने एंजल टैक्स की समस्या को नवीनतम अधिसूचना के जरिये अंततः सुलझा दिया है। जिनसे टैक्स वसूली का आदेश हो चुका है, उनको भी इससे राहत मिलेगी।

होटलों की मनमानी पर मंत्रालय नाराज

मामला ▸ एक होटल ने दो केले का चार्ज लिया था 442 रुपये, एक ने 1,700 में दिए दो अंडे

नई दिल्ली, प्रेट्र : खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दो केले के लिए 442 रुपये चार्ज करने वाले पांचसितारा होटल से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पासवान ने मंगलवार को कहा कि केले और और अंडों जैसे खाद्य पदार्थों के लिए पांचसितारा होटल द्वारा अत्यधिक दाम वसूला जाना, 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है और सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। मंत्री के मुताबिक ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए हाल ही में बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नियम और कानून बनाने के समय प्रावधान किए जाएंगे।

पासवान हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें अभिनेता राहुल बोस को चंडीगढ़ के पांचसितारा होटल जेडब्ल्यू मैरियट में दो केले के लिए 442 रुपये का बिल भरना पड़ा था। एक और पांच सितारा होटल द्वारा दो उबले हुए अंडे के लिए 1,700 रुपये का बिल दिया गया था जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'सोशल मीडिया और अन्य समाचार माध्यमों में शिकायतें और खबरें हैं कि केले और अंडे जैसी वस्तुओं के लिए कुछ पांचसितारा होटलों द्वारा काफी ज्यादा पैसे वसूल किए गए हैं। यह एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है।

पासवान ने इस पर आश्चर्य जताया कि कैसे पांचसितारा होटल दो केले के लिए 442 रुपये और दो अंडों के लिए 1,700 रुपये का शुल्क ले सकते हैं, जबकि ये सामान खुले बाजार में बहुत सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। पासवान ने कहा कि उनका मंत्रालय संबंधित पांचसितारा होटलों से सफाई मांगेगा कि उन्होंने किस आधार पर उन्होंने ये शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा, हम दोहरे एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की अनुमति नहीं देंगे। सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों की जांच करने के लिए नियम बनाएगी जिसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था इस मौके पर उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने कहा, 'प्रथम दृष्टया तो यह एक अनुचित व्यापार व्यवहार है। जैसा कि मंत्री ने निर्देश दिया है, हम इन होटलों से स्पष्टीकरण मांगेंगे।' उन्होंने कहा कि अगर इन पांचसितारा होटलों को अनुचित व्यवहार में लिा पाया जाता है तो ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाद उत्पन्न होने पर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआइ) ने हालांकि जेडब्ल्यू मैरियट चंडीगढ़ का बचाव किया था और उनका तर्क था कि होटल ने कुछ भी 'अवैध' नहीं किया है।

उसने कहा कि होटल परिसर में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थ पर 18 फीसद जीएसटी लगाना कानून सम्मत है। एफएचआरएआइ ने तर्क दिया था कि एक खुदरा स्टोर से केले की खरीद बाजार मूल्य पर की जा सकती है। लेकिन बड़े होटलों में केवल सामान ही नहीं, बल्कि उसके साथ सेवा, गुणवत्ता, प्लेट, कटलरी, साथ में अन्य चीजें, स्वच्छ किए गए फल, विशेष परिवेश और विलासिता भी प्रदान की जाती हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान दो केलों के लिए 442 रुपये चार्ज करने को मनमाना बताया। प्रेट्र

खुदरा महंगाई दर में राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ जुलाई में 3.15 फीसद रही खुदरा महंगाई दर, गांव की अपेक्षा शहरों में महंगाई दर अधिक

महंगाई के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है। फल और सब्जियों की कीमतें कम रहने से इस साल जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.15 फीसद पर आ गई है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) ने मंगलवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 3.18 फीसद तथा पिछले साल जुलाई में 4.17 फीसद थी। वैसे, इस साल जुलाई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मामूली बढ़कर 2.36 फीसद हो गयी है जबकि जून में यह 2.25 फीसद थी।

खुदरा महंगाई का ताजा स्तर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के महंगाई के लक्ष्य से कम है। आरबीआइ ने खुदरा महंगाई दर को चार फीसद (प्लस-माइनस दो फीसद) पर नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा है। आरबीआइ इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी मौद्रिक नीतियां तय करता है। जहां तक अलग-अलग वस्तुओं की महंगाई का सवाल है, तो मांस और मछली में मूल्य वृद्धि की रफ्तार काफी अधिक रही है। इस साल जुलाई में मांस और मछली की महंगाई दर नौ फीसद से ऊपर रही है। फलों की महंगाई दर जुलाई में -0.86 फीसद और शुगर एंड कन्फेक्शनरी की -2.11 फीसद रही है। इसी तरह फ्यूल एंड लाइट समूह की महंगाई दर भी 0.36 फीसद रही है। अंडों की महंगाई दर भी जुलाई में 0.57 फीसद रही है।

शहरों में ज्यादा महंगाई : शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर इस साल जुलाई में 4.22 फीसद रही। हालांकि गांवों में खुदरा महंगाई का स्तर शहरों से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई में खुदरा महंगाई की दर 2.19 फीसद रही। खास बात यह है कि पांच राज्यों - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई की दर नकारात्मक रही है।

प्रतीकात्मक

एनएमडीसी की बिक्री 35 फीसद बढ़ी

नई दिल्ली (वि) : चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनएमडीसी की बिक्री में 35 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में कंपनी ने 3264 करोड़ रुपये की बिक्री की जो पिछले साल इसी अवधि में 2422 करोड़ रुपये थी। इस अवधि में कंपनी ने लौह अयस्क के उत्पादन में 21 फीसद की वृद्धि दर्ज की।

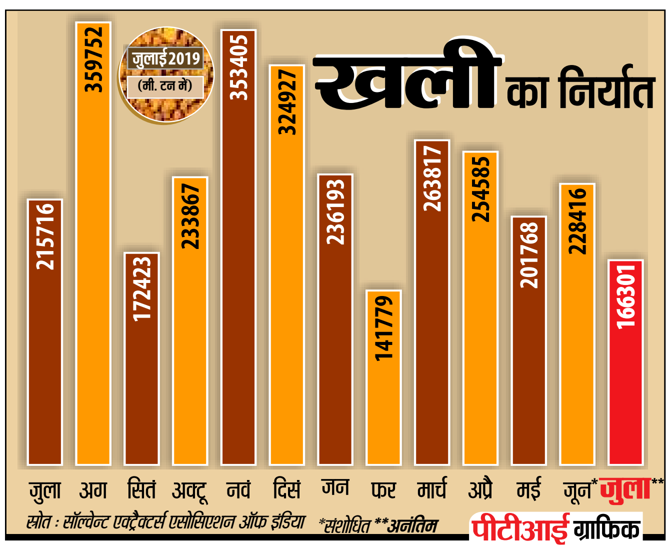

नीलांचल इस्पात संयंत्र का अधिग्रहण करेगी सेल

जागरण संवाददाता, बोकारो : स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने इस्पात मंत्रालय व ओडिशा सरकार के संयुक्त उद्यम नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के अधिग्रहण का फैसला लिया है। इससे सेल की इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

सेल की अधिग्रहण पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस बावत सेफी (स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख कर सेल हित में सभी संभावित पहलुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में कहा गया है कि नीलांचल इस्पात का सेल में विलय होने से कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 21.42 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2030 तक 60 मिलियन टन हो जाएगी। सेफी के इस पत्र के बाद पीएमओ की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है।

सीएसआर पर कंपनियों को राहत की उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि खर्च न करने पर जेल के प्रावधान को लेकर उद्योग जगत में उभरी चिंता के मद्देनजर सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने सीएसआर संबंधी नियमों में ढिलाई देने की वकालत की है। इस समिति का कहना है कि कंपनी कानून के तहत सीएसआर के नियमों का उल्लंघन होने पर उसे आपराधिक मामला बनाने की जगह दीवानी अपराध मानना चाहिए। साथ ही सीएसआर पर खर्च को कंपनियों की कर योग्य आय से घटा देना चाहिए। गौरतलब है कि हाल में सरकार ने कंपनी कानून में बदलाव करते हुए सीएसआर के नियमों के उल्लंघन में तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान किया है, जिसे लेकर उद्योग जगत ने चिंता प्रकट की है।

कंपनी मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली इस समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सीएसआर व्यय को सरकारी योजनाओं में धनराशि की कमी को पूरा करने का साधन नहीं मानना चाहिए। समिति की सबसे अहम सिफारिश सीएसआर संबंधी नियमों का अनुपालन न होने पर उसे दीवानी अपराध मानने के बारे में है। समिति का कहना है कि इस संबंध में जुर्माने की व्यवस्था की जा सकती है। समिति ने सीएसआर व्यय के एवज में कंपनियों को आयकर में कटौती का लाभ देने की सिफारिश भी की है। साथ ही पांच करोड़ रुपये से अधिक की राशि के व्यय के प्रभाव का मूल्यांकन कराने का सुझाव भी समिति ने दिया है। समिति में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के एमडी अमित चंद्रा और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बीएस नरसिम्हा सहित कई सदस्य शामिल थे। सरकार ने सीएसआर से संबंधित मौजूदा नियमों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन अक्टूबर, 2018 में किया था।

प्रतीकात्मक

अधिकतर बैंकों के फंसे कर्ज में पिछले छह महीनों में दर्ज की गई गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग संगठन फिक्की के एक सर्वेक्षण में आधे से ज्यादा बैंकों ने फंसे कर्ज (एनपीए) में कमी की सूचना दी है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। यह सर्वेक्षण जनवरी-जून, 2019 के दौरान किया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और लघु वित्त बैंक (स्मॉल फाइनेंस बैंक) समेत कुल 23 बैंकों ने हिस्सा लिया। बैंकों ने सुझाया है कि कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी की रूपरेखा को सरल बनाना चाहिए और जीएसटी की दरों में कमी करनी चाहिए। मंगलवार को फिक्की-आइबीए सर्वेक्षण के नौवें चरण को जारी करते हुए फिक्की ने कहा कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले बैंकों का मानना है कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अगले छह महीनों में अधिक कर्ज की जरूरत होगी। ये क्षेत्र बुनियादी ढांचा, धातु, रियल एस्टेट, वाहन एवं वाहन कलपुर्जे, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक बैंकरों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी डाली जानी चाहिए और एनबीएफसी क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। फिक्की ने कहा कि ये प्रतिक्रियाएं केंद्रीय बजट 2019-20 पेश होने से ठीक पहले मिली थीं और वास्तव में, बजट में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश भी शामिल है।

इसमें वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी की ऊंची रेटिंग वाली संपत्तियों के खरीद के लिए सरकारी बैंकों को एकबारगी छह महीने की आंशिक कर्ज गारंटी उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। यह गारंटी बैंकों को उनके पहले 10 फीसद तक के नुकसान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिक्की ने कहा कि इन उपायों से नकदी की समस्या को दूर करने में मदद मिलनी चाहिए और वृद्धि को समर्थन देने के लिए अधिक ऋण सुनिश्चित होगा।

सर्वेक्षण के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले बैंकों में से 52 फीसद का मानना है कि एनपीए में कमी आई है। पिछले दौर में 43 फीसद प्रतिभागी इसके पक्ष में थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, करीब 55 फीसद प्रतिभागियों ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी की सूचना दी है। सर्वेक्षण में कहा गया माना जाता है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र उधा एनपीए क्षेत्र है अर्थात सबसे ज्यादा कर्ज यहीं फंसा है। करीब 63 फीसद प्रतिभागियों का मानना है कि पिछले छह महीने के दौरान इस क्षेत्र के एनपीए में कमी आई है।

▸ बैंकों ने सरकार से जीएसटी की रूपरेखा और सरल करने की दी सलाह

▸ 52 फीसद बैंकों ने माना कि एनपीए में आई है कमी

प्रतीकात्मक

सांसत

नाइट फ्रैंक-फिक्की-नारेडको की रिपोर्ट ने पेश की बेहद निराशाजनक तस्वीर, अगले छह महीनों के दौरान जमीनी स्थिति और बिगड़ने की उम्मीद

मंदी के दलदल में और धंसेगा रियल एस्टेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के रियल एस्टेट की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। इस क्षेत्र की कम से कम छह बड़ी कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया के दायरे में हैं। देशभर में लाखों मकान तैयार हैं, लेकिन इनके खरीदार नहीं है। बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने कंपनियों को कर्ज देना बंद कर दिया है। परिसंपत्तियों की कीमत लगातार कम हो रही है। अब इस सेक्टर की स्थिति लगातार सामने लाने वाली एजेंसी नाइट फ्रैंक ने उद्योग संगठन फिक्की और रियल एस्टेट सेक्टर के संगठन नारेडको के साथ जो नया अध्ययन जारी किया है, वह भविष्य में हालात के और बिगड़ने की तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मांग में कमी, अनबिके मकानों की बढ़ती संख्या और एनबीएफसी की समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।

ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी क्षेत्र के मंदी के दायरे में फंसने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर भी और मुश्किल में फंसता दिख रहा है। इस क्षेत्र में परियोजनाओं की बढ़ती लागत को फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बताया गया है। इस समस्या के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तरफ से वित्त सुविधा के बंद होने को सबसे अहम वजह बताया गया है। एनबीएफसी से कर्ज नहीं मिलने की वजह से कंपनियों को बाहर से महंगा कर्ज लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि इस सेक्टर में गंभीरता से काम कर रही कंपनियों के लिए भी बैंकों व वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना आसान नहीं रह गया है। वैसे देश के सभी हिस्सों में निराशा का माहौल है लेकिन उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा मंदी है। सर्वे में हिस्सा लेने वाली कंपनियों ने सबसे ज्यादा उत्तर भारत के रियल एस्टेट बाजार को लेकर निराशा जताई है। सर्वे में शामिल वित्तीय संस्थानों की भी निराशा सामने आ रही है और इस सेक्टर की कंपनियों की भी।

सर्वे में शामिल 74 फीसद उत्तरदाताओं ने कहा है कि अगले छह महीनों के दौरान आर्थिक स्थिति अभी जैसी ही है वैसी ही रहेगी, या और खराब होगी। यह समूचे रिएल एस्टेट से जुड़े तंत्र के भय को उजागर करता है। आवासीय इकाइयों की लांचिंग और उनकी बिक्री की स्थिति भी पहले से खराब हुई है। 69 फीसद का कहना है कि आवासीय इकाइयों की बिक्री में और गिरावट आने के आसार हैं। आरबीआइ की तरफ से रेपो रेट में कटौती किए जाने के बावजूद बिक्री में कोई खास सुधार आने की गुंजाइश नहीं है। नाइट फ्रैंक के चेयरमैन व एमडी शिशिर बैजल का कहना है कि, 'यह सर्वे साफ करता है कि क्यों रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी है। ऑटो, एफएमसीजी जैसे सेक्टर भी मंदी के चपेट में हैं जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी रियल एस्टेट सेक्टर से काफी आगे जा चुका है।' इसी तरह से नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदनी का मानना है कि, 'दुनियाभर में रियल एस्टेट सेक्टर को आर्थिक गतिविधियों को एक साथ बढ़ाने वाला माना जाता है।

फाइल फोटो

चांदी में 2,000 रुपये का उछाल, सोना फिसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सराफा बाजार में मंगलवार का दिन पूरी तरह चांदी के नाम रहा। दिन के कारोबार में यह बहुमूल्य सफेद धातु 2,000 रुपये उछलकर 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। हालांकि सोने का भाव 100 रुपये की गिरावट के साथ 38,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र जैन का कहना था कि विदेशी बाजारों में सफेद धातु में निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी का फायदा घरेलू बाजार में चांदी के भाव पर दिखा। इसी वजह से चांदी 45,000 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच पाई। घरेलू बाजार में चांदी को सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाईयों ने हाथोंहाथ लिया। लेकिन विदेशी बाजारों में मजबूत संकेतों के बावजूद सोने का भाव घरेलू बाजार में कमजोर रहा।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव मजबूती के साथ 1,520.37 डॉलर, और चांदी का भाव उछाल के साथ 17.32 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर था। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 38,370 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। हालांकि सोने की आठ ग्राम गिन्नी का भाव 200 रुपये उछलकर 28,800 रुपये के स्तर पर चला गया। चांदी हाजिर 2,000 रुपये उछलकर 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 956 रुपये की मजबूती के साथ 44,280 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। चांदी के सिक्कों का भाव 1,000 रुपये प्रति सैकड़ा चढ़कर 90,000 रुपये बिक्री पर जा पहुंचा।

▸ 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा चांदी का भाव

प्रतीकात्मक

1 महिला की मौत हो गई ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हुए चाकू के हमले में। 21 वर्षीय हमलावर धार्मिक नारे लगा रहा था। आसपास के लोगों ने तुरंत उसको पकड़कर पुलिस को सौंपा। हमले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है।

न्यूज गैलरी

नेपाल के पीएम ओली के गृह जिले में बम धमाका

झापा : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृह जिले झापा में सोमवार को एक सरकारी दफ्तर में जोरदार बम विस्फोट हुआ। बिरतामोड़ नगरपालिका के दफ्तर में प्रेशर कुकर बम से किए गए इस धमाके में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोमवार सुबह हुए इस धमाके के वक्त दफ्तर बंद था। नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ के प्रमुख अजय कर्की ने बताया कि धमाके से दफ्तर का सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की सूचना मिलते ही नेपाल की सेना मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को हालांकि इस वारदात के पीछे प्रतिबंधित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नेत्र बिक्रम चंद बिप्लव होने की आशंका है। (एएनआइ)

नाइजीरिया के शिया नेता इलाज के लिए आ रहे भारत

अबुजा : अफ्रीकी देश नाइजीरिया के प्रमुख शिया नेता इब्राहिम अल-जकजाकी इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया (आइएमएन) के नेता जकजाकी ने मंगलवार को राजधानी अबुजा से भारत के लिए फ्लाइट पकड़ी। जकजाकी के साथ उनकी पत्नी भी भारत आ रही हैं। जकजाकी और उनकी पत्नी दिसंबर, 2015 से ही हिरासत में थे। 2016 में एक स्थानीय अदालत ने उनकी रिहाई के निर्देश दिए थे। लेकिन नाइजीरिया की सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें हिरासत में बनाए रखा। बिगड़ती सेहत के कारण हाल में कडुना प्रांत की एक अदालत ने जकजाकी को विदेश जाकर इलाज कराने के लिए जमानत दे दी थी। इसके बाद दंपती ने इलाज के लिए भारत का रुख किया। (एएनआइ)

द. कोरिया में उ. कोरियाई महिला बेटे के साथ मृत मिली

सियोल : उत्तर कोरिया से आकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रहने वाली एक महिला (42) अपने छह साल के बेट के साथ मृत पाई गईं। पति से तलाक होने के बाद महिला 2009 से यहां रह रही थी। मंगलवार को यहां एक अपार्टमेंट स्थित घर से बदबू आने के बाद जब कमरा खोला गया तब दोनों को मृत पाया गया। पड़ोसी मौत की वजह भूख को बता रहे हैं। जांच के लिए शव को भेज दिया गया है। (आइएएनएस)

बांग्लादेश में डेंगू से 40 लोगों की जान गई

ढाका : बांग्लादेश में डेंगू से 40 लोगों की मौत हो गई है। यह देश में डेंगू का सबसे खतरनाक असर कहा जा रहा है। इस साल देश भर में 44 हजार से भी ज्यादा डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, मच्छर के काटने से फैलने वाली इस बीमारी के कारण अकेले सोमवार को 21 सौ लोगों को भर्ती कराना पड़ा। इसे देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। स्थानीय मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है कि डेंगू से हुई मौत के आंकड़े और अधिक हैं। (एएफपी)

ब्रिटेन ने अभी तक ईरान का तेल टैंकर नहीं छोड़ा

दुबई : ब्रिटेन ने अभी तक ईरान का जब्त किए गए तेल टैंकर को नहीं छोड़ा है। रॉयल मरीन ने इस तेल टैंकर को जब्त कर लिया था। ईरान की रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्दी ही ब्रिटेन उसके तेल टैंकर को छोड़ सकता है। चार जुलाई को ग्रेस 1 जब्त करने के बाद तेहरान और पश्चिम के बीच खटास और बढ़ गई और तेल परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले खाड़ी क्षेत्र में बदले की कार्रवाई तेज हो गई। ब्रिटेन ने सीरिया को तेल आपूर्ति पर लगाए गए यूरोपीय प्रतिबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए तेल टैंकर को जब्त कर लिया था। (रायटर)

ब्रेक्जिट पर आयरलैंड के पीएम से बात करेंगे ब्रिटिश पीएम

डबलिन : ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट और उत्तरी आयरलैंड के मुद्दे पर बात करने के लिए आयरलैंड के पीएम लियो वराडकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मीडिया आरटीई के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात डबलिन में होगी। आयरलैंड के पीएम के प्रवक्ता को कोट करते हुए यह खबर दी गई। (आइएएनएस)

ह्यूस्टन में 'हाउडी, मोदी' सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 हजार ने कराया पंजीकरण

▶ पीएम मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित

ह्यूस्टन, प्रेट्र : भारतीय अमेरिकी समुदाय के सम्मेलन 'हाउडी, मोदी' में शिरकत करने के लिए करीब 40 हजार लोग अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को इस सम्मेलन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने अमेरिका जा रहे हैं। मोदी अमेरिका में भारतीय समुदाय को तीसरी बार संबोधित करेंगे। 2014 में न्यूयॉर्क के मैडीसन स्क्वायर गार्डन और 2016 में सिलिकॉन वैली में वह भारतीय समुदाय को संबोधित कर चुके हैं। दोनों समारोह में 20,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की थी।

'हाउडी' 'हाऊ डू यू डू' (आप कैसे हैं) का संक्षिप्त रूप है। दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका में आम तौर पर लोग एक-दूसरे से मिलते वक्त हालचाल जानने के लिए यही बोलते हैं। ह्यूस्टन के एक गैर सरकारी संगठन 'टेक्सास इंडिया फोरम' ने बताया कि समारोह में आने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए 'पास' होना जरूरी है। अमेरिका के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले शहर के 'एनआरजी फुटबाल स्टेडियम' में हो रहे इस कार्यक्रम में करीब 50 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। विश्व की ऊर्जा राजधानी के तौर पर प्रसिद्ध ह्यूस्टन में पांच लाख से अधिक भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं।

नरेंद्र मोदी फाइल

ह्यूस्टन के मेयर बोले-संबंधों को मजबूत करेगी पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा

ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूस्टन में स्वागत करने के लिए उत्साहित हूं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं।' उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक यात्रा व्यापार, संस्कृति और पर्यटन पर ह्यूस्टन और भारत के बीच पहले से मजबूत संबंधों को और सुदृढ़ करेगी, जिसका लाभ ह्यूस्टन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। 'टेक्सास इंडिया फोरम' ने बताया कि पहले सप्ताह में ही 39,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया था। 1000 से अधिक स्वयंसेवक और 650 'वेलकम पार्टनर' कार्यक्रम से जुड़े हैं। अमेरिकी सीनेटर जॉन कोर्निन ने कहा, 'टेक्सास के लाखों भारतीय अमेरिकी की ओर से और सीनेट इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष तौर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूस्टन में स्वागत करता हूं।'

एशिया में मिसाइल तैनाती को लेकर अमेरिका कर रहा विचार-विमर्श

बीजिंग, एपी : अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि एशिया में अपनी मिसाइलें तैनात करने के लिए सहयोगी देशों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मिसाइल तैनाती की तैयारी को लेकर चीन पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। चीन ने कहा है कि वह इन मिसाइलों को जगह देने वाले देश के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा।

अमेरिकी राजनयिक और विदेश मंत्रालय में हथियार नियंत्रण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले की अवर सचिव एंड्रिया थांपसन ने मंगलवार को कहा कि मिसाइल तैनाती पर अमेरिकी सरकार की सहयोगी देशों की सरकारों से बातचीत चल रही है। रूस के साथ मध्यम-दूरी की मिसाइलों पर प्रतिबंध से जुड़ी संधि के हाल में खत्म होने के बाद अमेरिका एशिया में अपनी मिसाइलें तैनात करने की कोशिश में है। इसकी एक वजह क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती देना भी है। इसके लिए तीन सहयोगी देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया में से किसी एक में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की संभावना जताई जा रही है।

पाकिस्तानी युवक ने मलीहा को सुनाई खरी-खरी, बताया चोर

▶ यूएन में पाक की स्थायी प्रतिनिधि से पूछा, 15-20 साल से क्या कर रही हैं आप

न्यूयॉर्क, एएनआइ : भारत के खिलाफ लामबंदी की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। हाल में यहां एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाक की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी को एक पाकिस्तानी नागरिक ने ही जमकर खरी-खोटी सुनाई। लोधी को चोर बताते हुए उसने कहा कि वह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं।

यूएन के कार्यक्रम में हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें लोधी उस पाकिस्तानी नागरिक के सवालों से बचती नजर आ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान जब वह मीडिया से बात कर रही थीं तभी एक शख्स ने आगे आकर उनसे पूछा कि क्या उसके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास एक मिनट का समय है। लोधी के जवाब का इंतजार किए बिना वह उनसे पूछने लगा, 'आप पिछले 15-20 साल से आखिर क्या कर रही हैं? आप सिर्फ हमारा पैसा खा रहीं है। आप हमारा ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है।'

लोधी के कहने पर भी वह शख्स चुप नहीं हुआ। जब वह जाने लगीं तो वह उनके पीछे जाते हुए कहने लगा, 'आप सब लोग हमारा पैसा चुरा रहे हैं। आप चोर हैं और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं।' कुछ घंटों में ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ ट्विटर यूजर ने उस पाकिस्तानी नागरिक का समर्थन किया है और लोधी को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। एक यूजर ने लिखा, 'लोधी हमारे पैसों का दुरुपयोग कर ऐश कर रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया।'

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी। एएनआइ

हालात बिगड़े तो लौटना होगा मुश्किल : कैरी लैम

बढ़ रहा मामला ▶ हांगकांग की प्रमुख ने लोगों को हिंसा से दूर रहने की सलाह दी, कहा- राज्य को बंटता नहीं देख सकते

हवाईअड्डे पर प्रदर्शन के कारण लगातार दूसरे दिन सैकड़ों उड़ानें प्रभावित

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन समाप्त होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने यहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का घेराव किया। इस कारण से ज्यादातर उड़ानों को रद करना पड़ा। इस बीच, हांगकांग की प्रमुख कैरी लेम ने प्रदर्शनकारियों को चेताया है कि हालात ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जहां से लौटने रास्ते बंद हो जाएंगे।

चीन की समर्थक मानी जाने वाली कैरी लेम ने मंगलवार की सुबह भावुक अंदाज में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में हिंसा हांगकांग को ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है, जहां से वापसी का विकल्प नहीं होगा। लेम ने कहा, 'बीते हफ्ते हांगकांग के हालात देखकर मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि हम ऐसे ही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं।' प्रदर्शनकारी लैम का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे स्पष्ट इन्कार किया है। उन्होंने कहा, 'एक मिनट हमारे शहर, हमारे घर की ओर देखिए। क्या हम इसे पाताल में जाने दें और इसे टुकड़ों में बंटता हुए देखते रहें। मेरी जिम्मेदारी इससे आगे है। बतौर मुख्य कार्यकारी, मैं हांगकांग की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, अपने लोगों की शिकायतें सुनने और हांगकांग को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हूं।' हांगकांग का शेयर बाजार में दो फीसद से ज्यादा टूट गया है। यह सात महीने के निचले स्तर पर है।

हवाईअड्डे पर प्रदर्शन जारी : लेम की बातों का प्रदर्शनकारियों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। दोपहर बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने फिर यहां के हवाईअड्डे को घेर लिया, जिससे लगातार दूसरे दिन सैकड़ों उड़ानें प्रभावित रहीं। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, 'मैं पिछले दिन की ही तरह हवाईअड्डे को बंद करना चाहता हूं। ज्यादा उड़ानें रद रहेंगीं।' एक प्रदर्शनकारी ने बैनर पर लिखा था, 'असुविधा के लिए खेद है। हम अपने घर के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं।' प्रदर्शनकारियों के जुटने के बाद हवाईअड्डे के प्रशासन ने दोपहर बाद से सारी उड़ानें रद कर दीं।

यात्री भी समर्थन में : समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, प्रदर्शन के कारण उड़ानें भले प्रभावित हो रही हैं, लेकिन व्यवधान में फंसे बहुत से यात्री प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हैं। जर्मनी के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे 53 वर्षीय फ्रैंक फिल्सर ने कहा, 'मैं तो कभी भी जर्मनी जा सकता हूं, लेकिन उन लोगों का क्या जो यहीं रहते हैं? यह उनका घर है। वे हांगकांग के लिए लड़ रहे हैं। यह उनका नजरिया है।' कई अन्य यात्रियों का भी इन प्रदर्शनों को लेकर ऐसा ही नजरिया है। कुछ यात्री उड़ानें रद होने के कारण क्रोधित भी देखे गए।

भारत ने जारी की एडवाइजरी : हांगकांग में उड़ानें रद होने के कारण यहां स्थित भारतीय दूतावास ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों को बताया गया है कि प्रदर्शन के कारण उड़ानें रद होने या देर होने का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। ऐसे में यात्रा से पहले विमानन कंपनियों से संपर्क करें। असुविधा से बचने के लिए अन्य मार्गों पर विकल्पों की जानकारी लेने का सुझाव भी दिया गया है।

चीन ने दी आतंकवाद की संज्ञा : चीन ने इन प्रदर्शनों को आतंकवाद का अंकुर कहा है। हांगकांग के कानूनी जानकारों का कहना है कि चीन यहां आतंकरोधी कानून को लागू करने की भूमिका तैयार कर रहा है। सरकारी मीडिया में इस तरह का वीडियो भी सामने आया है जिसमें चीनी सैनिक दक्षिणी शहर शेनझेन में जुटते दिख रहे हैं। यह हांगकांग की सीमा से लगता शहर है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बलप्रयोग पर चिंता जताई है।

हांगकांग के हवाई अड्डे में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी ट्रालियों का बैरीकेड बनाकर खड़े हो गए। रायटर

क्या है मामला?
वर्ष 1997 में ब्रिटेन से चीन के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद स्वायत्तशासी हांगकांग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दो महीने पहले विवादास्पद प्रत्यर्पण कानून के विरोध में शुरू हुआ लोगों का आंदोलन अब हांगकांग से चीन समर्थक शासन व्यवस्था हटाकर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने की मांग में बदल गया है।

अफगानी सीमा के सैनिक कश्मीर सीमा में तैनात करने की घुड़की

न्यूयार्क, आइएएनएस : कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने अपना अफगानिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि हमारे सैनिक अफगानिस्तान सीमा से हटकर कश्मीर की सीमा पर तैनात किए जा सकते हैं। बता दें कि पाक की यह 'धमकी' ऐसे समय में आई है जब अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है और इसी कड़ी में उसकी तालिबान से बातचीत भी चल रही है। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की एक खास भूमिका है, उसकी तालिबान पर पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अमेरिका को इस मामले में पाकिस्तान का साथ चाहिए।

सेना को वहां से हटाने का संकेत देकर पाकिस्तान परोक्ष रूप से अमेरिका पर दबाव बनाने की फिराक में है। यह बात दरअसल अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने कही है। उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड के साथ एक विशेष इंटरव्यू में यह चेतावनी दी, लेकिन साथ ही कहा कि अफगानिस्तान और कश्मीर दो अलग-अलग मामले हैं और वह इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके उलट, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता सफल हो और वह इसके लिए प्रयास कर रहा है।

अखबार ने पाकिस्तान को उस वादे की याद दिलाई जिसमें उसने अफगानिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा को और मजबूत करने की बात कही थी, ताकि इस इलाके में तालिबान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मिलने से रोका जा सके और अफगानिस्तान मुद्दे का समाधान हो। इस पर खान ने कहा, 'पश्चिमी सीमा पर हम अपनी पूरी क्षमता लगा चुके हैं। अगर पूर्वी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो हमें सेना की तैनाती पर (पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा पर) विचार करना पड़ेगा। अभी हम इस्लामाबाद में ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, सिवाय इसके जो कुछ पूर्वी सीमा पर हो रहा है।'

पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए इस समय से कोई और बुरा समय हमारे लिए नहीं हो सकता था। खान ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच बहुत कम संपर्क हुआ है और लग रहा है कि हालात और बुरे होंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने रविवार को ट्वीट में कहा था कि उन्हें यह जानकारी मिली कि, पाकिस्तानी सेना शनिवार रात से ही भारत से लगी नियंत्रण रेखा की तरफ कूच कर रही है'

पेरिस समझौते के तहत विकसित देश भी निभाएं वादा : जावडेकर

▶ ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री हुए रवाना

▶ कहा-समझौते के तहत हमने जो जिम्मेदारी ली थी, उसे निभा रहे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर मंगलवार को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स और बेसिक देशों के मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने दुनिया के विकसित देशों को पेरिस समझौते के तहत किए गए अपने वादों को निभाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि इस समझौते के तहत भारत ने जो जिम्मेदारी ली थी, उसे बखूबी निभा रहा है।

रवाना होने से पहले जावडेकर ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सराहा और कहा कि जिस तरह से उन्होंने इसकी अगुआई की है, उससे दुनिया में भारत को लेकर भरोसा और बढ़ा है। यही वजह है कि अब हम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से पीछे नहीं हैं, बल्कि अब हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। खास बात यह है कि ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स देशों की इस बैठक में रूस और चीन जैसे विकसित देश भी शामिल होंगे। पेरिस समझौते का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके तहत दुनिया के सभी विकसित देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद का वादा किया था। इसे विकसित देशों को निभाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों के वादों का मुद्दा भारत पहले भी विभिन्न वैश्विक मंच पर उठा चुका है। ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहली बैठक ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के बीच होनी है, जिसमें ब्राजील के साथ रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दूसरी बैठक बेसिक देशों के बीच होनी है, जिसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल होंगे। यह चार देशों का एक नया संगठन है।

प्रकाश जावडेकर फाइल

सैन्य प्रशिक्षण के लिए चुनाव अभियान से दो हफ्ते की छुट्टी लेंगी तुलसी गबार्ड

▶ अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी बनने की रेस में हैं शामिल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड इंडोनेशिया में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने चुनाव अभियान से दो हफ्ते की छुट्टी लेंगी। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने की दावेदार सांसद तुलसी ने सोमवार को कहा, 'इंडोनेशिया में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए मैं उत्साहित हूं। यह अभ्यास आतंकरोधी और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित है।'

गबार्ड अमेरिकी सेना के रिजर्व बल आर्मी नेशनल गार्ड के तहत दो बार पश्चिम एशिया में तैनात रह चुकी हैं। 2004 से 2005 के बीच उन्होंने इराक में अपनी सेवाएं दी थीं। इसके बाद 2008 से 2009 तक उन्होंने कुवैत में वहां की सेना के साथ काम किया था। सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए 2017 में भी उन्होंने दो हफ्ते की छुट्टी ली थी। लेकिन इस बार वह ऐसे समय पर छुट्टी ले रही हैं जब 2020 राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहा अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए 20 से ज्यादा नेता डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल हैं।

अभियान छोड़ने पर गबार्ड ने कहा, 'मैं अपने देश से प्यार करती हूं। मैं किसी भी तरह देश की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मुझे नहीं पता इससे मेरे अभियान पर क्या असर पड़ेगा।' उल्लेखनीय है कि दूसरी प्राइमरी बहस में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गबार्ड अभी तीसरी बहस के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास केवल एक फीसद लोगों का समर्थन हैं।

अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करतीं तुलसी गबार्ड। रायटर

संबंध

तेजी से बढ़ रही चीनी मीडिया की भारत में दिलचस्पी, भारत पर 'ग्लोबल टाइम्स' के रुख का हामी नहीं 'चाइना डेली'

एक-दूसरे को पश्चिम की निगाह से न देखें भारत-चीन

राजीव सचान, बीजिंग

सरकारी नियंत्रण वाले चीनी मीडिया की उभरते भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन वह भारत को पश्चिमी मीडिया की नजरों से नहीं देखना चाहता और यह भी अपेक्षा रखता है कि भारतीय भी उसे पश्चिम के समाचार माध्यमों की निगाह से न देखे। चीनी मीडिया भले ही सरकारी नियंत्रण में हो, लेकिन वह खेमों में बंटा दिखता है। इसका आभास बीजिंग आए भारतीय मीडिया दल को तब हुआ जब 'चाइना डेली' के संपादक मंडल ने 'पीपुल्स डेली' के मुकाबले अपनी नीति को बेहतर और विश्वसनीय बताया। साथ ही 'ग्लोबल टाइम्स' को टैबलायड करार देकर यह संदेश देने की कोशिश कि उसके रुख को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दिलचस्प यह है कि ये तीनों समाचार पत्र चीनी सरकार अथवा सत्ताधारी दल से ही नियंत्रित हैं। चीन में मीडिया सरकारी हाथों में है और निकट भविष्य में ऐसे कोई आसार नहीं कि इस देश में निजी मीडिया संस्थान अस्तित्व में आ सकेंगे।

चाइना डेली की ओर से ग्लोबल टाइम्स की रीति-नीति को खारिज करने की कोशिश उस वक्त हुई जब भारतीय मीडिया दल के सदस्यों ने डोकलाम विवाद के समय इस चीनी अखबार के भारत के खिलाफ आक्रामक और उकसावे वाले रुख का उल्लेख किया। ज्ञात हो कि उस दौरान ग्लोबल टाइम्स भारत को 'चुटकियों में खदेड़ देंगें-मिटा देंगे' वाली भाषा का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। तब इस अखबार को देखने-पढ़ने वालों को यही प्रतीत हो रहा था कि भारत के खिलाफ ऐसी उग्र भाषा का इस्तेमाल चीन सरकार की शह पर हो रहा है। चाइना डेली के प्रतिनिधि इस धारणा को ध्वस्त करते दिखे। चाइना डेली के संपादक मंडल ने भारत को अपने प्रतिनिधियों की नजर से जानने-समझने और दोनों देशों के मीडिया माध्यमों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही भारत के प्रति बढ़ती रुचि को भी रेखांकित किया। इस क्रम में आमिर खान और उनकी फिल्म दंगल का जिक्र किया। अंग्रेजी के इस समाचार पत्र में कई भारतीय भी काम करते हैं। मंगलवार के इसके अंक में भारतीय और चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई वार्ता की खबर पहले पेज पर प्रमुखता से थी, लेकिन शीर्षक 'कश्मीर विवाद को बातचीत से हल करने की जरूरत' पर ही केंद्रित था। खेल पेज पर विराट कोहली के वन डे में शतक की खबर भी थी। इसके अलावा इसी अखबार में काम करने वाले पत्रकार मंजूनाथ शेट्टी का एक स्तंभ भी प्रकाशित किया गया था। दुनिया के अन्य देशों की तरह चीनी अखबार भी ऑनलाइन समाचारों के जरिये पाठकों को आकर्षित करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वे पश्चिमी मीडिया माध्यमों को चीन के प्रति दुराग्रही मानते हैं। चीन में पश्चिमी देशों के अखबार, टीवी चैनल, ऑनलाइन नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाना दुष्कर है।

पुरानी हिंदी फिल्में भी लुभा रहीं

चीन में दंगल फिल्म की लोकप्रियता पुरानी बात हो चुकी। नई बात यह है कि आमिर, सलमान और ऋतिक रोशन की हालिया फिल्मों को चीन में मिली सफलता ने पुरानी हिंदी फिल्मों के प्रति भी दिलचस्पी बढ़ा दी है। पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों की वीडियो क्लिप चीनी नागरिकों के मोबाइल फोन में जगह बना रही है। इनमें आवारा फिल्म का कालजयी गीत मैं आवारा हूं.. भी शामिल है। भारतीय मीडिया दल की टूर गाइड ने यह गाना गुनगुनाने के बाद जितेंद्र और आशा पारेख के गाने का एक वीडियो दिखाकर फिल्म का नाम जानना चाहा, लेकिन दल के सदस्य अनुमान के घोड़े ही दौड़ा सके।

हॉट सीट पर बैठने से घबराता हूं : अमिताभ बच्चन

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) की मेजबानी करने वाले अमिताभ बच्चन ने तमाम प्रतिभागियों के ज्ञान की परीक्षा ली है। हालांकि वह खुद हॉट सीट पर बैठने से घबराते हैं। यह रहस्योद्घाटन उन्होंने मंगलवार को केबीसी सीजन-11 की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किया। अमिताभ के मुताबिक उन्हें हॉट सीट से डर लगता है। एकाध-बार वह उस सीट पर बैठे हैं और एक या दो ही सवालों का जवाब दे पाए हैं। महानायक बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़े हैं। वह कहते हैं, 'गांवों से कई युवा लड़कियां आकर जब यहां से 25 लाख की धनराशि जीतती हैं, तो वह कहानियां प्रेरित करती हैं।

चैरिटी के बारे में बताना नहीं चाहता: उन्होंने कहा कि कई सितारे धर्मार्थ कार्य करते हैं, लेकिन मीडिया में चर्चा नहीं करते हैं। हमें यह बताने में शर्म आती है कि हमने कितना काम कहां किया है। यहां आने से पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेरी बात हो रही थी। मैं जानना चाह रहा था कि अपने सोशल मीडिया पर मैं किस तरह की जानकारी साझा कर सकता हूं, जिससे लोगों को मदद मिल सके। केबीसी अमिताभ बच्चन के घर में भी देखा जाता है। वह कहते हैं उनकी पोती आराध्या भी यह शो देखती है। जब उनसे पूछा गया कि परिवार का कौन सा सदस्य इस खेल में आगे तक जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार मेरा परिवार नहीं आ सकता है।

शो के फार्मेट और सेट में किया गया है बदलाव: इस बार अमिताभ बच्चन की एंट्री एक गुफा के जरिये होगी। इसके अलावा क्यू रोवर कैमरा हॉट सीट के आसपास घूमता रहेगा, जो बिग बी के कहने पर काम करेगा। एक रिएलिटी रूम भी बनाया गया है। खेल की बात करें तो इस बार फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन के तहत 11 विषयों के विकल्प मिलेंगे, जिसमें से प्रतिभागी अपना पसंदीदा विषय सुनकर सवाल को बदल सकेंगे।

मुंबई में मंगलवार को टीवी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) सीजन 11 के लांच अवसर पर शो की मेजबानी करने वाले अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लेते प्रशंसक। प्रेट्र

तैयारी ▸ वेस्टइंडीज के साथ तीसरा व अंतिम वनडे मैच आज, बड़ी पारी खेल अपने दौरे का अंत करना चाहेंगे धवन

एक और सीरीज जीतना चाहेगा भारत

युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और रिषभ पंत पर होंगी सभी की निगाहें

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज शिखर धवन लगातार चार पारियों में असफल रहने के बाद बड़ी पारी खेलना चाहेंगे, जबकि भारत जब बुधवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे व अंतिम वनडे मैच में की नजरें एक और सीरीज जीतने पर होंगी। टी-20 सीरीज में 01, 23 और 03 रन के स्कोर बनाने के बाद धवन ने दूसरे वनडे मैच में सिर्फ 02 रन का स्कोर किया था, जिससे चोट के बाद उनकी वापसी अच्छी नहीं रही।

धवन को अंदर आती गेंद पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दो बार तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल ने आउट किया। धवन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं और ऐसे में बायें हाथ का दिल्ली का यह बल्लेबाज अपने कैरेबियाई दौरे का अंत यादगार पारी खेलकर करना चाहेगा।

भारतीय टीम में चौथे नंबर पर जगह पक्की करने को लेकर द्वंद्व चल रहा है और श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे में शानदार पारी खेलकर रिषभ पंत पर दबाव बढ़ा दिया है। पंत को टीम प्रबंधन विशेषकर कप्तान विराट कोहली का समर्थन हासिल है, लेकिन उनकी लगातार विफलता और दूसरे वनडे में अय्यर की 68 गेंद में 71 रन की पारी से चीजें बदल गई हैं। पंत की मानसिकता चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर अपना विकेट गंवाया है। कोई भी टीम इस महत्वपूर्ण स्थान पर धैर्यवान बल्लेबाज को उतारना चाहेगी और रविवार को खेली पारी से अय्यर ने अपना दावा मजबूत किया है। यहां तक कि दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी चौथे नंबर के स्थान के लिए अय्यर का समर्थन किया है। वह चाहते हैं कि पंत को नीचे नंबर पांच पर भेजा जाए। उन्हें लगता है कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज पारी के अंत में टीम को गति प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

दूसरे वनडे में 125 गेंद में 120 रन की पारी खेलने वाले कप्तान कोहली भी अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। धवन, रोहित शर्मा और पंत के जल्द आउट होने के बाद कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर पारी को संवारा था। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में आठ ओवर में 31 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और यह तेज गेंदबाज अपने इस शानदार प्रदर्शन को दौरे के आगामी मैचों में दोहराना चाहेगा। भुवनेश्वर के तेज गेंदबाजी जोड़ीदार मुहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने भी दो-दो विकेट चटकाए थे। बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप हालांकि रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे।

ज्यादातर टीमें जीत दर्ज करने वाली एकादश में बदलाव को प्राथमिकता नहीं देती हैं, लेकिन कोहली अंतिम वनडे में शमी को आराम देकर नवदीप सैनी को मौका दे सकते हैं। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए बेताब होगी। भारत को हराने के लिए हालांकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। कैरेबियाई टीम के पास शाई होप, शिमरोन हेटमायर और निकोलस पूरन जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन इन्हें उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें एंटिगा के नॉर्थ साउंड में 22 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगी।

पोर्ट ऑफ स्पेन में कीरोन पोलार्ड के साथ बोट पर शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। इंस्टाग्राम

टीमें : **भारत–** विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्रा सिंह चहल, केदार जाधव, मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और नवदीप सैनी।

वेस्टइंडीज– जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, जॉन कैंपबेल, इविन लुइस, शाई होप, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज, फेबियन एलेन, कार्लोस ब्रेथवेट, कीमो पॉल, शेल्डन कॉटरेल, ओशाने थॉमस और केमार रोच।

129 वनडे मैच खेले गए हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच। इनमें से भारत ने 61 व वेस्टइंडीज ने 62 मैच जीते हैं। दो मैच टाई रहे, जबकि चार के परिणाम नहीं निकले

38 वनडे मैच खेले गए हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच कैरेबियाई सरजमीं पर। इनमें से भारत ने 15 और वेस्टइंडीज ने 20 मैच जीते हैं। तीन मैचों के परिणाम नहीं निकले

04 वनडे मैच खेले गए हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन के नॉर्थ साउंड स्टेडियम में। इनमें दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं

विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार से सीखें युवा खिलाड़ी

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार बार-बार अनुभव को दोहरा रहे हैं और दोनों ने दूसरे वनडे के मुश्किल विकेट पर सामंजस्य बैठाया। यह युवाओं के लिए एक अच्छी सीख है। जैसा कि वह अब लंबे समय से आदर्श हैं, कोहली सच में अपने 42वें शतक तक पहुंचने के लिए काबिलेतारीफ थे।

जितना मैं उन्हें देखता हूं, उतना ही ज्यादा मैं उनके इरादे और तीव्रता को पाने की योग्यता की प्रशंसा करता हूं। जब आप लंबे समय तक खेलते हो, जैसा कि विराट कर रहे हैं तो यह मुमकिन होता है कि कई बार आप अपना फोकस खो देते हो। यहीं विराट खास हैं। जब भी वह देश के लिए खेलते हैं, वह हमेशा तैयार रहते हैं और उनका इरादा जितना बाउंड्री लगाने में पक्का दिखता है, उतना ही डिफेंस में भी दिखता है। जैसा कि वह स्ट्राइक बदलते हैं, जैसे वह पहला रन तेजी से दौड़ते हैं और वह सिर्फ अपने ही नहीं अपने साथी के रन पर भी इतना ही तेज दौड़ते हैं। उनके बारे में एक चीज बहुत अच्छी है कि वह पिच को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और उसी के मुताबिक अपना खेल खेलते हैं। उनके पास पिच की गति के अनुरूप अपने बल्ले की स्विंग की गति को बढ़ाने का तोहफा है। यह आसान नहीं है, क्योंकि बल्ले की स्विंग स्वभाविक होती है। वह सहज ज्ञान के मास्टर हैं और उनका इस तरह से सामंजस्य बैठाना ही उनके तीनों प्रारूपों में सफलता का कारण है।

श्रेयस अय्यर ने भी एक बेहतरीन पारी खेली। किसी के लिए भी राष्ट्रीय टीम में वापसी आसान नहीं होती है, लेकिन उन्होंने इंडिया-ए के लिए बड़े रन किए। इससे उन्हें विराट संग लंबे समय तक बल्लेबाजी करने में मदद मिली और इससे उन्हें बड़ा आत्मविश्वास भी मिला होगा। हालांकि उनके मन के अंदर टीम में लंबे समय तक टिकने की बातें चल रही होंगी। भुवी हमेशा की तरह चालाक दिखे, उन्होंने दोबारा विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की और अपनी विविधताओं को बढ़ाया। एक चुनौतीपूर्ण विकेट पर अच्छे लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज को जरूरत थी कि उनके अनुभवी बल्लेबाज लय बनाए, लेकिन एक बार दोबारा क्रिस गेल लय के लिए जूझते दिखे।

इंग्लैंड को लॉर्ड्स में वापसी की उम्मीद

एशेज ▸ ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा टेस्ट मैच आज से

लंदन, एएफपी : बर्मिंघम में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 251 रनों से मात खाने वाली इंग्लैंड बुधवार से लॉर्ड्स मैदान पर शुरू हो रहे दूसरे मैच में वापसी की उम्मीद में उतरेगी। मैच से पहले हालांकि इंग्लैंड को एक झटका लगा है क्योंकि जेम्स एंडरसन पिंडली में चोट के कारण इस मैच में नहीं उतरेंगे। एंडरसन के नहीं होने और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बेहतरीन फॉर्म के बाद भी इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भरोसा है कि टीम वापसी कर सकती है।

एंडरसन के स्थान पर युवा जोफ्रा आर्चर को टेस्ट पदार्पण का मौका मिल सकता है। आर्चर ने विश्व कप में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था और उम्मीद होगी की वह स्टीव स्मिथ के अगुआई वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को रोक सकेंगे। इंग्लैंड के सहायक कोच पॉल कोलिंगवुड ने हालांकि कहा है कि टीम सिर्फ आर्चर के भरोसे नहीं रह सकती। वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया आत्मविश्वास से भरी है। बर्मिंघम में उसने खराब शुरुआत से बाहर निकलते हुए जीत हासिल की थी। इस मैच में वह अपनी बढ़त को दोगुना करना चाहेगी। पिछले मैच में सिर्फ स्टीव स्मिथ ही नहीं थे जो चमके थे, उनके अलावा वेड ने भी शतक जमाया। वहीं गेंदबाजी में लियोन ने कमाल दिखा मेजबान टीम के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया था।

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। टीम में जेम्स पैटिंसन के स्थान पर मिशेल स्टार्क को जगह दी है। वहीं जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क को चुना गया है। बाकी कोई और बदलाव अंतिम-12 में नहीं हुआ है। लॉर्ड्स के मैदान पर स्लोप है जो बायें हाथ के गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है इसलिए क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले इस मैदान पर स्टार्क के उतरने की उम्मीद ज्यादा है।

अभ्यास सत्र के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो। एएफपी

लैंगर को वार्नर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर को उम्मीद है कि सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट में टीम के लिए रन जुटाएंगे। एक साल के प्रतिबंध के बाद टीम में लौटे वार्नर ने बर्मिंघम में पहले टेस्ट में मात्र 10 रन बनाए थे। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ ने दोनों पारियों में शतक लगाया था। लैंगर ने कहा कि मुझे यह पसंद है जब महान खिलाड़ी इसे मिस करते हैं। इसका मतलब है कि आंकड़ों के रूप से वह शायद जल्द ही इसमें सुधार करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि इस टेस्ट में ऐसा होगा। कोच ने कहा कि इसी वजह से वह एक महान खिलाड़ी हैं और उनकी आंख में यह नजर आता है।

इंग्लैंड केवल आर्चर पर भरोसा नहीं कर सकता : कॉलिंगवुड

लंदन, एएफपी : इंग्लैंड टीम के सहायक कोच पॉल कॉलिंगवुड का मानना है कि जो रूट और उनकी टीम को जोफ्रा आर्चर पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और ना ही उन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। कॉलिंगवुड ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि जोफ्रा, आप ऑस्ट्रेलिया द्वारा पूछे जा रहे सभी सवालों के जवाब देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत अच्छा तेज गेंदबाज मिला है और वह हमें अलग विकल्प देते हैं। अपनी कप्तानी में वर्ष 2010 में इंग्लैंड को टी-20 का विश्व चैंपियन बना चुके पूर्व कप्तान ने कहा कि उनके पास आत्मविश्वास है और वह एक्स-फैक्टर है। लेकिन, मैं नहीं चाहता कि टीम आने वाले युवा खिलाड़ी पर भरोसा करें और उनसे ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने की उम्मीद करें।

टीमें (संभावित)

ऑस्ट्रेलिया : टिम पेन (कप्तान), डेविड वार्नर, कैमरन बेनक्राफ्ट, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, पीटर सिडल, नाथन लियोन, जोश हैजलवुड।

इंग्लैंड : जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, सैम कुर्रन, जो डेनले, जैक लीच, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स।

पैटिनसन की जगह स्टार्क को अगले टेस्ट में चाहते हैं जॉनसन

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन लॉर्ड्स में होने वाले अगले टेस्ट मैच में जेम्स पैटिंसन की जगह मिशेल स्टार्क को अंतिम-11 में देखना चाहते हैं। जॉनसन ने इसके पीछे लॉर्ड्स में 2.5 मीटर के स्लोप को कारण बताया है।

जॉनसन के कहा कि मैं स्टार्क को टीम में चुनूंगा और शायद पैटिंसन को बाहर रखूंगा। मैं जोश हैजलवुड को खेलते देखना चाहता हूं और आप पीटर सिडल को बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि स्टार्क काफी उपयोगी रहे हैं। खासकर स्लोप पर मुझे लगता है कि वह ज्यादा असरदार रहेंगे। उन्हें ऑफ स्पिनर नाथन लियोन का समर्थन भी अच्छे से मिलेगा। कमिंस अपनी दुनिया में हैं, उन्हें टीम में रहने दें। जॉनसन ने माना कि विजयी टीम में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी वह स्टार्क को टीम में देखना चाहते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि मैं स्टार्क को टीम में आते हुए देखना चाहता हूं। स्लोप उनकी मदद करेगा, वह बायें हाथ के गेंदबाज हैं तो उनके पास एक अलग एंगल है।

सुशील को आसानी से मिलेगा विश्व चैंपियनशिप का टिकट

योगेश शर्मा, नई दिल्ली

कुश्ती

▸ 74 किग्रा में दो बार के ओलंपिक विजेता कुमार के टक्कर का नहीं है कोई पहलवान

▸ सुशील का सामना करने के लिए तैयार धनकड़, जितेंद्र भी लेंगे ट्रायल में हिस्सा

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 14 से 22 सितंबर तक कजाखिस्तान में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आसानी से टिकट मिल जाएगा। दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में शनिवार या रविवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 74 किग्रा का ट्रायल होना है और सुशील के सामने कोई भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी पहलवान नहीं है। इस वर्ग के अलावा गैर ओलंपिक वर्ग 61 किग्रा, 70 किग्रा, 79 किग्रा, 92 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल के ट्रायल भी होंगे।

सुशील के अलावा इस वर्ग में प्रवीण राणा, जितेंद्र और अमित धनकड़ हिस्सा लेते हैं। राणा ने चोट के कारण इस ट्रायल से अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन वह सुशील को कभी हरा नहीं पाए हैं। इसके अलावा पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल में सुशील और राणा के बीच काफी विवाद हुआ था। राणा ने सुशील पर उनके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। सुशील के साथ अभ्यास करते हैं धनकड़ : इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए धनकड़ ने हामी भर दी है। उन्होंने दैनिक जागरण से कहा कि उनके सामने कोई भी आए, वह सिर्फ अपना ट्रायल जीतने की कोशिश करेंगे। धनकड़ शुरुआत से ही छत्रसाल अखाड़े में सुशील के साथ अभ्यास करते हैं। धनकड़ ने कहा, 'मैं सुशील का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। लेकिन, यह बड़ा ट्रायल हैं और मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं फिट हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने जितेंद्र हो या सुशील, मुझे सिर्फ अपना खेल खेलना है।' धनकड़ और सुशील का अभी तक कोई मुकाबला नहीं हुआ है और सुशील को जीत का दावेदार माना जा रहा है। धनकड़ के अलावा जितेंद्र के भी हिस्सा लेने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वह सुशील से कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में हार चुके हैं। जब इस वर्ग के ट्रायल के बारे में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के सूत्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा, '74 किग्रा में सिर्फ यही पहलवान हैं और मुझे लगता है कि सुशील को उन्हें हराने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वह आसानी से विश्व चैंपियनशिप का टिकट पा लेंगे। इस वर्ग में कम ही पहलवान हैं और सुशील के अलावा सिर्फ नरसिंह यादव ही एक दमदार पहलवान थे, लेकिन वह भी डोप में फंसे हुए हैं। यह वर्ग ओलंपिक का है और इसमें अच्छे पहलवानों का कम होना चिंता की बात है।'

अगले साल टोक्यो ओलंपिक के लिए कुश्ती का पहला क्वालीफायर टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप है और इसके लिए डब्ल्यूएफआइ ने पिछले महीने पुरुष फ्री स्टाइल के ट्रायल कराए थे लेकिन पहलवानों के चोटिल होने के कारण 74 किग्रा का ट्रायल नहीं कराया था। सुशील लगभग एक साल बाद मैट पर उतरे थे जब वह मिंस्क में मेदवेद टूर्नामेंट में 90 सेकेंड में बेकजोद अब्दुराखामोनोव से हार गए थे। फिर इसके बाद कांस्य पदक के मुकाबले में भी उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। सुशील विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल की तैयारी के लिए मेदवेद टूर्नामेंट में खेलने गए थे।

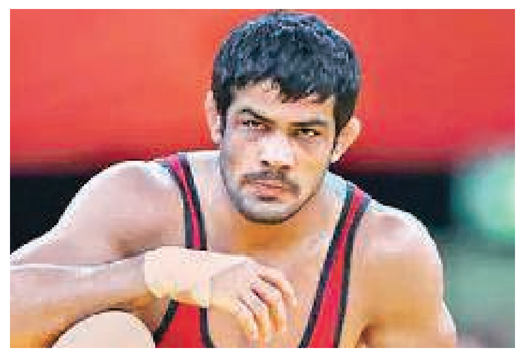

भारतीय पहलवान सुशल कुमार। फाइल फोटो, प्रेट्र

डुप्लेसिस से छीनी टी-20 की कमान, डिकॉक होंगे कप्तान

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए मंगलवार को अपनी टीम का एलान कर दिया। टीम की कप्तानी फाफ डुप्लेसिस से छीन कर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को दी गई है। दक्षिण अफ्रीका को 15 सितंबर से भारत का दौरा करना है। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका पहले तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगा और बाद में फाफ की कप्तानी में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा।

हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद ऐसी अटकलें थी कि डुप्लेसिस के हाथों से कमान जा सकती है और टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टी-20 टीम में ऐसा देखने को मिला है। टीम में तीन नए खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। टेंबा बावुमा, बजरेन फॉर्टयुइन और तेज गेंदबाज एनरिक नोर्टजे टीम में आए हैं। टेस्ट टीम में भी तीन नए चेहरे हैं। नोर्टजे के अलावा यहां सेनुरान मुथुसामी और रूड़ी सेकंड को टीम में जगह मिली है। रेसे वेन डेर डुसेन को टी-20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। वहीं टेंबा टेस्ट टीम के उप कप्तान होंगे। टी-20 में एडेनन मार्करैम, थेयुनिस डि ब्रूयन और लुंगी नगिदी को जगह नहीं मिली है।

फाफ डु प्लेसिस। फाइल फोटो, एपी

टी-20 टीम : क्विंटन डिकॉक (कप्तान), रेसे वेन डेर डुसेन, टेंबा बावुमा, जूनियर डाला, बजोर्न फॉर्टयुइन, बेयूरन हैंड्रिक्स, रीजा हैंड्रिक्स, डेविड मिलर, एनरिक नोर्टजे, एंदिले फेलुकवायो, ड्वेन प्रिटोरियस, कैगिसो रबादा, तबरेज शम्सी, जोन-जोन स्मुट्स।

टेस्ट टीम : फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), टेंबा बावुमा (उप कप्तान), थेयुनिस डि ब्रूयन, क्विंटन डिकॉक, जुबायर हमजा, केशव महाराज, एडेन मार्करैम, सेनुराह मुथुसामी, लुंगी नगिदी, एनरिक नोर्टजे, वर्नेन फिलेंडर, डेन पिएड्ट, कैगिसो रबादा, रूडी सेकंड।

चोट के बाद सिंगल्स में वापसी करते हुए हारे मरे

टेनिस

सिनसिनाटी, एएफपी : तीन बार के ग्रैंडस्लैम विजेता एंडी मरे को यहां सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा। 32 वर्षीय मरे सिंगल्स में वापसी करते हुए पहले ही दौर में रिचर्ड गास्केट के खिलाफ मुकाबला हार गए। सात महीने में पहला सिंगल्स मैच खेल रहे मरे को गास्केट के खिलाफ सीधे सेटों में 4-6, 4-6 से हार झेलनी पड़ी। यह मैच 96 मिनट तक चला।

करियर को खतरे में डालने वाली कूल्हे की चोट के कारण जनवरी में सिंगल्स मैचों से दूर हुए मरे ने हालांकि अपने इस प्रदर्शन को ठीक करार दिया। मरे ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि इस मैच से मैंने क्या उम्मीद की थी। इस मैच में कई ऐसी चीजें थीं जो मैं बेहतर करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आपको अपनी उम्मीदों में वास्तविकता रखनी होगी। मैं मैच के दौरान शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा था।' मरे ने कूल्हे की सफल सर्जरी कराने के बाद पुरुष डबल्स के मुकाबले खेलने शुरू किए थे।

अमेरिकी ओपन के सिंगल्स में नहीं खेलेंगे मरे : पूर्व विश्व नंबर एक ब्रिटेन के एंडी मरे ने साथ में यह भी घोषणा की है कि वह 26 अगस्त से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन के सिंगल्स में नहीं खेलेंगे। मरे ने कहा, 'यह वह निर्णय था जो कि मैंने अपने टीम के साथ किया था। मैं वाइल्ड कार्ड नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं एक मैच के बाद कैसा महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद के प्रति निष्पक्ष होना चाहता हूं। इस तरह का फैसला करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ मैच खेलूं।' सिनसिनाटी टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों में अमेरिकी ओपन के पूर्व विजेता मारिन सिलिक भी सिंगल्स में पहले दौर का मुकाबला सीधे सेटों में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिलिक को राडू अल्बोट ने 6-4, 7-6 से हराया। वहीं, सैमी क्वेरी ने फ्रांस के पियरे ह्यूगस हर्बर्ट को 7-6, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई, जहां उनका सामना शीर्ष वरीय और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक से होगा। इसके अलावा सात बार के विजेता रोजर फेडरर अपने अभियान की शुरुआत दूसरे दौर के मुकाबले से करेंगे, जहां उनका सामना अर्जेंटीना के जुआन इग्नासियो लोंडेरो से होगा, जिन्होंने इटली के मेटेयो बेरेटिनी को 7-6, 6-3 से हरा दिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को सीधे सेटों में 7-5, 6-4 से हरा दिया।

शारापोवा दूसरे दौर में

सिनसिनाटी : 2011 की विजेता और पांच साल बाद सिनसिनाटी मास्टर्स में खेल रहीं रूस की महिला खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में अमेरिका की एलिसन रिस्क को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं, अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने हमवतन लौरेन डेविस को 7-5, 6-2 से मात दी। 2017 के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली ब्रिटेन की जोहान कोंटा पहले दौर में रेबेका पीटरसन से 3-6, 6-3, 5-7 से हार गईं।

मैच हारने के बाद दर्शकों का अभिवादन करके कोर्ट से लौटते एंडी मरे। एपी

विजेता

इंग्लैंड में त्रिकोणीय अंडर-19 सीरीज जीतकर लौटी युवा भारतीय टीम, कप्तान प्रियम गर्ग ने अपने प्रदर्शन से किया चयनकर्ताओं को प्रभावित

उम्मीदों तले दबती नहीं आज की युवा पीढ़ी

निखिल शर्मा, नई दिल्ली

यशस्वी जायसवाल, प्रियम गर्ग, पूर्णांक त्यागी, ध्रुव जुरेल, कार्तिक त्यागी, समीर रिजवी ये वो नाम हैं जिनके कंधों पर आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी हो सकती है। कभी युवा पीढ़ी के पास टीम इंडिया में पहुंचने के लिए सिर्फ बीसीसीआइ की घरेलू ट्रॉफियों में शानदार प्रदर्शन सीढ़ी की तरह होता था। पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में अब एक अहम बदलाव इन युवा खिलाड़ियों को खुद को तराशने का मौका दे रहा है। यह बदलाव है अंडर-19 टीम के ज्यादा मैच। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के प्रियम गर्ग की कप्तानी में इंग्लैंड में हुई त्रिकोणीय सीरीज का खिताब जीतकर लौटी भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ी सीरीज जीतकर खुश हैं, लेकिन उनके अंदर उम्मीदों के तले दबने का डर नहीं है। अकेले मेरठ शहर से 18 सदस्यीय टीम में चार खिलाड़ियों ने जगह बनाई। अपने शहर पहुंचे प्रियम जहां अब 17 अगस्त से शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी की तैयारियों में जुटेंगे, जबकि तेज गेंदबाज पूर्णांक तीन से 15 सितंबर तक श्रीलंका में होने वाले यूथ एशिया कप की तैयारी करेंगे। वहीं कार्तिक त्यागी और समीर आने वाले घरेलू सत्र की तैयारियां करेंगे।

इंग्लैंड से स्वदेश लौट भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के सदस्य पूर्णांक त्यागी, कप्तान प्रियम गर्ग और समीर रिजवी। जागरण

हर मौके को भुनाना चाहता हूं : प्रियम

अंडर-19 टीम के कप्तान रहे प्रियम ने कहा कि यह दौरा तैयारियों के लिए अच्छा रहा। अच्छा अनुभव मिला। अच्छा विकेट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थीं। खासकर बल्लेबाजों को बहुत कुछ सीखने को मिला। दलीप ट्रॉफी की तैयारियों पर दायें हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि यह मेरे लिए एक मौका है। मैं हर मौके को भुनाना चाहता हूं। मेरे अंडर-19 के प्रदर्शन को देखते हुए ही यूपीसीए प्रमुख राजीव शुक्ला सर और सचिव डॉ. युद्धवीर सिंह सर ने मुझे रणजी में मौका दिया। यूथ क्रिकेट पर प्रियम ने कहा कि इससे बहुत खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। यह युवा खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अच्छा है। मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं।

विविधता नहीं, अभी तकनीक अहम : पूर्णांक

टीम के तेज गेंदबाज पूर्णांक ने कहा कि वहां परिस्थिति अलग और काफी चुनौतीपूर्ण थीं। परिस्थिति की वजह से वहां जल्दी गए। धूप-बादल आते रहते हैं, फर्क पड़ता है। मुझे काफी सीखने को मिला। एशिया कप की तैयारियों पर पूर्णांक ने कहा कि वहां मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। बल्लेबाजों की मुफीद सीमित ओवर क्रिकेट पर विविधता सीखने पर पूर्णांक ने कहा कि हमारी क्रिकेट में हम तकनीक पर ध्यान रखते हैं। विविधता सीखते जरूर हैं, लेकिन उसे मैच में अमल में नहीं लाते हैं, सारा फोकस सिर्फ तकनीक पर ध्यान देने पर होता है। उन्होंने कहा कि गति और लेंथ दोनों पर ध्यान लगाना अहम है। यह एक-दूसरे के पूरक हैं।

द्रविड़ का मंत्र : ईमानदारी से खेलो

17 वर्ष के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने कहा कि राहुल द्रविड़ सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह कहते हैं कि जब भी खेलो ईमानदारी से खेलो, कभी बेईमानी नहीं। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो खुद चले जाना है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास अंडर-19 में दो साल हैं। मैं यहीं से सीनियर टीम में जाना चाहता हूं क्योंकि आगे हालात मुश्किल हो जाते हैं। द्रविड़ का क्षेत्ररक्षण पर खास फोकस रहता है। समीर ने कहा कि क्षेत्ररक्षण के लिए एनसीए में हमारा कैंप होता है। यहां सॉफ्ट बैड पर कैच होते हैं। कूदने की तकनीक सिखाते हैं। स्लाइड के लिए कवर पर पानी-सर्फ डालकर अभ्यास कराते हैं।

7 राज्यों के 1500 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अंगदान की शपथ ली है। एक जुलाई को सीए-डे से सात जुलाई तक यह अभियान चलाया गया था। सीआइआरसी चेयरमैन केंद्रीय मंत्री को एकत्र हुए फार्म सौंपेंगे।

मौत के जबड़े से सीता बचा लाईं थीं 18 मासूमों की जिंदगी

अपने पौत्र के साथ सीता शुक्ला। जागरण

मुहम्मद इब्राहिम, भदोही

जय हिंद

ताकत वतन की हमसे है...

- लपटों से घिरी वैन में कूद गई थीं पल्लू बांधकर, मासूमों को सही सलामत निकाला था
- लखनों में सिलेंडर रिसाव से लगी थी आग, दिखाया अदम्य साहस

12 जनवरी 2019 की ठिठुरती रात किसी तरह गुजरी तो सुबह लोग दैनिक क्रिया में जुट गए। इसी बीच जानपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनों गांव में 18 मासूमों से भरे एक अमान्य स्कूल की वैन में गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लग गई। पलक झपकते धू-धूकर जली वैन से लगा कि मौत उन मासूमों को मौत के आगोश में लेने को झपट्टा मार रही हो। बच्चों को उनके घर से लेकर स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने वाला चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बच्चे मदद को छटपटा रहे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मंजर को निहारती तमाशबीन भीड़ अभी क्या करें कि सोच रही थी कि अदम्य साहस व हौसले की मिशाल पेश करती 60 वर्षीय सीता शुक्ला मासूमों की मौत व जिंदगी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई।

आग का शोला बन चुकी वैन की जद में आने से सीता शुक्ला खुद झुलसती रहीं, लेकिन उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक सभी बच्चों को मौत के जबड़े से खींचकर बाहर नहीं निकाल लिया। उनकी इस बहादुरी का ही परिणाम रहा कि वैन में फंसे 15 बच्चे आज अपने परिवार में सलामत हैं। हालांकि, उनके प्रयास के बाद भी गंभीर रूप से जल चुके तीन मासूमों ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

बहू ने निभाया भरपूर साथ : जब घटना घटी सीता अपने दरवाजे के सामने अलाव ताप रही थीं। सब कुछ ठीक लग रहा था तभी पहुंची स्कूल वैन में आग देख वह फंसे बच्चों को निकालने में जुट गईं। इसी बीच घर से निकली उनकी बहू सुमन नजारा देख हतप्रभ रह गईं। उन्हें अकेले जूझते देख वह भी मासूमों को सुरक्षित निकालने में जुट गईं और भरपूर साथ निभाया।

सहन नहीं हुई बच्चों की तड़प : 12 जनवरी को अचानक सामने आए उस मंजर को याद कर सीता शुक्ला यादों में खो जाती हैं कि आग की लपटों के बीच घिरे वैन का गेट बंद हो चुका था। अपनी ओर बढ़ती मौत को देख तड़पते बच्चे मदद की गुहार लगा रहे थे। मासूमों की तड़प देखी नहीं गई और वह पल्लू बांधकर उन्हें बचाने में जुट गईं। उन्हें अपने इस साहसिक प्रयास पर गर्व तो है लेकिन बाद में तीन बच्चों की मौत और मासूमों सहित अपने शरीर पर आ चुके दाग की टीस भी चेहरे पर साफ झलकती है। बताया जाता है कि उनके पुत्र बद्री शुक्ला के दो बेटे अनमोल व अभिषेक भी फंसे थे। दोनों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अनमोल अभी तक ठीक नहीं हो सका है।

अब तक 50 निर्धन बच्चों को बना चुके अफसर

लगन ▶ गरीब बच्चों के लिए खोल चुके हैं 12 पुस्तकालय, परीक्षा के दौरान लाइब्रेरी को बना देते हैं छात्रावास

मनोज सिंह, जमशेदपुर

संजय कच्छप ने खुद तो कांटों की चुभन सही, लेकिन गांव के गरीब बच्चों के लिए वरदान बनकर उभरे। इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि जब कभी वह सक्षम होंगे तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पैसे के अभाव में बंद नहीं होने देंगे। कारण, बचपन में वह खुद एक-एक पैसे के लिए मोहताज थे। वह 2005 में रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत तीन अलग-अलग पद की नियुक्ति परीक्षा में सफल हो गए तो परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। 2008 में संजय ने झारखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास की और आज वह जमशेदपुर में कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव हैं।

नौकरी मिलने के बाद से वह अपना अधिकतर समय गरीब बच्चों का भविष्य गढ़ने में लगा रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल में दर्जन भर से अधिक लाइब्रेरी खोल कर वह बच्चों को किताब खरीदने की परिपाटी से दूर कर रहे हैं। खुद क्लास भी लेते हैं। इनके शिक्षण से अब तक 50 से अधिक गरीब बच्चे अधिकारी बन चुके हैं। आज भी संजय अपना आधा वेतन गरीब छात्रों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। जिस सरकारी आवास में वह रहते हैं वहां भी उन्होंने पुस्तकालय बनाया है। यहां दूरदराज के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। इन्होंने आसपास के कई गांव में किराये पर घर लेकर पुस्तकालय खोला है, जहां बच्चे पढ़ाई तो करते ही हैं, परीक्षा के दौरान वहीं रहते भी हैं। कुछ पुस्तकालय नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी हैं। पुस्तकालय में 11 हजार से अधिक किताबें हैं। इनके प्रयास से चाईबासा के मनोज खलखो (सहायक प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक) व पंकज रवि (सहायक प्रबंधक आइडीबीआइ) के अलावा 50 से अधिक बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं।

जमशेदपुर के परसुडीह स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप अपना समय गरीब बच्चों का भविष्य गढ़ने में भी लगा रहे हैं। जागरण

अब डिजिटल क्लासरूम : चक्रधरपुर स्थित कोलचकड़ा के पास कुडख गांव में संजय कच्छप ने एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली है, जहां सात कंप्यूटर हैं। दूरदराज के गांवों के बच्चे यहां कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। संजय कहते हैं कि वह बहुत जल्द यहां डिजिटल क्लासरूम खोलेंगे, ताकि गरीब बच्चे भी बेहतर व आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। संजय कच्छप की इस मुहिम से प्रभावित होकर अब कई संस्थाओं के लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई अजय कच्छप व एक रिश्तेदार विकास टोप्पो दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही पांच युवकों को तकनीकी शिक्षा दिला रहे हैं।

अब तक 12 पुस्तकालय : संजय अब तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में 12 पुस्तकालय खोल चुके हैं। इसके अलावा मनोहरपुर व चक्रधरपुर (प. सिंहभूम), सीतारामडेरा (जमशेदपुर), घाटशिला (पू. सिंहभूम), भालूपानी राजनगर, कुचाई व खरसावां (सरायकेला-खरसावां) में पुस्तकालय के लिए काम शुरू हो चुका है।

स्वतंत्रता के सारथी
हर हाथ को काम

अब तक खोले पुस्तकालय

- कुडख पुस्तकालय, चाईबासा
- आदिवासी पुस्तकालय, ईचापुर झींकपानी
- सरना पुस्तकालय, चाईबासा
- आदिवासी पुस्तकालय, चक्रधरपुर
- कुडख डिजिटल लाइब्रेरी, चक्रधरपुर
- बिरसा मुंडा पुस्तकालय, चक्रधरपुर
- तिलका मांझी पुस्तकालय, घाटशिला
- कुडख पुस्तकालय, चाईबासा
- कार्तिक उरांव पुस्तकालय, खरसावां
- कार्तिक उरांव पुस्तकालय, चाईबासा
- डा. भीमराव पुस्तकालय, प. सिंहभूम
- कार्तिक उरांव पुस्तकालय, रांची

मध्य प्रदेश की 'सिटी ऑफ जॉय' मांडू अब विश्व धरोहर की राह पर

राजीव सोनी, भोपाल

'सिटी ऑफ जॉय' के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मांडू को अब विश्व धरोहर बनाने के लिए सरकार ने भी जतन शुरू कर दिए हैं। दो दशक से मांडू का नाम यूनेस्को तक भेजा जा रहा है, लेकिन कोई न कोई दस्तावेजी कमी उसे विश्व विरासत का दर्जा दिलाने से रोक देती है। मध्यप्रदेश सरकार ने अब मांडू का डोजियर तैयार कर केंद्र सरकार की मदद से यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है।

विंध्याचल की पहाड़ियों में बसे करीब 1400 साल पुरातात्विक इतिहास समेटे इस धरोहर की खूबसूरती का जिक्र विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज 'जहांगीरनामा और अकबरनामा' में भी दर्ज है। जहांगीरनामा में तो मांडू को 'श्रावण माह में धरती का सबसे खूबसूरत स्थल' बताया गया है। मांडू में एक साथ कई खूबियां मौजूद हैं, विश्व विरासत के लिए 'मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के रूप में दावा किया गया है। सरकार का दावा है कि यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10 में से तीन मानदंडों पर मांडू पूरी तरह खरा उतरता है, जबकि विश्व धरोहर के लिए एक मानदंड पूरी करना ही पर्याप्त माना जाता है। मप्र में अभी सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर और भीमबैठिका को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है।

मांडू का प्रशिद्ध जहाज महल। फाइल

मांडू में विश्व धरोहर बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। यूनेस्को के समक्ष हम इस बार पूरी तैयारी से अपना दावा पेश करेंगे। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री सहित अन्य सभी विभागों की मदद भी मांगेंगे।

– सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, मंत्री, पर्यटन व नर्मदा घाटी विकास मप्र

तैयार कराया डोजियर : पर्यटन विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने वास्तुविद गरिमा राजपूत से मांडू पर केंद्रित दो हजार पेज का डोजियर तैयार करवाया है। गरिमा बताती हैं कि इसमें 13 नक्शों की सहायता से मांडू के 63 प्रमुख और 100 से अधिक सभी स्मारकों का ब्योरा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के पलोड़ी गांव के आदिवासी अब देखेंगे आजादी का नया सवेरा

आकाश शुक्ला, रायपुर

रामायण काल का दंडकारण्य। जितना दुरूह उतना ही अबूझ। शायद तभी यहां के जंगल को अबूझमाड़ के नाम से जाना गया। यहां जंगल के बीच बसे हैं सैकडों आदिवासी गांव। ऐसा ही एक गांव है पलोड़ी। यहां आजादी का जश्न तो आदिवासियों ने भी मनाया था, लेकिन ढिबरी युग से बाहर की चकाचौंध कभी नहीं देखी। आजादी के 73 वर्ष गुजरने के बाद अब इनके घरों में बिजली की रोशनी से बल्ब जगमगाए तो उत्साह को परवान चढ़ना ही था। ग्रामीण कहते हैं कि आजादी का उजाला तो उन्होंने अब देखा है।

सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला ग्राम पलोड़ी बरसों से लाल आतंक की त्रासदी झेल रहा है। यहां पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। यहां के ग्रामीण अपने जिला मुख्यालय भी तब जा पाते हैं जब वह 130 से 150 किमी का सफर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना की सीमा लांघ करते हैं। यही वजह है, कि नक्सलियों के खौफ से वर्षों तक इस क्षेत्र को विकास की मूलधारा से नहीं जोड़ा जा सका है। इसके चलते आज भी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों का पूरा करने के लिए यहां के आदिवासी आंध्र और तेलंगाना पर निर्भर हैं। इन्हें मूलधारा में वापस लाने और बिजली पहुंचाने की योजना पर भी तब साकार हो सकी, जबकि जवानों ने खून-पसीना बहाया।

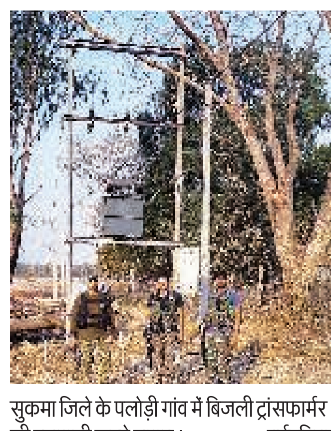

सुकमा जिले के पलोड़ी गांव में बिजली ट्रांसफार्मर की रखवाली करते जवान। नईदुनिया

24 घंटे पहरेदारी में बिछी 20 किमी की बिजली लाइन : अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर पर बसे छत्तीसगढ़ के पलोड़ी समेत आसपास के गांवों में लगभग 20 से 25 किमी बिजली लाइन बिछाई गई। कोबरा बटालियन, डीआरजी और सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों की निगहबानी में लगभग दो से तीन महीने तक चले ऑपरेशन के बाद मई महीने में अंततः गांव कि बिजली पहुंच गई।

- दुर्गम क्षेत्र और नक्सल खौफ के बीच आसान नहीं था गांव में बिजली पहुंचाना
- 60 दिनों से अधिक का समय, सुरक्षा बलों की 24 घंटे निगहबानी से संभव हो पाया ऑपरेशन उजाला

पलोड़ी सहित आसपास के लगभग आठ से दस गांव में बिजली लाइन का विस्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ से कटे होने के कारण तेलंगाना से बिजली ली जा रही है। दुर्गम इलाकों में जवान पैठबनाकर नक्सलियों को खदेड़ने में जुटे हैं। **– शलभ सिन्हा, एसपी, जिला सुकमा**

बस्तर संभाग के कई इलाके पहुंचविहीन और नक्सल प्रभावित होने की वजह से लाइनों का विस्तार करना काफी मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा बलों के सहयोग से उन इलाकों में भी बिजली का विस्तार किया जा रहा है। ताकि आदिवासियों को बिजली सेवा से जोड़कर विकास की मूलधारा से जोड़ा जा सके।

– शैलेंद्र शुक्ला, चेयरमैन, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज।

अशफाक उल्लाह खां को मिलती थी राजाराम से प्रेरणा

मातृवेदी का काम संभालने वाले राजाराम एक डकैती में थे शामिल, इस डकैती से मातृवेदी के कोष में आए थे 10 हजार रुपये

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

जय हिंद

मातृवेदी के बलिदानी

कहानी–7

▶ अशफाक ने अपनी डायरी में लिखा– 'मैं इस मामले में मास्टर साहब से पूछने को झुका, मगर मास्टर साहब बताने से डरे'

देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अशफाक उल्लाह खां को कौन नहीं जानता, मगर उनके प्रेरणा पुरुष के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। लखीमपुर के मोहम्मदी में 1898 में जन्मे राजाराम भारतीय ने शाहजहांपुर मिशन स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के दौरान सशस्त्र क्रांति की राह चुनी तो सातवीं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी उनके व्यक्तित्व पर फिदा हो गया। यह विद्यार्थी बड़ा हुआ तो अपनी डायरी में उनका जिक्र किया। शहीद-ए-वतन अशफाक की यह डायरी बताती है कि राजाराम भारतीय उनके प्रेरणा पुरुष रहे।

काकोरी कांड के अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह खां ने अपनी डायरी में लिखा- 'मैं इस मामले में मास्टर साहब से पूछने को झुका, मगर मास्टर साहब बताने से डरे। एक लड़के ने कहा कि राजाराम ने कहीं डाका मारा है और कुछ दूसरे लड़के भी गिरफ्तार हुए हैं, अब मुझे राजाराम की फिक्र हुई कि यह लड़का कौन है? क्योंकि राजाराम एक सीधा और खामोश लड़का था। यूं अक्सर तल्बा-ए-स्कूल उससे वाकिफ न थे। दरजे के एक मेरे साथी ने मुझको अलहदा ले जाकर कहा- राजाराम एक खुफिया सोसाइटी का मेंबर है, न डाकू है, न कातिल।' मातृवेदी के कई सारे काम संभालने वाले राजाराम 23 जून 1918 को हरदोई के परेली गांव की डकैती में शामिल थे। इस राजनीतिक डकैती से मातृवेदी के कोष में 10 हजार रुपये का इजाफा हुआ था। 'मातृवेदी-बागियों की अमर गाथा' पुस्तक में शाह आलम ने बताया है कि उन दिनों आयरलैंड और रूस के क्रांतिकारी गुप्त पार्टी के संचालन के लिए ऐसे ही एक्शन को अंजाम देते थे।

मकान से मिले थे 242 पर्चे : मैनपुरी षडयंत्र केस में गिरफ्तार होने के बाद राजाराम भारतीय के मकान से पुलिस ने 242 पर्चे बरामद किए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी गवाह सोमदेव शर्मा ने बताया था कि ये पर्चे देवनारायण का लिखा हुआ है, जो मातृवेदी दल में शिवकृष्ण, गंगा सिंह और रामप्रसाद का छद्म नाम है। इस केस में राजाराम भारतीय को तीन साल कठोर कारावास की सजा हुई। इसके बाद भी वह मिशनरी भाव से देशसेवा में जुटे रहे।

प्रतीकात्मक चित्रण। जागरण

चंद्रधर के कंठ से निकलता था अंग्रेजों के खातिर 'हलाहल'

एटा के चंद्रधर जौहरी को भी याद किया जाना चाहिए। इनकी आवाज में गजब की ताकत थी। इससे डरकर अंग्रेज जज ने उन्हें पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद भी इनकी वाणी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग उगलती रही। 30 अक्टूबर 1895 में जन्मे चंद्रधर जौहरी के पिता एटा गवर्मेंट हाईस्कूल में हेडमास्टर थे। पिता की मौत के बाद चंद्रधर मैनपुरी आकर रहने लगे। यहीं अपने छोटे भाई चंद्रभाल जौहरी के साथ मिशन हाईस्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इसी दौरान मातृवेदी दल से जुड़ाव हुआ। जौहरी ने कांतिकारियों के द्रोणाचार्य गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर विभिन्न जिलों में मातृवेदी का विस्तार किया। एक दिन जब चंद्रधर गुप्त बैठक के बाद शिवकृष्ण के साथ बाहर जा रहे थे तभी गिरफ्तार कर लिए गए। जज किश ने कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि इन्होंने राष्ट्रीय गीत गा–गाकर नौजवानों में रक्त का संचार करने का अपराध किया है। लिहाजा इन्हें पांच वर्ष की सख्त सजा दी जाती है।

थर्मल पॉवर प्लांट की जमीन से सोलर एनर्जी का बन रहा प्लान

नईदुनिया, रायपुर

- छत्तीसगढ़ के कोरबा पूर्व संयंत्र की 50–50 मेगावॉट की चार यूनिटें हो गई हैं बंद
- सरकार ने जमीन के उपयोग का फैसला करने के लिए कंपनी प्रबंधन को कर दिया है अधिकृत

छत्तीसगढ़ में बंद किए गए एक सरकारी थर्मल पॉवर प्लांट की जमीन से सोलर एनर्जी के उत्पादन की संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि, बंद किए गए संयंत्र की जमीन को खाली करने में अभी वक्त लग सकता है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि बंद की गई चार यूनिटों के साथ दो और यूनिट हैं, जो चालू हैं। इस बीच बिजली कंपनी प्रबंधन में खाली होने वाली जमीन के उपयोग को लेकर प्रारंभिक चर्चा हुई है। बिजली कंपनियों के अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि जमीन के उपयोग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसमें वक्त लग सकता है। वैसे सोलर यूनिट की स्थापना बेहतर विकल्प हो सकता है।

53 वर्ष पुरानी हो चुकी थी यूनिटें : बिजली अफसरों के अनुसार कोरबा पूर्व संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 440 मेगावॉट थी। इसमें 50-50 मेगावॉट की चार और 120 मेगावॉट की दो यूनिटें शामिल हैं। 50 मेगवॉट के पहले संयंत्र से करीब 53 वर्ष पहले 22 अक्टूबर 1966 में उत्पादन शुरू हुआ था। दूसरी यूनिट 1967, तीसरी और चौथी यूनिट 1968 में चालू हुई। वहीं 120 मेगावॉट की दो यूनिटें क्रमशः 1976 और 1981 में शुरू हुई।

तीन वर्ष से बंद था उत्पादन : 50 मेगावॉट की चारों यूनिटों से करीब तीन वर्ष से उत्पादन बंद था। पुरानी होने की वजह से इन संयंत्रों से उत्पादन महंगा पड़ रहा था। साथ ही प्रदूषण भी अधिक हो रहा था। इसी वजह से 2017 के पहले इन यूनिटों को बंद कर दिया गया था। अब सरकार ने आधिकारिक रूप से इन संयंत्रों को बंद करने की घोषणा के साथ खाली होने वाली जमीन के उपयोग के लिए बिजली कंपनी प्रबंधन को अधिकृत किया है।

सोलर प्लांट की फाइल फोटो।

इस वजह से सोलर पर विचार : छत्तीसगढ़ में निजी और सरकारी क्षेत्र के छोटे-बड़े करीब दो दर्जन थर्मल पॉवर प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 22 हजार मेगावॉट से अधिक है। थर्मल प्लांट्स के कारण न केवल प्रदूषण का खतरा रहता है बल्कि वहां से निकलने वाली फ्लाइ एश भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में सरकार अब नए थर्मल प्लांट के पक्ष में नहीं है। चूंकि प्लांट औद्योगिक क्षेत्र में है और आसपास दूसरे पावर प्लांट है। इस वजह से वहां सोलर संयंत्र को ही बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

छह एकड़ जमीन पर एक मेगावॉट का संयंत्र : गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जानकार अफसरों के अनुसार एक मेगावॉट का सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए करीब छह एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 200 मेगावॉट के थर्मल यूनिट को बंद करके वहां बड़े सोलर प्लांट की स्थापना की जा सकती है।

दर्शनीय

मानसून सीजन में भी बड़ी तादाद में फूलों की घाटी का रुख कर रहे देशी–विदेशी पर्यटक, एक जून से अब तक घाटी में पहुंच चुके हैं 11753 पर्यटक, इनमें 314 विदेशी पर्यटक शामिल

रोजाना 500 पर्यटक कर रहे फूलों की घाटी का दीदार

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

मानसून सीजन के चलते जहां चारों धाम में यात्रियों की संख्या सिमटकर रह गई है, वहीं विश्व धरोहर फूलों की घाटी में पर्यटकों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ रही है। एक जून से अब तक घाटी में 11753 पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिनमें 314 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। घाटी में पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन व्यवसायी भी बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार घाटी में पर्यटकों की आमद का नया रिकॉर्ड बन सकता है।

सीमांत चमोली जिले में समुद्रतल से 12995 फीट की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली फूलों की घाटी में इन दिनों 300 से अधिक प्रजाति के रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं। साथ ही कल-कल करते बह रही पुष्पावती नदी, झरनों का सुमधुर संगीत, दूर-दूर तक नजर आते बर्फीले पहाड़, परिंदों की चहचहाट व दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की चहलकदमी घाटी के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। इससे मंत्रमुग्ध पर्यटक घाटी की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो रोजाना 500 के आसपास पर्यटक फूलों की घाटी के दीदार को पहुंच रहे हैं।

चमोली स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी का खूबसूरत नजारा। घाटी के इन नजारों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जागरण

वन क्षेत्राधिकारी फूलों की घाटी बृजमोहन भारती ने बताया कि वीकेंड पर तो पर्यटक सीधे घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। इन दिनों घाटी अपनी पूरी रंगत में है, जिससे पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। अगस्त में हमेशा ही पर्यटक बड़ी तादाद में घाटी का रुख करते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या बीते वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। बताया कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन को अब तक पर्यटकों से 14 लाख दस हजार 900 रुपये की आय हो चुकी है।

छह वर्षों में फूलों की घाटी पहुंचे पर्यटक

वर्ष	पर्यटक (11 अगस्त तक)
2019	11753
2018	14712
2017	13752
2016	6503
2015	181
2014	484

यही 'नंदकानन', यही 'अलका' : 'स्कंद पुराण' के केदारखंड में भ्यूंडार स्थित फूलों की घाटी को 'नंदकानन' नाम दिया गया है। जबकि, महाकवि कालिदास ने इसका 'अलका' नाम से वर्णन किया है। इसके अलावा 'गंदमादन', 'पुष्पावती', 'पुष्प रस', 'भ्यूंडार', 'देवद्वार', 'वैकुंठ' आदि नामों से विभिन्न ग्रंथों में इस घाटी का जिक्र हुआ है।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा होगी जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति संभव है। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली का मौसम उमस के साथ गर्म रहेगा तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/25/व	अहमदाबाद	33/25/आंबा
कोलकाता	35/27/आंबा	बड़ौदा	32/25/व
चेन्नई	35/27/आंबा	नागपुर	30/22/आंबा
हैदराबाद	32/25/व	इन्दौर	26/23/व
बंगलूरू	26/20/व	राँची	35/25/आंबा
त्रिवेन्द्रम	29/22/व	पटना	36/28/आंबा
गुवाहाटी	31/25/आंबा	जमशेदपुर	36/26/आंबा
गंगटोक	17/09/व	पुणे	24/22/आंबा

© Copyright Skymet Company 2019: All rights reserved.

मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन लागू करने वाला पहला देश बना फ्रांस

1893 में आज ही फ्रांस में पेरिस पुलिस ऑर्डिनेंस के पारित होने के बाद गाड़ियों का पंजीयन किया जाना शुरू हुआ। सभी गाड़ियों पर उनके मालिकों का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य किया गया। पंजीयन दस्तावेज 1899 में बनाए गए।

सबसे ज्यादा समय तक प्रदर्शित होने वाली फिल्म रिलीज हुई

1975 में आज ही दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रदर्शित की जाने वाली साइ-फाइ हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द रॉकी हॉरर पिक्चर शो' लंदन में रिलीज हुई। शुरुआत में इसे लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया लेकिन देखते ही देखते दुनिया इसकी मुरीद हो गई। आज भी हैलोवीन के समय इसे दिखाया जाता है।

चहेते हास्य कलाकार जॉनी लीवर को जन्मदिन मुबारक

अपनी बेजोड़ संवाद अदायगी और बेमिसाल भाव-भंगिमाओं से दर्शकों को गुदगुदाने वाले जॉनी लीवर का जन्म 1957 में आज ही आंध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में हुआ। उनका असल नाम जॉन राव प्रकाश राव जानुमाला है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करते समय उन्होंने एक बार कुछ उच्चाधिकारियों की नकल उतारी। तभी से उनका नाम जॉनी लीवर हो गया। 1982 में फिल्मी करियर शुरू हुआ। 1993 में बाजीगर फिल्म में बाबूलाल के किरदार ने लोकप्रिय बनाया। जॉनी ने अब तक 350 से अधिक फिल्में की हैं। दो बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है।

इधर-उधर की

प्लास्टिक के कचरे से खरीदें बस टिकट

जकार्ता, एजेंसी : इस वक्त प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन हुआ है। ऐसे में इंडोनेशिया में भी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए नई पहल शुरु हुई है। दरअसल, शहर सुरबाया के बस स्टॉप पर दर्जनों यात्री प्लास्टिक की बोतलें और डिस्पोजेबल कप लेकर खड़े रहते हैं। यदि आप इस प्लास्टिक के कचरे को देते हैं तो आप बस की टिकट खरीद सकते हैं। हर हफ्ते करीब 16 हजार यात्री प्लास्टिक कचरा देकर बस की टिकट खरीद रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को एक घंटे तक बस में सफर करना है तो उसे बस तीन बड़ी बोतलें, पांच मध्यम बोतलें या 10 प्लास्टिक कप देने होंगे। मगर, बोतलें साफ होनी चाहिए और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया समुद्र को प्रदूषित करने के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वहां की सरकार ने तय किया है कि वह 2025 तक समुद्र में फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे को करीब 70 फीसद तक कम करेगा।

चार्जिंग केबल से भी चोरी हो सकता है डाटा

रहें सतर्क ▶ कोई भी केबल इस्तेमाल करने में बरतें सावधानी, सुरक्षा पर उठे सवाल

केबल के जरिये किसी भी डिवाइस में वायरस भेज सकते हैं हैकर

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : अक्सर ऑफिस या किसी यात्रा पर जाने के दौरान हम अपने स्मार्टफोन या आइपैड की चार्जिंग केबल साथ में ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में जब फोन चार्ज करना हो तो हमें किसी से चार्जिंग केबल मांगनी पड़ती है। उसे इस्तेमाल करने से पहले हम केबल के सुरक्षित या असुरक्षित होने पर ध्यान हीं नहीं देते। अब एक हैकर ने इन चार्जिंग केबल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि चार्जिंग केबल के जरिये भी यूजर का डाटा चोरी किया जा सकता है। ऐसे में बिना सोचे-समझे किसी की भी चार्जिंग केबल इस्तेमाल करना घातक हो सकता है।

एक रिपोर्ट में एमजी नामक हैकर ने कहा, 'कई लोग पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के इस्तेमाल के प्रति तो सचेत रहते हैं लेकिन यूएसबी केबल को खतरा नहीं मानते।' एमजी ने ही एपल के यूएसबी पोर्ट में लगने वाली चार्जिंग केबल का नमूना तैयार किया है। ओ.एमजी नामक यह नकली केबल बाहर से किसी अन्य चार्जिंग केबल की तरह ही दिखती है। लेकिन इस केबल के जरिये हैकर किसी भी डिवाइस में वायरस आदि ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके लिए उस डिवाइस का वाई-फाई नेटवर्क क्षेत्र में होना जरूरी है।

डाटा ट्रांसफर करने के काम भी आती है यूएसबी केबल। प्रतीकात्मक

हैकर चाहे तो उस डिवाइस में नकली केबल के इस्तेमाल किए जाने की जानकारी भी मिटा सकता है। इस केबल के जरिये कंप्यूटर या स्मार्टफोन की स्क्रीन को लॉक कर उसका पासवर्ड भी पता किया जा सकता है। एमजी ने एपल की केबल में ही कुछ बदलाव कर इस नकली केबल को तैयार किया है। उसका कहना है कि इस केबल को अन्य यूएसबी पोर्टल के लिए भी बनाया जा सकता है। हालांकि वह इस केबल को सिक्योरिटी टूल की तरह इस्तेमाल में लाना चाहता है।

डीएसएलआर कैमरों में भी हो सकता है मॉलवेयर अटैक

▶ **कैमरों को वाई-फाई और यूएसबी के जरिये इंटरनेट से कनेक्ट करने से हो सकता है नुकसान**

नई दिल्ली, आइएएनएस : कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बाद अब हैकर्स की नजर आपके कैमरों पर भी है। सुरक्षा शोधककर्ता ने चेतावनी दी है कि डीएसएलआर कैमरों पर भी रैनसमवेयर या मॉलवेयर (एक तरह का वायरस) हमले हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि आधुनिक कैमरे यूएसबी और वाई फाई से जुड़े होते हैं, ऐसे में हैकर्स उनके डेटा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता इयाल इटकिन ने बताया कि कोई भी स्मार्ट डिवाइस, जिसमें डीएसएलआर कैमरे भी शामिल हैं, हैकरों के हमले के लिए संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे अब केवल यूएसबी से ही नहीं, बल्कि वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट हो रहे हैं। जिसके कारण यह अब हैकरों की जद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कैमरे पर वायरस से हमला किया जाता है तो उसकी तस्वीरों को हैकर डाउनलोड कर बदले में फिरौती की मांग सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि आधुनिक कैमरों में तस्वीरें फिल्म पर नहीं उतारी जाती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय इमेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक मानक प्रोटोकॉल बनाया है, जिसे पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल (पीटीपी) नाम दिया गया है, इसी के माध्यम से कैमरे से तस्वीरें पीसी पर ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अब हो सकता है कि तस्वीरें ट्रांसफर करने के दौरान ही हैकर आपकी तस्वीरें चोरी कर लें। शोधकर्ताओं का कहना है कि कैमरों को हैकरों की पहुंच से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे कैमरे को अपडेट करते रहें। इसके अलावा जब इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो तो कैमरे को बंद कर दें।

खून की जांच के लिए बनाई नई किफायती डिवाइस

स्पेक्ट्रम

▶ **आइआइटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने की विकसित**

कोलकाता, प्रेट्र : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सस्ती डिवाइस विकसित की है, जिसकी मदद से खून के नमूने लेकर विभिन्न रोगों का परीक्षण किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस डिवाइस को एक पेपर स्ट्रिप आधारित किट की आवश्यकता होती है, जिसे स्मार्टफोन के साथ जोड़कर नमूनों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही एलईडी लाइट के जरिए इसकी इमेजिंग की जाती है।

आइआइटी खगड़पुर के प्रोफेसर और शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाल सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि इस किट की सबसे बड़ी बात यही है कि इसे प्रयोग करना बहुत ही आसान है। साथ ही इसका खर्चा भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि इसे चलाने के लिए केवल एक बूंद रक्त और रासायनिक क्रिया के लिए एक बूंद रीजेंट की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा अन्य पोर्टेबल उपकरणों की तुलना में इस डिवाइस के जरिये हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत भी नहीं है। रोगी स्वयं भी आसानी से अपने खून की जांच कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक

उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में जहां परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं, वहां इस उपकरण की मदद से ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आइआइटी खड़गपुर के मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल प्रोफेसर डॉ. सतादल साहा ने कहा कि इस डिवाइस का हमने सभी तरह के वातारण में परीक्षण किया है, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया में 80 फीसद लोग काम के दौरान हो जाते हैं बीमार

▶ **एसीटीयू के सर्वेक्षण में सामने आई बात, काम पर हिंसा, प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं कई लोग**

कैनबरा, आइएएनएस : असुरक्षित माहौल के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक पांच में चार कामकाजी लोग घायल हो जाते हैं और इसके कारण बीमार भी हो रहे हैं या फिर दर्दनाक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक नए सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है।

समाचार एजेंसी शिंहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक 'वर्क शुड नॉट हर्ट' नामक इस सर्वेक्षण को ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एसीटीयू) ने सोमवार को जारी किया था, जिसमें 26 हजार कामगारों को शामिल किया गया था। इसके मुताबिक लगभग 80 फीसद कामकाजी लोग अपने काम के कारण घायल, बीमार या दोनों हो रहे हैं, जबकि16 फीसद लोग किसी ऐसे आदमी को जानते थे, जिसकी काम के दौरान मौत हो गई, या फिर काम से जुड़ी बीमारियों के कारण मौत हो गई। इसमें यह भी पाया गया कि 47 फीसद प्रतिभागियों ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्हें काम के दौरान दर्दनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा और 31 फीसद लोगों ने कहा कि उन्हें सहकर्मियों या ग्राहकों द्वारा धमकी दी गई या मारपीट की गई। पांच में से तीन कामगारों ने कहा कि पिछले 12 महीनों से वे खराब मानसिक स्वास्थ्य का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका नियोक्ता (काम देने वाला) असुरक्षित कामकाजी स्थितियों को सुधारने में असफल है।

एसीटीयू के सहायक सचिव लियाम ओब्रायन ने बताया कि लोगों को चोट लगने या मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की घटनाओं से बचा जा सकता है। 'वर्क शुड नॉट हर्ट' के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत सारे कामकाजी लोग काम पर हिंसा, प्रताड़ना और खराब कामकाजी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जबकि इसमें से ज्यादातर को रोका जा सकता है।

शोध अनुसंधान

धूमपान के अन्य तरीकों से ज्यादा खतरनाक है हुक्का

हाल के वर्षों में हुक्का की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक चौंकाने वाला शोध सामने आया है। शोध के मुताबिक, हुक्का पीना धूमपान के अन्य तरीकों की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता वेरोनिक पेरॉड ने कहा कि हुक्का पीने से शरीर में निकोटिन पहुंचता है, जो तंबाकू की लत का कारण बन सकता है। इसमें बेंजीन भी पैदा होती है, जो कैंसर का कारण बन सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि आमतौर पर लोग हुक्का ज्यादा देर तक पीते हैं, इस कारण से शरीर में पहुंचने वाले खतरनाक रसायनों की मात्रा भी ज्यादा होती है। हुक्का में तंबाकू को गरम करने के लिए कोयला जलाने से कार्बन मोनो ऑक्साइड भी पैदा होती है। सांस के रास्ते कार्बन मोनो ऑक्साइड शरीर में जाने से नुकसान और बढ़ जाता है। शोध में धुएं के जरिये शरीर में पहुंचने वाले 100 नैनोमीटर से भी छोटे सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया गया। - आइएएनएस

वैज्ञानिकों ने दांतों के इलाज का नया तरीका खोजा

वैज्ञानिकों ने दांतों की मरम्मत का नया तरीका खोजा है। विज्ञान पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में इसकी जानकारी दी गई है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित किए जा रहे चूहे के नुकीले दांतों में विशेष कोशिकाओं की पहचान की है। ये कोशिकाएं ऊतकों (टिश्यू) में पाई जाती हैं। दांतों को बाहर से ढंक कर रखने वाली कठोर परत डेंटिन के निर्माण में इन कोशिकाओं की भूमिका देखी गई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे ही ये कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, इनसे ऊतकों की मूल कोशिका को संकेत मिलता है और नई कोशिकाओं का उत्पादन नियंत्रित होता है। इसी शोध में यह भी देखा गया कि एक जीन इन कोशिकाओं को सक्रिय करके घाव वाली जगह पर ऊतकों के पुनर्निर्माण को गति दे सकता है। इस प्रक्रिया के जरिये दांतों की मरम्मत का नया तरीका ईजाद करना संभव हो सकता है। - एएनआइ

दीवारें बेधकर घर में पहुंचेगी रोशनी

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

आविष्कार

▶ **एचबीटीयू के छात्र ने बनाई पारदर्शी कंक्रीट, 30 फीसद होगी बिजली की बचत**

▶ **लोहे के कचरे और फाइबर से बनी कंक्रीट की लागत 26 फीसद**

▶ **कार्बन डाई आक्साइड न होने से 15 फीसद है हल्की**

अब पारदर्शी दीवारों से छनकर सूरज की किरणें घर के भीतर पहुंचेगी। इससे दिन में भी बिना बिजली कमरों में भरपूर रोशनी होगी। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से एमटेक छात्र रामांश वाजपेयी ने लोहे के कचरे और प्लास्टिक फाइबर को मिलाकर ऐसी 'ट्रांसपैरेंट कंक्रीट' बनाई, जो सूर्य की किरणों को पार जाने देगी। इससे बनी दीवार से छनकर केवल रोशनी जाएगी पर गर्मी नहीं। दीवार अंदर से नहीं तपेगी। इससे बिजली की खपत 30 फीसद घटेगी।

कार्बन डाई ऑक्साइड मुक्त होने के साथ यह पारदर्शी कंक्रीट साधारण कंक्रीट के मुकाबले 15 फीसद हल्की, 23 फीसद अधिक मजबूत होगी जबकि लागत मौजूदा दीवार के मुकाबले महज 33 फीसद होगी। इसमें उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर सस्ते व टिकाऊ होने के साथ ही सूरज की रोशनी को आर-पार करने की क्षमता रखते हैं। इस कंक्रीट में ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लेग (जीजीबीएस) व प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) होने के कारण यह साधारण कंक्रीट की अपेक्षा 15 फीसद हल्की है।

सूरज से आती 30 फीसद रोशनी : डॉ. दीपेश कुमार सिंह के निर्देशन में इस कंक्रीट को तैयार करने वाले छात्र रामांश ने बताया कि इसके जरिए सूरज की 30 फीसद रोशनी घर के अंदर पहुंचेगी। यह साधारण कंक्रीट से 23 फीसद अधिक मजबूत है। उन्होंने ट्रांसपैरेंट कंक्रीट बनाने के लिए 40 फीसद जीजीबीएस का उपयोग कर पाया कि इसका इस्तेमाल करने से साधारण कंक्रीट के मुकाबले महज 33 फीसद लागत रह जाती है। जीजीबीएस से बनी (3 गुणा 3 गुणा 0.1125 घन मीटर) ट्रांसपैरेंट कंक्रीट की लागत करीब 1924 रुपये आई, वहीं ईंट की इसी आयतन की दीवार की लागत 5800 रुपये आती है।

क्या होता है जीजीबीएस : रामांश ने बताया कि लोहे व स्टील उद्योग के कचरे को जीजीबीएस कहते हैं। इससे चूरे में बदलकर पारदर्शी कंक्रीट बनाई जा सकती है। इससे रोशनी तो आएगी लेकिन हवा और पानी नहीं। इसमें सीलन का भी खतरा नहीं होगा।

क्या होगा फायदा: शोधकर्ता रामांश ने बताया कि आज पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इस तकनीक से बिजली की खपत को कम की ही जा सकेगी। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

फास्ट फूड की दुकानों वाले क्षेत्रों में बढ़े हार्ट अटैक के मामले : शोध

सिडनी, आइएएनएस : यह तो सभी जानते हैं कि ज्यादा फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन इलाकों में फास्ट फूड की दुकानें ज्यादा हैं, वहां लोगों में हार्ट अटैक के मामले भी ज्यादा पाए गए हैं।

यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि एक फास्ट फूड की दुकान से हर साल दस लाख लोगों में चार लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। शोधकर्ताओं ने कहा कि फास्ट फूड की दुकानें जिन क्षेत्रों में ज्यादा थीं वहां के लोगों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी शिकायतें भी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की तरुणप्रीत सलूजा ने कहा कि अध्ययन के परिणाम इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग रहने की जरूरत है। इस अध्ययन में 2011 से 2013 के बीच अस्पताल में भर्ती किए गए हार्ट के 3,070 मरीजों को शामिल किया गया था।

पारंपरिकता का आकर्षण

मौजूदा दौर में आधुनिक खानपान और रहन-सहन का प्रभुत्व भले हो लेकिन लोगों में पारंपरिकता के प्रति लगाव भी बरकरार है। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। जिसमें मॉडल्स ने पारंपरिक पहनावे में अनूठी रंगत बिखेरी। इंडोनेशिया में 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एएफपी

जर्मनी में पर्यटकों के लिए बनाई 'डायनासोर सिटी'...

जर्मनी के बोचूम शहर का सिटी सेंटर इन दिनों 'डायनासोर सिटी' के रूप में जाना जाता है। दरअसल पर्यटकों को लुभाने के अभियान के तहत सिटी सेंटर में डायनासोर की 33 कलाकृतियां लगाई गई हैं। यह कलाकृतियां इतनी जीवंत हैं कि हर आगंतुक का मन मोह लेती हैं। बोचुम में 2012 में अरबों साल पुराना डायनासोर ट्रैक मिला था। एपी

स्क्रीन शॉट

शूटिंग के दौरान नितेश-अश्विनी ने ऐसे रखा बच्चों का खयाल

हिंदी सिनेमा में नितेश तिवारी 'चिल्लर पार्टी', 'भूतनाथ रिटर्न्स', 'दंगल' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी अश्विनी अय्यर तिवारी 'निल बटे सन्नाटा' और 'बरेली की बरफी' जैसी सौगात दे चुकी हैं। खास बात यह है कि छह सिंतबर को नितेश की फिल्म 'छिछोरे' रिलीज हो रही है। उसमें सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर अहम भूमिका में हैं। वहीं अश्विनी की कंगना रनोट अभिनीत फिल्म 'पंगा' अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। नितेश ने ही अश्विनी की फिल्मों की कहानी लिखी थी। वह खुद तो फिल्में बनाते ही हैं, पत्नी को भी प्रोत्साहित करते हैं। नितेश और अश्विनी के जुड़वां बच्चे हैं। अश्विनी ने अपनी फिल्म की शूटिंग ज्यादातर भोपाल में की है, जबकि नितेश ने मुंबई में। फिल्मों की शूटिंग के साथ बच्चों की देखभाल को लेकर नितेश का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई में की है। इसलिए कोई प्रेशर नहीं था कि बच्चों को कौन देखेगा। एक शहर में रहने से दूरी ज्यादा नहीं होती। वैसे भी अगर उन दोनों में कोई एक भी बच्चों के आसपास साथ रहता है तो वे खुश रहते हैं। शूटिंग के दौरान वह रात में घर पर आ जाते थे। बच्चे उससे खुश हो जाते थे। वैसे बच्चे आत्मनिर्भर हैं। उनकी परवरिश ऐसी रही है कि वह बहुत डिमांडिग नहीं हैं। लिहाजा तालमेल बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आई। वाकई नितेश से बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है।

मी टू के आरोपितों साथ काम करने पर बोलीं रिचा चड्ढा

मी टू अभियान के तहत कई कलाकारों ने आरोपित लोगों के साथ काम करने से इन्कार किया है। दीपिका पादुकोण, मेघना गुलजार, अक्षय कुमार, अजय देवगन उस फेहरिस्त का हिस्सा हैं। मंगलवार को मुंबई में फिल्म 'सेक्शन 375' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आरोपित लोगों के साथ काम करने के सवाल पर निर्देशक अजय बहल ने कमान संभालते हुए उल्टा सवाल दागा कि अगर किसी संस्था में बॉस पर आरोप लगे तो क्या लोग नौकरी करना छोड़ देंगे? संस्थान में काम नहीं करेंगे? इस पर एक मीडियाकर्मी ने जवाब दिया- कारपोरेट सेक्टर में ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस पर रिचा ने सवाल उठाया कि मीडिया क्यों उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है? उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहराया जाता, मीडिया या ट्विटर पर ट्रायल अलग बात है। मैं उनकी बात कर रही हूं, जहां एक-दो आरोप लगे हैं। यह सोशल समस्या है। इस पर बात करनी होगी। उस मामले पर कैसे संबोधित करें, यह बहुत जटिल मामला है।

फिर दिखेगा काजोल और अजय का रोमांस

बॉलीवुड में 'सिंघम' के नाम से लोकप्रिय अभिनेता अजय देवगन आजकल फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त हैं। फिलहाल वह गुजरात में 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया' की शूटिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर वह फिल्म 'तानाजीः द अनसंग वॉरियर' में अपनी पत्नी और अभिनेत्री काजोल के साथ लंबे समय बाद साथ नजर आएंगे। अजय और काजोल की रोमांटिक जोड़ी एक समय बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय हुई थी। ऐसे में खबर आई है कि यह कपल एक और फिल्म में रोमांटिक जोड़े के रूप में नजर आएगा। इस फिल्म का नाम है, 'यू मी और हम'। हालांकि देवगन के प्रोडक्शन हाउस ने तीन और शीर्षक रजिस्टर किए हैं। एक सूत्र ने जानकारी दी, 'पिछले सप्ताह जब काजोल का जन्मदिन था, तभी इस बारे में विचार किया गया। अपने जन्मदिन पर काजोल अजय से मिलने भुज गई थीं। उसी दौरान इस तरह की योजना बनी थी।' बहरहाल इस फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े पर आधारित होगी, जिसमें उनका रोमांस भी फोकस में होगा। अजय देवगन के प्रोडक्शन ने तीन शीर्षक रजिस्टर किए हैं, 'रोमांस और क्या', 'धोखा अराउंड द कॉर्नर' और 'धोखा।' खबर है कि अजय और काजोल दोनों फिल्म में शीर्ष भूमिका निभाने को उत्सुक हैं। हालांकि यह निर्णय नहीं लिया गया है कि फिल्म का निर्देशन अजय ही करेंगे या कोई और। फिल्म की स्क्रिप्ट अभी अंतिम दौर में हैं और उसके बाद ही यह कपल फाइनल कहानी सुनेगा। सूत्र के अनुसार, अगर सबकुछ योजना के अनुसार चला, तो फिल्म अगले साल मध्य तक फ्लोर पर आ जाएगी।

'सेक्रेड गेम्स 2' में डबल रोल में नजर आएंगी एलनाज

वेब सीरीज की दुनिया में 'सेक्रेड गेम्स' काफी लोकप्रिय है। इसकी बड़ी वजह सैफ अली खान का होना नहीं, बल्कि इसका दमदार कंटेंट है। अब इसका दूसरा भाग रिलीज होने को तैयार है। बहरहाल अभिनेत्री एलनाज नौरोजी भी 'सेक्रेड गेम्स 2' में महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगी। एलनाज इस सीरीज में दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। इस रोल के बारे में अभिनेत्री ने कहा, 'दो अलग-अलग किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं इसमें जमीला का किरदार निभा रही हूं, जो कमजोर और भोली है और उसके बाद जोया बन जाती हूं, जो शक्तिशाली और जोड़-तोड़ करने वाली है। यह अनुभव मुझे अच्छी अभिनेत्री बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। साथ ही मैं इसके तीसरे सीजन में भी नजर आऊंगी।' गौरतलब है कि ईरानी मूल की एलनाज पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री हैं और फिल्म 'खिडो खुंडी' से उन्होंने पंजाबी फिल्म में डेब्यू किया था।

किया आगाह

विशेषज्ञों ने कहा कि सिर्फ टीडीएस को पानी की गुणवत्ता का मापदंड मानकर आरओ खरीदना सही नहीं, पानी की भी होती है बर्बादी

सोच-समझकर करें आरओ का इस्तेमाल

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ वाटर प्यूरीफायर की जरूरत के बारे में पड़ताल किए बिना जल शोधन के लिए इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। अधिक मात्रा में पानी में घुले खनिजों (टीडीएस) की मात्रा का डर दिखाकर कंपनियां और डीलर्स धड़ल्ले से आरओ प्यूरीफायर बेच रहे हैं। जल शोधन की तकनीकों पर केंद्रित शोध एवं विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया कि आरओ का विकास ऐसे क्षेत्रों के लिए किया गया है, जहां पानी में घुले खनिजों (टीडीएस) की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। इसलिए, सिर्फ टीडीएस को पानी की गुणवत्ता का मापदंड मानकर आरओ खरीदना सही नहीं है।

इंडिया वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से जुड़े विशेषज्ञ वी.ए. राजू ने बताया कि पानी की गुणवत्ता कई जैविक और अजैविक मापदंडों से मिलकर निर्धारित होती है। टीडीएस पानी की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले 68 मापदंडों में से सिर्फ एक मापदंड है। पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले जैविक तत्वों में कई प्रकार के बैक्टीरिया तथा वायरस हो सकते हैं। वहीं, अजैविक तत्वों में क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, जिंक, शीशा, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फेट, नाइट्रेट जैसे खनिजों के साथ-साथ पानी का खारापन, पीएच मान, गंध, स्वाद और रंग जैसे गुण शामिल हैं।

कई जैविक और अजैविक मापदंडों से मिलकर निर्धारित होती है पानी की गुणवत्ता। प्रतीकात्मक

कहां लगाया जा सकता है आरओ : नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के वैज्ञानिक डॉ. पवन लभसेत्वार ने बताया कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा खारा नहीं है, वहां रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) की जरूरत नहीं है। जिन जगहों पर पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स (टीडीएस) की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है। आरओ का उपयोग अनावश्यक रूप से करने पर सेहत के लिए जरूरी कई महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी पानी से अलग हो जाते हैं। इसीलिए, पानी को साफ करने के लिए सही तकनीक का चयन करने से पहले यह निर्धारित करना जरूरी है कि आपके इलाके में पानी की गुणवत्ता कैसी है।

एनजीटी ने भी जताई थी चिंता : कुछ समय पूर्व आरओ के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार से इस पर नीति बनाने के लिए कहा है। एनजीटी ने कहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ऐसे स्थानों पर आरओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है, जहां पीने के पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है।

70 फीसद पानी हो जाता है बर्बाद : आरओ के उपयोग से करीब 70 प्रतिशत पानी बह जाता है और सिर्फ 30 प्रतिशत पीने के लिए मिलता है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि 60 फीसदी से ज्यादा पानी देने वाले आरओ सिस्टम को ही मंजूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रस्तावित नीति में आरओ से 75 फीसदी पानी मिलने और रिजेक्ट पानी का उपयोग बर्तनों की धुलाई, फ्लशिंग, बागवानी, गाड़ियों और फर्श की धुलाई आदि में करने का प्रावधान होना चाहिए।